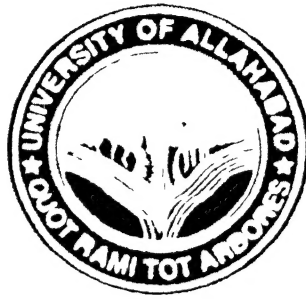


# भारत के लोक उद्यमों में जगता एवं चर्रीय प्रबन्ध (जनपद इलाहाबाद विशेष के सन्दर्भ में)



इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत  
शोध - प्रबन्ध

शोध निर्देशक

रीडर

डॉ० ए० के० मुखर्जी

वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

शोधकर्ता

शीतला प्रसाद श्रीवास्तव

पी०जी०टी० कॉमर्स  
केन्द्रीय विद्यालय पवई  
मुम्बई

वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2002

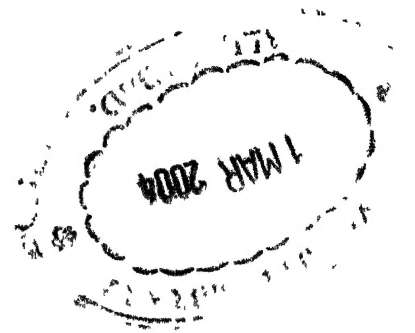
# प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे शोध निर्देशन में **श्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव** ने डी० फिल् उपाधि हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध विषय “**भारत के लोक उद्यमों में रुग्णता एवं चक्रीय प्रबन्ध (इलाहाबाद विशेष के सन्दर्भ में)**” पर अपना मौलिक शोध ग्रन्थ प्रस्तुत किया है। जो कि न तो कही प्रकाशित हुआ है और न ही प्रकाशन हेतु कही भेजा गया है।

**शोध-निर्देशक**

(डॉ० अश्लीम कुमार मुखर्जी)

रीडर, वाणिज्य एवं  
व्यवसाय प्रशासन विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद



वर्तमान निरन्तर परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में किसी देश के लोक उद्यम की समस्या का गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे विश्लेषणात्मक अध्ययन से प्राप्त बहुमूल्य जानकारीयों किसी देश की वर्तमान प्रमुख लोक उद्यमों की समस्याओं के अभिव्यक्तिकरण में अत्यन्त उपयोगी है। इसके अतिरिक्त किसी अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड के आधार पर उपयुक्त औद्योगीकरण के स्तर को प्राप्त करने और अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तीव्रता के वरीयता क्रम में आवश्यक सन्तुलित लोक उद्यम का विकास करने में व्यावहारिक दृष्टि से शामिल अग्रिम लोक उद्यमों के बारे में नियोजन करने और उनके व्यवहार में अपनाने एवं उनके सामयिक मूल्यांकन करने में इन जानकारीयों का बहुमूल्य उपयोग हो सकता है। अतः भारतीय लोक उद्यम प्रबन्ध समस्याओं एवं उनके चक्रीय प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्लेषणात्मक अध्ययन करने हेतु मैंने शोध कार्य का संकल्प लिया और इस शोध कार्य के माध्यम से मैंने यह प्रयास किया है कि इस विषय पर शोध-ग्रन्थ प्रस्तुत करूँ जो कि केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विशेषज्ञ, शोधकर्ताओं और शोध विषयक अभिरूचियों को उनके व्यावसायिक परीक्षण में बहुमूल्य सिद्ध हो और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में भारतीय हितों को पूरा करने के क्षेत्र में भी उपयोगी हो। इस प्रस्तुत किये गये शोध-ग्रन्थ में शोध विषयक विवेचन के क्षेत्र में यथासंभव सरलतम भाषा एवं शैली का प्रयोग किया, ताकि शोध विषय को आसानी से समझा जा सके और उसका उपयोग राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में आवश्यक सामयिक लोक उद्यम के समस्या व समाधान के लिए प्रयोग किया जा सके मेरी यही अपेक्षा है कि इस क्षेत्र में प्रस्तुत किये गये शोध ग्रन्थ में शोध विषय का विश्लेषणात्मक विवेचन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

## आभारोक्ति

प्रस्तुत किये गये शोध-ग्रन्थ के सफल अभिलेखन और अपने शोध-कार्य के परिक्षेत्र में मैं अपने आदरणीय शोध-निर्देशक श्री डॉ० ए० के० मुखर्जी रीडर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वाणिज्य सकाय के प्रति हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने अपने वृहद शोधात्मक अनुभवों से मुझको शोध विषयक अभिज्ञान प्रदान करने में अपना बहुमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान किया। मैंने अपने इस शोध-ग्रन्थ में उनके शोध विषयक मौलिक विचारों को अभिव्यक्त किया है, जिनके आधार पर शोध-विषय का वृहद विश्लेषणात्मक विवेचन किया जाना सम्भव हो सका है। शोध विषयक ऐसे विश्लेषणात्मक अध्ययन में पर्याप्त विषय सामग्री के अभाव में सफल शोध-कार्य में अभिप्रेरणा का मुख्य श्रेय उन्हीं को है। उनके सतत सहयोग के फलस्वरूप दुर्लभ शोध विषयक अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सकी, जिसका उपयोग करके शोध-कार्य पूर्ण किया जा सका और शोध-ग्रन्थ अभिलेखन करके उनको प्रस्तुत किया जा सका, इसके लिए मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगा।

मैं विशेष रूप से अपने आदरणीय गुरुजन प्रो० के० एम० शर्मा व एच० के० सिंह के प्रति हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझको इस शोध कार्य में अपना बहुमूल्य समय और आत्मीयतापूर्ण सहयोग प्रदान किया। उनके इस सहयोग के फलस्वरूप मैं अपने शोध-कार्य में सफल हो सका, और इस शोध-ग्रन्थ को प्रस्तुत कर सका। मेरी आशा है कि यह शोध-ग्रन्थ सभी पाठकगणों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

शीतला-प्रसाद

Srivastava

शीतला प्रसाद श्रीवास्तव

पी० जी० टी० कॉमर्स

(केन्द्रीय विद्यालय, पवई, मुम्बई)



## अनुक्रमणिका

क्र० सं०	अध्याय	पृ० सं०
	प्राक्कथन	I-II
1.	लोक उद्यम का अर्थ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य व विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विकास	1-25
2.	लोक उद्यमों का विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत विकास	26-50
3.	भारत में लोक उद्यमों का विकासात्मक अध्ययन	51-71
4.	भारत के लोक उद्यमों में रूग्णता की वर्तमान स्थिति व रूग्णता के कारण	72-95
5.	भारत के लोक उद्यमों में रूग्णता का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन— जनपद इलाहाबाद विशेष के सन्दर्भ में	96-139
6.	रूग्णता के निराकरण के लिए चक्रीय प्रबन्ध	140-164
7.	प्रमुख निष्कर्ष एवं सुझाव	165-192

## *प्रथम अध्याय*

लोक उद्यम का अर्थ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य व  
विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विकास

## *प्रस्तावना*

लोक उद्यम किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसी भी देश के लिए आधार स्तम्भ का कार्य करता है। भारत देश के त्वरित आर्थिक विकास में लोक उद्यमों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार, क्षेत्रीय असमानता में कमी, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, राजकोष में अंशदान, विदेशी मुद्रा अर्जन के क्षेत्र में भारतीय लोक उद्यमों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। बिना लोक उद्यमों की उन्नति के कोई भी देश सम्पन्नता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच नहीं सकता। विश्व के सभी विकसित देश लोक उद्यमों के बल पर ही विकास की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। भारत भी इन उद्योगों के आधार पर ही विकास की ओर अग्रसर है।

लोक उद्यम भारत के चतुर्दिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, देश के प्राकृतिक ससाधनों का पूर्ण उपयोग, आदि के क्षेत्र में लोक उद्यमों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। वर्तमान में भारत के लोक उद्यमों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है भारत के उन्नति में लोक उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के संविधान में समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर तथा समाज को उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों के शोषण से बचाने के लिए ही लोक उद्यमों की स्थापना की गयी। जिससे उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके तथा देश के तीव्र विकास में लोक उद्यम महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप प्राचीन काल से ही रहा है, परन्तु अधिकांश आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों तथा

व्यवसायियों के हाथों में सकेन्द्रित होने के कारण राजकीय हस्तक्षेप सीमित था परन्तु अब स्थिति बदल गई है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का स्वरूप दिन-प्रतिदिन बदलने व बढ़ने लगा है और यह एक प्रकार से सरकारी प्रबन्ध तन्त्र का एक आवश्यक अंग बन गया है। अब आर्थिक एवं व्यवसायिक क्रियाकलापों में राज्य का हस्तक्षेप एक आर्थिक अभिशाप अथवा राजकीय निषेधता नहीं रह गया है। अब आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने समग्र समाज के हितों की रक्षा एवं कल्याण करने आर्थिक विकास प्रक्रिया में तीव्रता लाने तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की दृष्टि से व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।

इस प्रकार राज्य ने प्रायः सभी औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं में प्रवेश करने का प्रयास किया है। लोक उद्योगों ने देश में तीव्र औद्योगिक विकास, कृषि यातायात, सवादवाहन के लिए आर्थिक संरचना के निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

1948 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। 1956 की औद्योगिक नीति में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने की बात की गयी। इन दोनों ही औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत एक बड़ा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया जिसमें सुरक्षा सम्बन्धी और मूल उद्योग शामिल किये गये। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन वाले क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। सरकार की इस नीति के पीछे महत्वपूर्ण कारण थे। देश के औद्योगिक विकास के लिए जिन आधारभूत एवं पूँजीगत उद्योगों की शीघ्र स्थापना की आवश्यकता थी, उन्हें स्थापित करने की निजी क्षेत्र की न क्षमता थी और न ही इच्छा। क्षमता इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके साधन सीमित थे और इच्छा इसलिए नहीं थी क्योंकि इन

उद्योगों की लाभप्रदता अपेक्षाकृत बहुत कम थी। दूसरा कारण यह भी था कि इस प्रकार के उद्योगों में स्वायत्त निवेश की आवश्यकता होती है और यह निवेश राज्य द्वारा ही संभव है, अतः इन्हें सार्वजनिक हित में रखा गया।

1948 व 1956 की औद्योगिक नीति के आधार पर विभिन्न योजनाओं में क्षेत्र की भूमिका के अनुरूप ही सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किया गया। पहली और दूसरी योजना में कुल निवेश का 54 प्रतिशत, तीसरी योजना में 60 प्रतिशत, चौथी योजना में 59 प्रतिशत, पांचवी योजना में 57.6 प्रतिशत और छठी योजना में 53 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किया गया। 1980 की औद्योगिक नीति के बाद उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार हुआ जिसके परिणामस्वरूप सातवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश में हिस्सा 47.8 प्रतिशत रह गया। 1991 की नई औद्योगिक नीति में व्यापक स्तर पर उदारीकरण के प्रभाव स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और सीमित कर दी गयी और आठवी योजना के कुल निवेश का केवल 45.2 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किया गया। नौवी योजना के प्रारूप के अनुसार इसे काफी कम करके कुल निवेश का केवल 33 प्रतिशत कर दिया गया है।

### लोक उद्यमों का आशय :-

सरकार के स्वामित्व व नियन्त्रण के अधीन आने वाली सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयां लोक उद्यम कहलाती हैं।

प्रो० ए० एच० हैन्सन के अनुसार "लोक उद्यम का आशय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक कृषि वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थाओं से है।"<sup>1</sup>

प्रो० एस० एस० खेरा के शब्दों में "लोक उद्योग से तात्पर्य सरकारी स्वामित्व में स्थापित एवं नियंत्रित ऐसी स्वशासित अथवा अर्द्धस्वशासित निगमों एवं कंपनियों से है जो औद्योगिक और वाणिज्यिक क्रियाओं में लगी हों।"<sup>2</sup>

(1) हैन्सन ए० एच०, पब्लिक इण्टरप्राइज एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट, लण्डन राउटलेज एण्ड कींगन पाल लिमिटेड, 1972, पेज नं० 3

(2) खेरा एस० एस०, गवर्नमेंट इन बिजनेस, नेशनल पब्लिशिंग हाउस न्यू देलही, 1977 पेज नं० 4

लोक उद्यम को ब्रिटेन में पब्लिक कारपोरेशन, कनाडा में क्राउन कारपोरेशन, आस्ट्रेलिया में सवैधानिक निगम, राज्य अमेरिका में इन्हे सरकारी निगम के नाम से संबोधित किया जाता है। फ्रांस में सरकार के औद्योगिक उपक्रम व इटली में सार्वजनिक निगमों, नगर पालिकाओं तथा स्वायत्तशासी सरकारी विभाग से लिया गया है।

प्राचीन समय में व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वतंत्रता की प्रधानता थी। प्रत्येक पूंजीवादी देश में आर्थिक गतिविधियों का संगठन एवं संचालन निजी क्षेत्र के अन्तर्गत होता था। अहस्तक्षेप की नीति अथवा स्वतन्त्र व्यापार की नीति का प्रचलन था। इस नीति के अनुसार उपभोक्ता एवं व्यापारी किसी भी यात्रा एवं मूल्य पर वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने के लिए स्वतन्त्र थे तथा राज्य का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते थे। उस समय सरकारी हस्तक्षेप केवल आन्तरिक शान्ति बनाने, बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने तथा लोकोपयोगी सेवाओं तथा कार्यों तक ही सीमित था। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप के लिए कुछ अनुकूल वातावरण बनना प्रारम्भ हुआ। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही इस विचारधारा को पर्याप्त आधार प्राप्त हो गया कि किसी देश के आर्थिक जीवन में सरकार का सहयोग एवं सक्रिय भूमिका आवश्यक है।

### **प्राचीन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र :-**

आर्थिक क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन काल स्मरणीय है। ईसा से 300 वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भी सरकार व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं में सक्रिय भाग लेती थी। चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य में उद्योगों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों के अध्यक्ष नियुक्त किये जाते थे, जैसे लोहाध्यक्ष, अंकराध्यक्ष, खानों का अधिकारी, लवणाध्यक्ष (नमक का अधिकारी) आदि।

(1) महाभारत का कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस बात का पर्याप्त विवेचन उपलब्ध है कि प्राचीन भारत में मानव जीवन के समस्त सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक पहलुओं से राज्य की क्रियाओं का किसी न किसी रूप में सम्बन्ध अवश्य था। उस समय के आर्थिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप दो रूप में होता था। प्रथम उद्योगों को सरकारी सहायता तथा दूसरे सरकार द्वारा व्यवसाय एवं उद्योगों का नियमन किया जाना। गौतम बुद्ध के काल में मूल्यों का नियमन सहकारिता के रूप में होता था जिस पर भारत समाज आधारित था। लोकोपयोगी सेवाओं एवं कार्यों में सरकार के हस्तक्षेप की अनुमति उपलब्ध थी। इस प्रकार प्राचीन भारत में समाज के सम्पूर्ण आर्थिक जीवन के प्रबंध एवं नियमन में राज्य निकटता से सहयोग करता था।

### **मध्यकालीन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र :-**

भारत का मध्यकाल मुगलशासन से संबन्धित है इस काल में राजा उद्योगों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करता था। इस अवधि में आगरा, लाहौर, फतेहपुर एवं अहमदाबाद में अनेक सरकारी उद्योग स्थापित हुये। इस काल में सार्वजनिक उद्योगों में निम्न लक्षण थे :-

(1) निजी उद्योगपतियों द्वारा भी कारखाने संचालित किये जाते थे। लेकिन निजी क्षेत्र के कारखाने किसी भी प्रकार से शाही कारखानों के आकार व्यवस्था तथा उपकरण की दृष्टि से बराबरी नहीं कर पाते थे।

(2) इस अवधि में स्थापित राजकीय उद्योगों में प्रमुख रूप से रेशम एवं सन उद्योग धातु एवं खनिज उद्योग आदि थे।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कोर्स पर नियन्त्रण हेतु खान-ए-सामान नामक मन्त्री की नियुक्ति की जाती थी।

(4) सभी उपक्रमों के सम्बन्धों में अलग-2 निदेशकों की नियुक्ति की जाती थी। ये निदेशक मन्त्रियों तथा अन्तिम रूप से राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे।

## **भारत में आधुनिक लोक उद्योगों का विकास**

इसका अध्ययन दो भागों में किया जा सकता है।

### **(अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व विकास :-**

इस समय ब्रिटिश शासन था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उतना ही विकसित होने दिया जितना उनकी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था। 1600 ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के पश्चात् से 1757 ई० तक भारत का कम्पनी के साथ व्यापार लाभकारी रहा, क्योंकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी बहुमूल्य धातुओं के बदले में यहाँ बने कपड़े तथा मसाले खरीदती थी। भारतीय वस्त्रों की इंग्लैण्ड तथा अन्य यूरोपीय देशों में भारी मांग थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपड़ों के ब्रिटेन में प्रवेश पर भारी आयात शुल्क और जुर्माना लगाने का निर्णय लिया, जिसके बावजूद भारत में बने रेशमी व सूती वस्त्र 18 वीं शताब्दी के मध्य तक विदेशी बाजारों में जमे रहे।

1857 के प्लासी के युद्ध के पश्चात् भारतीय उद्योगों का विकास तीव्र गति से होने लगा।

इस प्रकार भारत में ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल उत्पादित करने तथा उनमें बनी हुई वस्तुओं को विक्रय करने के लिए एक विस्तृत बाजार बनाने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया, लेकिन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिनसे बाध्य होकर सरकार को सन् 1830 में गणितीय संयंत्र कार्यालय की स्थापना करनी पड़ी जिसे वर्तमान समय में संयंत्र कारखाना के नाम से जाना जाता है इसके पश्चात्



सन 1835 में डाक व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया तथा सन् 1839 में प्रथम प्रायोगिक टेलीग्राफ लाइन का निर्माण किया गया। लोक उद्योगों की वर्तमान संरचना में महत्वपूर्ण रेल उद्योग का प्रारम्भ भी इसी समय सन् 1839 में किया गया। सन् 1888 में मैसूर राज्य में सरकार द्वारा स्थापित सूती वस्त्र उद्योग की महबूबशाही गुलबर्गा मिल्स कम्पनी उल्लेखनीय है।

19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मशीनों पर आधारित आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारम्भ हो गई। 1918 में औद्योगिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके फलस्वरूप 1922 से उद्योगों को विवेचनपूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। पूर्व के उत्पादन की तुलना में 1939 में सूती कपड़े तथा कागज का उत्पादन ढाई गुना तथा इस्पात का उत्पादन आठ गुना बढ़ गया। चीनी उत्पादन 1932 से 1936 के बीच आत्मनिर्भरता प्राप्ति के स्तर तक बढ़ गया। सीमेंट, माचिस, शीशा, साबुन वनस्पति घी एवं इंजीनियरिंग वस्तुओं के उत्पादन में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई। 1927 में सूती वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो जाने से इसका विकास और तेजी से हुआ। 1931 में सूती कपड़े की मिल्स की संख्या 278 तक पहुँच गई, जिनमें से बम्बई में ही 70 मिलें थीं।

औद्योगिक विकास को नई गति व दिशा पंचवर्षीय योजनाओं के श्रीगणेश से मिला।

इस अवधि में लोक उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए सरकार द्वारा सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया गया। सन् 1902 में लोक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रथम हाइड्रो शक्ति परियोजना—शिव समुद्रम को स्थापित किया गया। सन् 1916 में भारत के प्राकृतिक साधनों एवं औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गयी। सन् 1921 में देश में भारतीय प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति की गयी जिसने भारत के लिए भेद-मूलक संरक्षण नीति को अपनाने का सुझाव दिया। सन् 1930 में प्रसारण विभाग सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया।

लगभग इसी अवधि में सरकार ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक बन्दूक एवं शैल फैक्टरी, काशीपुर (बगाल) आदि लोक आयोग स्थापित किए सन् 1934 में गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता और मेजमॉन डॉक लिमिटेड की भी स्थापना किया गया। जैसे सन् 1937 में निजाम सुगर फैक्टरी लिमिटेड, सन् 1933 में मैसूर सुगर कम्पनी एवं 1924 में उत्तर प्रदेश में भारतीय वायु कम्पनी, भारतीय तरपेन्टाइन एण्ड रोसिन कम्पनी आदि को स्थापित किया गया।

इस अवधि में तृतीय महायुद्ध के कारण लोक उद्योगों को स्थापित एवं विकसित करने के लिए सरकार को अत्यधिक प्रेरणा मिली। युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए सन् 1940 में औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शोध मण्डल की स्थापना की गयी। सन् 1940 में श्री बालचन्द्र हीराचन्द्र द्वारा स्थापित हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैक्टरी को भारत सरकार ने सन् 1942 में अपने अधिकार में ले लिया। सन् 1944 में सरकार ने योजना एवं विकास विभाग की स्थापना की। सन् 1945 में इस विभाग द्वारा औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में एक विवरण प्रकाशित किया गया इस विवरण में कहा गया है कि सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों, रेल, डाक तथा सार्वजनिक सेवाओं के अतिरिक्त सभी राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए एवं अन्य उद्योगों को निजी क्षेत्र में छोड़ देना चाहिए इस प्रकार मूलतः इसी समय से मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली का प्रारम्भ हुआ इस अवधि में स्थापित लोक उद्योगों में फर्टिलाइजर्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ट्रावनकोर, प्रागटूल्स लिमिटेड गोहाटी, चालकुडी पोटररी लिमिटेड त्रिपुरा, गोण्डवाना पेण्ट्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड नागपुर रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिक मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी बंगलौर, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर उल्लेखनीय हैं।

## स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास :-

देश में योजनबद्ध विकास के पूर्व लोक उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। सन् 1948 की औद्योगिक नीति में निजी एवं लोक उद्योगों का क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया। इस वर्ष देश में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गयी तथा विद्युत पूर्ति अधिनियम पारित किया गया जिसके आधार पर देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत बोर्ड स्थापित किये गये। इसी वर्ष इलियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज बंगलौर की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया। इसके पश्चात 1949 में सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण किया जो लोक क्षेत्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था नियोजन के पूर्व ही सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम, इण्डियन रेयर आर्से लिमिटेड बम्बई नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स नेपानगर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि महत्वपूर्ण लोक उपक्रमों की स्थापना की। भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया 1950-51 में प्रारम्भ हुआ जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है -

### तालिका - 1

## लोक उद्यमों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में कुल व्यय का प्रावधान तथा व्यय का प्रतिशत

पंचवर्षीय योजना	कुल व्यय का प्रावधान (करोड़ रु० में)	व्यय का प्रतिशत
प्रथम	1980	2.5
द्वितीय	938	20.1
तृतीय	1726	20.1
चतुर्थ	2864	18.2
पांचवीं	8998	22.8

छठी	15002	13 7
सातवी	29220	13 4
आठवी	40588	9 3
नौवी	859000	अनुपलब्ध

स्त्रोत भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2000-2001 पेज न० 3

### प्रथम पंचवर्षीय योजना :-

प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय औद्योगिक विकास उपभेक्ता वस्तुओं तक सीमित था। मध्यवर्ती क्षेत्र में भी उद्योग थे लेकिन अल्पविकसित अवस्था में थे। पूँजीगत उद्योग लगभग नगण्य थे। इस प्रकार, प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के समय भारतीय औद्योगिक संरचना अल्पविकसित थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थी। इस योजना में कुल व्यय का केवल 25 प्रतिशत ही औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखे गये। इसके बावजूद, पहली पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि यह रही कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए जिसमें हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, सिन्दरी उर्वरक कारखाना, इंटिमल कोय फ़ैक्ट्री, रोपा फ़ैक्ट्री, इत्यादि। इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्थान पर वास्तविक वृद्धि दर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही।

### दूसरी पंचवर्षीय योजना :-

दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी जिसमें औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मूल व पूँजीगत वस्तु उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया।

इस योजना का भारत के औद्योगीकरण के इतिहास में विशेष महत्व है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

दूसरी योजना में कुल व्यय (4,672 करोड़ रुपये) का 20.1 प्रतिशत (938 करोड़ रुपये) औद्योगिक क्षेत्र पर खर्च किये गए। इसी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में तीन बड़े इस्पात कारखानों की स्थापना की गई जो पिछड़े क्षेत्रों (राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर) में लगाये गये। इनके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक, रेल इंजन व डिब्बे, भारी रसायन, मशीन टूल्स, जहाज आदि का भी निर्माण प्रारंभ हुआ। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि दर का लक्ष्य 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया था। लेकिन 7.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष ही प्राप्त किया जा सका।

### **तीसरी पंचवर्षीय योजना :-**

तीसरी योजना में औद्योगिक आधार को और मजबूत तथा विस्तृत करने का उद्देश्य रखा गया। इसी उद्देश्य के अनुरूप इस योजना में भी मूलभूत और पूँजीगत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। जिन औद्योगिक परियोजनाओं को स्थगित कर दिया गया था, उन्हें भी वरीयता दी गई। दूसरी योजना के समान ही तीसरी योजना में भी कुल व्यय (8,577 करोड़ रुपये) का 20.1 प्रतिशत (1,726 करोड़ रुपये) औद्योगिक क्षेत्र पर खर्च किये गये। इस योजना में कुल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर (15 प्रतिशत से अधिक) प्राप्त की गई।

### **वार्षिक योजनाएँ :-**

तीसरी योजना के बाद योजना प्रक्रिया को तीन वर्ष के लिए स्थगित करना पड़ा जिसका औद्योगिक विकास के प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ा। कई उद्योगों में विकास की क्षति पहुँची और कई अन्य उद्योगों में उत्पादन की

प्रक्रिया पर असर पड़ा। 1965-66 में औद्योगिक संवृद्धि की दर 53 प्रतिशत थी जो 1966-77 व 1967-68 में क्रमशः 0.2 और 0.5 प्रतिशत रह गयी। 1968-69 में इसमें सुधार हुआ और इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि दर 62 प्रतिशत हो गई।

### **चौथी पंचवर्षीय योजना :-**

चौथी योजना में औद्योगिक विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए : (1) औद्योगिक विकास की उन योजनाओं को पूरा करना जिनके सम्बन्ध में पहले निर्णय लिया जा चुका था। (2) वर्तमान तथा भावी विकास के लिए आवश्यक स्तरों तक औद्योगिक क्षमता में वृद्धि करना। औद्योगिक विकास की ये आवश्यकताएँ निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन अथवा बढ़ती घरेलू मांग से उत्पन्न हो सकता था तथा (3) घरेलू उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए नए उद्योगों की स्थापना।

चौथी योजना में कुल निवेश (15,779 करोड़ रुपये) का 18.2 प्रतिशत (2,864 करोड़ रुपये) औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखे गए। चौथी योजना में औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक रखा गया था लेकिन वास्तविक वृद्धि दर केवल 3.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ही प्राप्त की जा सकी।

### **पांचवी पंचवर्षीय योजना :-**

पांचवी योजना के औद्योगिकरण कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और संवृद्धि के साथ सामाजिक न्याय के उद्देश्यों के आधार पर तय किए गये थे। इन कार्यक्रमों में निवेश और उत्पादन के लिए निम्नलिखित संकल्पना की गयी थी। (1) प्रमुख क्षेत्र (Core Sector) उद्योगों का तेज विकास क्योंकि ये उद्योग दीर्घकालीन आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए इस्पात,

अलौह, धातुओ, उर्वरको, खनिज तेलो, कोयला और मशीन निर्माण उद्योगो में विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गई (2) निर्यात उत्पादक उद्योगों का तेज विविधीकरण और विकास (3) कपडा, खाद्य तेल व वनस्पति, चीनी, दवाईयों, साइकिल इत्यादि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन विस्तार तथा (4) अनावश्यक उपभोग वस्तुओ के उत्पादन पर रोक।

पाचवी योजना के कुल व्यय (39,436 करोड रूपये) का 22.8 प्रतिशत (8,998 करोड रूपये) औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखे गये। इस योजना मे औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर का लक्ष्य 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया था लेकिन वास्तविक वृद्धि दर प्रतिशत प्रतिवर्ष रही।

### **छठी पंचवर्षीय योजना :-**

तीस वर्षों के औद्योगिक विकास की गति और दिशा के बारे मे छठी योजना में कहा गया कि “अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संरक्षण दिए जाने के कारण, उद्योग कई बार अलाभकारी स्थानों पर स्थापित किए गए तथा उनमे क्षमता के सही प्रयोग की ओर भी ध्यान नही दिया गया। इससे उच्च लागत वाली औद्योगिक संरचना का निर्माण हुआ। तकनीक में सुधार और वस्तुओ की क्वालिटी में सुधार की ओर भी ध्यान नही दिया गया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र बहुत कम साधनों का सृजन कर पाया तथा क्षेत्रीय असमानताओं की स्थिति में विशेष परिवर्तन नही हुआ।”

छठी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा की गई। औद्योगिक नियन्त्रणों में ढील दी गई तथा औद्योगिक नीति और आयात-नीति को उदार बनाया गया। परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि होने लगी लेकिन इससे औद्योगिक विकास में असन्तुलन भी पैदा हुआ। उदारवादी औद्योगिक नीतियों के परिणामस्वरूप देश में उपभोग टिकाऊ वस्तुओं

का उत्पादन तो तेजी से बढ़ा लेकिन मूलभूत उद्योगों के उत्पादन में कमी आने लगी।

इस योजना में कुल व्यय (1,09,292 करोड़ रुपये) में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 13.7 प्रतिशत (15,002 करोड़ रुपये) था। इस योजना में औद्योगिक संवृद्धि की दर 7 प्रतिशत रही।

### **सातवीं पंचवर्षीय योजना :-**

सातवीं योजना में संवृद्धि के साथ विकास और उत्पादकता में सुधार मुख्य उद्देश्य रखे गये। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए

- (1) उचित कीमत तथा क्वालिटी की आम उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- (2) उत्पादन में सुधार लाकर तथा उपलब्ध तकनीकों का बेहतर प्रयोग करके उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करना।
- (3) घरेलू बाजार तथा निर्यात सम्भाव्य वाले उद्योगों का विकास
- (4) इलेक्ट्रॉनिक विकास में रोजगार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास।

सातवीं योजना में कुल व्यय (2,18,730 करोड़ रुपये) में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 13.4 प्रतिशत (29,220 करोड़ रुपये) रहा। इस योजना में औद्योगिक विकास की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8.4 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा था जब कि वास्तविक वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही।



## आठवीं पंचवर्षीय योजना :-

1991 में नई औद्योगिक नीति आने के बाद निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकाधिक रूप से मूलभूत (basic) तथा कोर (Core) उद्योगों तक केन्द्रित करने का निश्चय किया गया। इस कारण आठवी योजना में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा केवल 9.3 प्रतिशत (40,588 करोड़ रुपये) रखा गया था, जबकि वास्तविक व्यय 43,062 करोड़ रुपये था जो कुल वास्तविक व्यय 5,08,187 करोड़ रुपये का मात्र 8.5 प्रतिशत है। योजना औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि दर का लक्ष्य 7.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया था जब कि वास्तविक वृद्धि दर योजना के पाँच वर्षों के क्रमशः 2.3 प्रतिशत, 6.0 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत, 12.1 प्रतिशत तथा 7.1 प्रतिशत रही है।

आठवी योजना में औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें मात्रात्मक लक्ष्यों पर जोर कम किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में वांछित विकास प्राप्त करने के लिये मात्रात्मक प्रतिबन्धों तथा लाइसेंसिंग आदि नियंत्रणों के स्थान पर औद्योगिक, व्यापार तथा राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन का सहारा लेने का निश्चय किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय करने की घोषणा की गई।

- (1) आधुनिकीकरण, क्षमता व उत्पादन-संरचना पुनर्गठन तथा व्यापक पैमाने पर निजीकरण द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की पुनः संरचना।
- (2) सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और उसके निष्पादन (Performance) का निरन्तर मूल्यांकन करना।
- (3) दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से उद्यम-स्तर पर प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार लाना
- (4) राज्यों की सार्वजनिक इकाइयों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयास।

## नौवीं पंचवर्षीय योजना :-

(1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक)

नौवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में उन राज्यों में अधिक निवेश किया जायेगा जो अपेक्षाकृत कम साधन सम्पन्न हैं। क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करना नौवीं योजना की एक प्राथमिकता है। योजना आयोग के अनुसार सशोधन नौवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 8,59,000 करोड़ रुपये के परिव्यय में केन्द्रीय योजना 4,39,000 करोड़ रुपये की तथा राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजना 3,70,000 करोड़ रुपये की होगी। योजना के लिए 3,74,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आंतरिक स्रोतों से 2,90,000 करोड़ रुपये के ससाधन जुटाए जायेंगे। शेष 1,95,000 करोड़ रुपये राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्रों के जरिये जुटाए जायेंगे।

इस योजना के तहत लोक उद्यमों के माध्यम से सार्वजनिक रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जायेगा। कुछ लोक उद्यमों के निजीकरण पर भी विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिससे कारण लोक उद्यमों की संख्या में निरन्तर कमी हो और सरकार पर कम से कम वित्तीय बोझ हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना प्रारम्भ की है इसे गोल्डेन हैंड शेक स्कीम कहा गया है।

योजना में औद्योगिक-संरचना में परिवर्तन (Changes in Industrial Pattern during Planning Period)

योजनाकाल में भारतीय औद्योगिक-संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आजादी के समय भारतीय औद्योगिक-संरचना अल्प विकसित थी तथा

कमजोर आधार पर टिकी हुई थी। इस अवधि में औद्योगिक संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं -

(1) योजनाकाल में भारतीय औद्योगिक-संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आजादी के समय भारतीय औद्योगिक-संरचना अल्प विकसित थी तथा कमजोर आधार पर टिकी हुई थी। इस अवधि में औद्योगिक संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं -

(2) औद्योगिक क्षेत्र (विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस, जलपूर्ति) का पहली योजना के आरम्भ (1950-51) में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कुल हिस्सा केवल 15.1 प्रतिशत था जो 1980-81 में 24.4 प्रतिशत तथा 1996-97 में 29.3 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, योजनाकाल में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ा है। अर्थात् देश के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका में लगातार वृद्धि हुई है।

(3) पहली योजना के आरम्भ में औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक में पूंजीगत वस्तु उद्योगों का भाग 19.8 प्रतिशत था जो 1990 में बढ़कर क्रमशः 23.7 तथा 38.4 प्रतिशत हो गया। इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह रहा कि आयोजकों क्षेत्र में निवेश का बड़ा हिस्सा इन उद्योगों में लगाया गया क्योंकि इन उद्योगों के विकास के अभाव में औद्योगिक उत्पादन की वांछित वृद्धि दर प्राप्त करना संभव नहीं था।

(4) पाचवी योजना के बाद अर्थात् अस्सी के दशक में औद्योगिक नीति तथा आयात नीति के उदारीकरण के फलस्वरूप उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है।

(5) अस्सी के दशक में धातु आधारित उद्योगों के महत्व में गिरावट आई। इनके स्थान पर रसायन पेट्रो-रसायन तथा अन्य सम्बद्ध उद्योगों में अधिक

तेजी से विकास हुआ। अस्सी के दशक में औद्योगिक संरचना में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

(6) पहली योजना के आरम्भ के समय सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 5 इकाइयाँ थी और इनमें कुल 29 करोड़ रुपये का निवेश था। 1995-96 में इनकी संख्या 239 हो गई और कुल निवेश 1,73,874 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार योजनाकाल में सार्वजनिक क्षेत्र का न केवल विस्तार व विकास हुआ बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र ने आधारभूत और पूँजीगत उद्योगों के विकास और विस्तार के द्वारा निजी क्षेत्र के तीव्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### ***योजनाकाल में औद्योगिक ~~वेग~~ का मूल्यांकन***

(A review of industrial development during planning period)

औद्योगिक विकास के मूल्यांकन की दृष्टि से सम्पूर्ण योजनाकाल चार चरणों में बांटा जा सकता है।

(1) 1951 से 1965 तक

(2) 1965 से 1980 तक

(3) 1981 से 1990 तक

(4) 1991 से आज तक

औद्योगिक विकास के पहले चरण का समय 1951 तक है जिसमें प्रथम तीन योजनाएँ पूरी हुईं। यह समय भारतीय उद्योगों के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी काल में भारतीय औद्योगिक विकास की नींव रखी गयी। इस काल में मूलभूत वस्तु उद्योगों तथा पूँजीगत वस्तु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया और इस कार्य में महत्वपूर्ण सफलता मिली। यद्यपि इन तीनों योजनाओं में औद्योगिक संवृद्धि-दर के लक्ष्य को प्राप्त नहीं

किया जा सका लेकिन इन तीनों योजनाओं में औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर में क्रमशः वृद्धि हुई। यह दर पहली योजना में 5.7 प्रतिशत, दूसरी योजना में 7.2 प्रतिशत और तीसरी योजना में 9.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही।

इन तीनों योजनाओं में पूँजीगत वस्तु उद्योगों की संवृद्धि दर क्रमशः 9.8 प्रतिशत, 13.1 प्रतिशत और 19.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। इन तीनों योजनाओं में क्रमशः 4.7 प्रतिशत, 12.1 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत रही। मूलभूत वस्तु उद्योगों और पूँजीगत वस्तु उद्योगों की संवृद्धि दर को देखने से स्पष्ट है कि योजनाकाल के पहले चरण (1951-65) में औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली जिसका काफी श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश को जाता है।

औद्योगिक विकास के दूसरे चरण का समय 1965 से 1980 तक है। इस काल को औद्योगिक मंदी व संरचनात्मक प्रतिगमन (Structural Retrogression) का काल भी कहा जाता है। इस काल में औद्योगिक संवृद्धि दर में तेज गिरावट आई। 1965 से 1976 के मध्य संवृद्धि दर केवल 4.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। पाचवी योजना में संवृद्धि-दर 6.1 प्रतिशत थी जो 1979-80 में ऋणात्मक (-1.6 प्रतिशत) हो गई।

इस काल (1965-76) में पूँजीगत वस्तु उद्योगों की वार्षिक संवृद्धि-दर 2.6 प्रतिशत रह गई। मूलभूत वस्तु उद्योगों की वार्षिक संवृद्धि दर में भी तीव्र कमी इस बात का प्रमाण है कि इस काल में संरचनात्मक प्रतिगमन हुआ। इस काल में उन्हीं उद्योगों की संवृद्धि-दर अधिक थी जो उच्च आय वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे थे।

इस मंदी और संरचनात्मक प्रतिगमन के कई कारण थे। इसमें प्रमुख भूमिका कुछ बाह्य कारकों की रही जिसमें 1968 व 1971 के युद्ध, कुछ वर्षों में सूखे की स्थिति, आधारित संरचना का अपूर्ण या अल्प विकास तथा



अस्सी के दशक में औद्योगिक पुनरुत्थान के कारणों में उदार औद्योगिक तथा राजकोषीय नीति, कृषि क्षेत्र की माग में वृद्धि, सेवा क्षेत्र का तीव्र विस्तार तथा आधारित संरचना में निवेश में वृद्धि तथा दक्षता (Efficiency) में सुधार प्रमुख हैं।

इस काल में उद्योगों में प्रवेश पर प्रतिबन्धों में कमी की गयी, गई प्रौद्योगिकी और उच्च माल के आयात के लिए सुविधाएं और छूट प्रदान की गयी तथा स्थापित क्षमता के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त बड़े राजकोषीय घाटे, ऊँची दर पर अधिक ऋण तथा निबचत (Dissaving) में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में भी बड़े किसानों की आय में वृद्धि के कारण उपभोग वस्तुओं तथा कृषि में मशीनीकरण के विस्तार के कारण कृषि उपकरण व अन्य आगतों (Input) की माग में वृद्धि हुई। जिससे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की माग में वृद्धि हुई। इन दस वर्षों में आधारित संरचना में निवेश में भी तेज वृद्धि हुई जो दूसरे चरण के 4.2 प्रतिशत की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं।

नब्बे के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुआ। 1991 में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का नया युग आरम्भ हुआ। नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अधिकतर उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त किया गया, कार्यकारी नियमों व नियन्त्रणों में कमी की गयी, निजी क्षेत्र को अधिकतर उद्योगों में प्रवेश की अनुमति दी गई, सार्वजनिक क्षेत्र में अपरिवेश (Disinvestment) की योजना आरम्भ की गई, आय-कर निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदि में कमी की गई तथा घरेलू औद्योगिक क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिये खोला गया। इन सब गतिविधियों के आरंभिक परिणाम औद्योगिक क्षेत्र पर अच्छे नहीं पड़े। परिणामस्वरूप 1991-92 तथा 1992-93 में औद्योगिक संवृद्धि दर क्रमशः 0.6 प्रतिशत तथा 2.3 प्रतिशत रही। 1993-94 से

इस स्थिति में थोड़ा सुधार आया और 1993-94, 1995-96 में औद्योगिक संवृद्धि दर क्रमशः 0.6 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत और 12.1 प्रतिशत रही। लेकिन 1996-97 से इसमें पुनः कमी आई और यह केवल 7.1 प्रतिशत रह गई। आर्थिक उदारीकरण के प्रथम दो वर्षों में औद्योगिक संवृद्धि दर की कमी के कई कारण थे।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में अपनाए गए 'समष्टि आर्थिक समायोजन (Macro economic adjustment) कार्यक्रम के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी निवेश में भारी कमी करनी पड़ी जिसका प्रभाव निजी क्षेत्र में निवेश पर भी पड़ा।

(2) 1991 में भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के कारण आयातों की कीमत में वृद्धि हुई जिससे इन पर निर्भर उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ गई।

(3) उदारीकरण के आरम्भिक वर्षों में विदेशी मुद्रा संकट के कारण आयातों में भारी कटौती की गयी।

(4) मुद्रास्फीति रोकने के प्रयास में बैंकों की ब्याज दरों में वृद्धि की गई जिससे साख की लागत (Cost of credit) में वृद्धि हुई।

इसी समय, कृषि क्षेत्र में भी संवृद्धि दर में कमी आने के कारण इस क्षेत्र में माँग में कमी हो गई। सोवियत संघ के विघटन के कारण भारत की विनिर्मित वस्तुओं का एक बड़ा बाजार कम हो गया। मुद्रास्फीति के कारण शहरी क्षेत्रों के लोगों की वास्तविक आय में कमी हुई जिससे वस्तुओं की माँग में कमी हुई। सामाजिक व राजनैतिक अस्थिरता के कारण निवेश माँग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में औद्योगिक संवृद्धि दर में सुधार हुआ और यह क्रमशः 6.0 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत तथा 12.1 प्रतिशत



रही। 1994-95 तथा 1995-96 में पूँजीगत वस्तु उद्योग में संवृद्धि दर में काफी वृद्धि हुई और इन दो वर्षों में यह क्रमशः 24.8 प्रतिशत तथा 17.8 प्रतिशत रही। इसका अन्य औद्योगिक समूहों की संवृद्धि दर पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा। उपर्युक्त तीन वर्षों में औद्योगिक संवृद्धि दर में सुधार के कई कारण हैं। पहला यह कि नई औद्योगिक नीति का लाभ उठाने में औद्योगिक क्षेत्र को कुछ समय लगा। दो वर्षों के अन्तराल के बाद औद्योगिक क्षेत्र ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया और उदारीकरण का लाभ उठाने में सक्षम हो गया। दूसरा यह कि आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप पूँजी बाजार में सुधार हुआ तथा विदेशी पूँजी के उदारीकृत नियमों के कारण निजी क्षेत्रों की सार्वजनिक क्षेत्रों पर निर्भरता में अपेक्षाकृत कमी आई। तीसरा यह कि उदारीकरण के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा (Competition) का वातावरण बना जिससे निजी क्षेत्र में गत्यात्मक (dynamism) की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे इनकी कार्यकुशलता और दक्षता में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त विदेशी कम्पनियों के आगमन के कारण भारतीय निगम क्षेत्र में भी विलयन, एकीकरण आदि की प्रक्रिया तेजी से आरम्भ हुई जिससे पैमानों की बचतों का लाभ उठाने तथा अग्र व पश्च अनुबंधों (Forward and backward linkages) का लाभ उठाने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम हुए।

किन्तु उदारीकरण के फलस्वरूप बाजारों का जिस प्रकार प्रसार हुआ, उनका उस स्तर पर बने रहना संभव नहीं था। यही कारण है कि 1996-97 व उसके बाद से संवृद्धि दर में तेज गिरावट दर्ज की गई है। 1996-97 में पूँजीगत वस्तु उद्योग में वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत थी जबकि औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि दर केवल 7.1 प्रतिशत थी। इसका मूल कारण है कि भारत में आय के निम्न स्तर, आय की असमानता तथा संरचनात्मक कमियों के कारण उपभोक्ता व्यय में होने वाली वृद्धि के घरेलू बाजार में गुणाक प्रभाव (Multiplier effect) सीमित होंगे। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि

उदारीकरण के फलस्वरूप जिस उत्पादन व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है, वह आयातों पर अत्यधिक निर्भर है और उसकी रोजगार सृजन की क्षमता सीमित है। इस कारण, इसमें लोगों की आय बढ़ाने की सामर्थ्य कम है। योजना आयोग के अनुसार सशोधित नौवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 8,50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय में केन्द्रीय योजना 4,39,000 करोड़ रुपये की तथा राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजना 3,70,000 करोड़ रुपये की होगी। योजना के लिए 3,74,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आंतरिक स्रोतों से 2,90,000 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाए जायेंगे। शेष 1,95,000 करोड़ रुपये राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्रों के जरिये जुटाए जायेंगे।

अध्याय - दो  
औद्योगिक नीतियों के तहत  
लोक उद्यमों का विकास

स्वतन्त्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के बर्बाद हो चुके स्वरूप को पुनः सम्बल प्रदान करने तथा उसका तीव्र गति से विकास करने हेतु औद्योगीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। औद्योगीकरण हेतु नियोजित विकास की प्रणाली का सहारा लिया गया। भारतीय नियोजन के उद्देश्यों में विकास के साथ-साथ समाजवाद पर आधारित समाज की स्थापना और आय व सम्पत्ति के वितरण में समानता लाने को भी प्रमुखता दी गई। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत सरकार ने सुव्यवस्थित औद्योगिक नीति अपनायी और उसी के अनुरूप देश का औद्योगिक विकास किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का औद्योगिक वातावरण अत्यंत दयनीय अवस्था में था। पूँजी तथा कच्चे माल का अभाव, औद्योगिक सम्बन्धों में रखकर देश की पहली औद्योगिक नीति की 1948 में घोषणा की गयी।

### **औद्योगिक नीति 1948 :-**

6 अप्रैल 1948 को घोषित औद्योगिक नीति के प्रारूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था कायम करने का सुझाव दिया गया था। इस नीति में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का औद्योगीकरण हेतु महत्व स्वीकार करते हुए उद्योगों को स्वामित्व की दृष्टि से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ये चार क्षेत्र थे - उद्योगों के प्रथम वर्ग में अस्त्र-शस्त्र और युद्ध सामग्री के निर्माण परमाणु शक्ति के उत्पादन और नियंत्रण तथा रेल परिवहन के स्वामित्व और प्रबन्ध पर केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार भी दिया गया था कि वह आपातकाल में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी भी उद्योग को अपने स्वामित्व में ले सकती थी।

इस वर्ग में छ उद्यम शामिल किये गये थे - कोयला, लोहा इस्पात, वायुयान, पोत निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ का वायरलेस यंत्र तथा खनिज तेल। इस वर्ग के उद्योगों की नई इकाइयों की स्थापना का U. S. P.

उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया था, परन्तु पुरानी इकाइयों को निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया गया।

तीसरे वर्ग में उन मूलभूत महत्ता के उद्योगों को सम्मिलित किया गया जिनका आयोजन और नियमन केन्द्रीय सरकार स्वयं करना आवश्यक समझती थी। इस लाबी में राष्ट्रीय महत्व के 18 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है।

नमक, मोटर गाड़ियों, ट्रैक्टर, विद्युत, भारी इंजीनियरिंग, मशीनी औजार, भारी रासायनिक सामग्री, उर्वरक, अलौह धातुएं, रबड़ संचालनशक्ति, औद्योगिक अल्कोहल, सूती व ऊनी कपड़ा, सीमेंट, चीनी कागज, वायु और नौ परिवहन, खनिज और प्रतिरक्षा से सम्बन्धित उद्योग।

उपर्युक्त तीन वर्गों के अलावा शेष सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित और विकसित करने का अधिकार दिया गया।

1948 की औद्योगिक नीति में लघु तथा कुटीर उद्योगों का महत्व स्वीकारते हुए इसके लिए सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं जुटाने पर बल दिया गया। उसके अलावा औद्योगीकरण हेतु विदेशी पूंजी के महत्व को भी स्वीकार करने का भी प्रावधान किया गया। विदेशों से तकनीकी के आगमन और भारतीय श्रम के प्रतिरक्षण के लिए विदेशी सहायता ली जा सकती थी, परन्तु इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय उद्यमों में लगे विदेशी श्रमिकों द्वारा धीरे-धीरे प्रतिस्थापित करने का विचार रखा गया। औद्योगिक शान्ति की स्थापना की जरूरत को महत्वपूर्ण मानते हुए श्रमिकों को न्यायोचित मजदूरी के साथ-साथ पूंजीपतियों को समुचित प्रतिफल देने की सिफारिश भी की गयी।

## औद्योगिक नीति 1956 :-

द्वितीय पंचवर्षीय योजना देश के तीव्र औद्योगीकरण को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी अतः इसके लिए औद्योगिक नीति में भी आवश्यक परिवर्तन करना जरूरी समझा गया। सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना को अपना मूल उद्देश्य मानते हुए 30 अप्रैल 1956 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने और इसके लिए औद्योगीकरण में तीव्रता लाने को मुख्य उद्देश्य माना गया था। औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र का विस्तार करना आय व सम्पत्ति के वितरण में समानता लाना और इस क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना भी महत्वपूर्ण समझा गया। इस नवीन नीति की मुख्य विशेषताएँ निम्न थीं।

(1) निम्न औद्योगिक नीति में 1948 के उद्योगों का वर्गीकरण प्रारूप में कुछ संशोधन करके उन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया।

(2) उद्योगों के प्रथम वर्ग में उन उद्योगों को शामिल किया गया जिन पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार होगा और उनका पूर्ण दायित्व राज्य पर होगा। इस वर्ग में 17 उद्योगों को शामिल किया गया। परन्तु इस वर्ग के उद्योगों में वर्तमान समय में कार्यरत निजी इकाइयों के राष्ट्रीयकरण का प्रावधान नहीं किया गया था। बल्कि उन इकाइयों को स्वयं विकसित होने का समुचित अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया इस वर्ग के उद्योगों को पाँच उपवर्गों में विभाजित किया गया —

(क) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग, जैसे अस्त्र-शस्त्र, युद्ध सम्बन्धी अन्य उपकरण तथा परमाणु शक्ति।

(ख) भारी उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, लोहा इस्पात की कास्टिंग व फोर्जिंग, भारी मशीन निर्माण तथा विद्युत मशीनें।

(ग) खनिज उद्योग जिसमें कोयला व लिग्नाइट, खनिज तेल, लोहा, मैंगनीज, जिप्सम, गंधक, सोना, हीरा, तौबा, क्रोम, सीसा, जस्ता, टिन आदि का खनन शामिल था।

(घ) परिवहन तथा संचार जिसमें वायु परिवहन, वायुयान निर्माण, रेल परिवहन जलयान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा वायरलेस उपकरणों (रेडियो रिसीविंग सेट छोड़कर) को शामिल किया गया था।

(ड०) शक्ति, जिसमें विद्युत का उत्पादन किया तथा वितरण शामिल था।

(i) यह सार्वजनिक तथा निजी उद्यम का मिश्रित क्षेत्र वाला वर्ग था। ऐसा विचार किया गया कि उस वर्ग के उद्योगों पर राज्य का अधिकार बढ़ता जाएगा और जिनमें साधारणतया राज्य नये उद्यमों की स्थापना करेगा, किन्तु निजी क्षेत्र से उनको चलाने में सहायता प्राप्ति की भावी विकास की दिशा में राज्य का ही प्रयास होगा परन्तु निजी उद्यमियों को भी स्वतंत्र रूप से या राज्य के साथ सहयोग करते हुए नयी इकाइयों की स्थापना के अवसर प्रदान करने का विचार रखा गया था। इस श्रेणी में निम्न 12 उद्योगों को शामिल किया गया था। अन्य खनन, उद्योग, अल्युमीनियम तथा अन्य अलौह धातुएं मशीन औजार, लौह मिश्रित धातु और औजार इस्पात, रसायन, उद्योग, एंटीवायोटिक्स एवं अन्य आवश्यक दवाएँ उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कोयले का कोर्बानाइजेशन रासायनिक लुग्दी सड़क, परिवहन तथा समुद्री परिवहन।

(ii) अनुसूची 'अ' तथा 'ब' में शामिल उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योग इस वर्ग में शामिल किये गये हैं। यह निजी उद्योगों का क्षेत्र है, जिसके भावी विकास का भार निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ग

के अन्तर्गत आने वाले उद्योग यद्यपि निजी उद्यम द्वारा विकसित होंगे, परन्तु उसका यह कदापि तात्पर्य नहीं है कि वे अपनी गतिविधियों में पूर्ण स्वतंत्र होंगे, बल्कि वे सरकार द्वारा बनाये गये अनेक नियमों जैसे – उद्योग अधिनियम आदि से नियंत्रित एवं निर्देशित होंगे।

उद्योगों के उपर्युक्त वर्गीकरण की स्पष्ट रूपरेखा के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आने वाले उद्योगों की स्थापना कुछ विशेष परिस्थितियों में निजी क्षेत्र द्वारा की जा सकती है और निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में भी की जा सकती है। अर्थात् दोनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग एवं सामेज्य स्थापित कर सकते हैं।

(2) नई औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र के उद्योगों को सरकार द्वारा स्वच्छ एवं पक्षपात रहित समर्थन देने का वादा किया गया है। सरकार इसके लिए आवश्यकता अथ संरचना जैसे – परिवहन, विद्युत तथा अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ उसे वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।

(3) इस नीति में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने का विचार रखा गया। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की अधिकता को देखते हुए इनके विकास के लिए प्रत्यक्ष सहायता व अनुदान देने के साथ-साथ बड़े उद्योगों पर अनेक नियंत्रण लगाने की भी व्यवस्था की गई। उस क्षेत्र के उत्पादन की गुणवत्ता में भी वृद्धि करने पर बल दिया गया।

(4) नई औद्योगिक नीति में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने हेतु पिछड़े क्षेत्रों में शक्ति के साधनों और परिवहन सुविधाओं के विस्तार करने पर विचार किया गया था। उसके अलावा सभी क्षेत्रों में कृषि तथा उद्योग के मध्य संतुलन स्थापित करने पर भी बल दिया गया।



(5) समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नई नीति में श्रमिकों के हितों की रक्षा का विशेष ख्याल रखा गया और प्रबन्धकीय मामलों में उनकी भागीदारी को भी स्वीकार किया गया। वास्तव में श्रमिकों का हित साधन करके औद्योगिक शान्ति बनाये रखना औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक समझा गया।

(6) नई नीति में विदेशी निवेश के प्रति सरकार वही नीति अपनाने का विचार करती है, जिसे उसने 1948 की औद्योगिक नीति में अपनाया था।

दत्त समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखकर सरकार ने 2 फरवरी 1973 को 1956 की औद्योगिक नीति में कुछ संशोधन किये और संयुक्त क्षेत्र की स्थापना का विचार रखा गया। निजी क्षेत्र को अनेक रियायतें भी दी गईं। सरकार ने 19 उद्योगों को शामिल करते हुए 'परिशिष्ट I' का गठन किया, जिसमें राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योग तथा नियति के लिए महत्व रखने वाले उद्योग शामिल थे। इस श्रेणी के अनेक उद्योगों को निजी क्षेत्र की देशी तथा विदेशी फर्मों द्वारा खोलने की अनुमति दी गई।

### **औद्योगिक नीति 1977 :-**

दत्त समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखकर सरकार ने 2 फरवरी, 1977 को जनता पार्टी की सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जो बेरोजगारी नगरीय तथा ग्रामीण असमानता और औद्योगिक रूग्णता की दयनीय स्थिति पर नियंत्रण लगाकर औद्योगिक विकास करने की अवधारणा पर आधारित थी। इस औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्न थी—

(1) लघु औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार अवसरों की अधिकता और आय व सम्पत्ति की समानता लाने में विशेष भूमिका को देखते हुए नई नीति में इनके विकास पर विशेष बल दिया गया था, सरकार की यह नीति थी कि जो कुछ

भी लघु एव कुटीर उद्योगों को विशेष महत्व देने की हानियों को पहचानकर ही लघु उद्योगों को तीन खण्डों में विभाजित किया —

(I) कुटीर एव घरेलू उद्योग जो स्वरोजगार के निर्माण में विशेष रूप से सक्षम होते हैं।

(II) पिछड़ी क्षेत्र, जिनमें मशीनों व अन्य औजारों पर 1 लाख रुपये से कम का निवेश होता है तथा जो 50000 से कम आबादी वाले नगरों में उपस्थित हैं।

(III) लघु उद्योग क्षेत्र में जिनमें 10 लाख रुपये तक का विनियोग हुआ हो इन तीनों वर्गों के विकास के लिए नई नीति में निम्न व्यवस्थाएँ की गईं।

(i) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की संख्या 180 से बढ़ाकर 807 कर दी गई।

(ii) लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का विचार रखा गया।

(iii) खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग को पुनः व्यवस्थित करके उनकी गति विधियों में विस्तार करने का विचार रखा गया और इसके लिए पालिस्टर खादी, जूते साबुन आदि का उत्पादन करने की व्यवस्था की गई।

(2) नई नीति में बड़े पैमाने पर उद्योगों को जनसंख्या की मूल न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया, ताकि वे लघु तथा ग्राम उद्योगों के फैलाव को बढ़ावा दे सकें और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर सकें।

(3) नई औद्योगिक नीति में यह स्वीकार किया गया कि बड़े औद्योगिक घरानों का विकास उनके अपने संसाधनों की तुलना में कहीं अधिक हो गया है। अर्थात् उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर अपना

विकास किया हुआ है। यह नीति बड़े घरानों को अपना विकास अपने ही ससाधनों से करने को प्रेरित करती है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय सस्थाओं के साधनों के हाथों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए ऐसा विचार रखा गया कि भविष्य के पूँजी प्रधान उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों द्वारा की जाय।

(4) नई औद्योगिक नीति तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने पर बल देती है।

(5) विदेशी सहयोग के अनावश्यक क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने पर बल दिया गया। साथ ही साथ उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रभावी नियंत्रण भारतीयों में ही रखने की आवश्यकता को समझा गया।

(6) इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को और और अधिक बढ़ाने पर बल दिया ताकि आर्थिक विकास के साथ-साथ स्थिरता बनी रहे।

(7) बीमार औद्योगिक इकाइयों के प्रति नई औद्योगिक नीति चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाती है। वस्त्र, पटसन, चीनी आदि उद्योगों की अनेक बीमार इकाइयों को पुनः स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है परन्तु सभी इकाइयों को राष्ट्रीयकृत करना सम्भव नहीं है।

### **औद्योगिक नीति 1980 :-**

1980 में कांग्रेस (इ) सरकार की स्थापना के पश्चात् उसने अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा जुलाई 1980 में की जो मूलतः 1956 की औद्योगिक नीति पर आधारित थी। इस नीति के तीन मौलिक उद्देश्य निर्धारित किये गये थे – आधुनिकीकरण विस्तार और पिछड़े क्षेत्रों का विकास पिददी, छांट तथा सहायक उद्योगों में निवेश का उच्चतम सीमा का निर्धारण करने, अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बड़े

पैमाने की इकाइयों को स्वतः विस्तार की सुविधा की अनुमति प्रदान करने तथा पिछड़े क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक केन्द्र कायम करने का भी प्रावधान किया गया था। इस औद्योगिक नीति में तीव्र एवं सन्तुलित औद्योगिक विकास करने पर जोर दिया गया था ताकि आम आदमी के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ायी जा सके।

इस औद्योगिक नीति के निम्न सामाजिक उद्देश्य निर्धारित किये गये—

- (1) स्थापित क्षमता का अनुकूलतम उपयोग
- (2) उत्पादन अधिकतम करना और उत्पादकता का उच्च स्तर प्राप्त करना
- (3) रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- (4) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना।
- (5) निर्यात प्रेरित और आयात प्रतिस्थापना उद्योगों को तेजी से विकसित करना
- (6) कृषि आधारित उद्योगों को पोषाह्न देकर कृषि आधार को मजबूत बनाना और अनुकूलतम अन्तः क्षेत्रीय सम्बन्धों को प्रोन्नत करना।
- (7) देश में आर्थिक संघर्ष को प्रोत्साहन देना और इसके लिए विनियोग का न्यायोचित विस्तार करना और इसके प्रतिफल को ग्रामीणों तथा नगरीय क्षेत्रों में छोटी तथा विकासशील इकाइयों में वितरित करना।
- (8) ऊँची कीमतों तथा घटिया गुणवत्ता के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस नीति में निम्न प्रस्ताव रखे गये —

- (1) सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की क्षमता एवं दक्षता को पुनः बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाय और उनका समयबद्ध सुधार किया जाय।

- (2) आर्थिक संघर्ष की धारणा को प्रोत्साहित करके निजी क्षेत्र का औद्योगिक विकास में समन्वय कायम करने पर बल दिया गया। इसी उद्देश्य से प्रत्येक जिले में कुछ केन्द्रक संगठन स्थापित करने का विचार रखा गया।
- (3) लघु पैमाने पर उद्योगों के तीव्र विकास हेतु उनकी पुनः परिभाषा की गई और पिछड़ी, छोटे तथा सहायक इकाइयों में निवेश की उच्चता सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2 लाख, 20 लाख और 25 लाख कर दी गई।
- (4) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण को आवश्यक समझा गया, परन्तु इसके साथ-साथ उनके पर्यावरण की रक्षा को आवश्यक माना गया। ग्रामीण उद्योगों में रोजगार वृद्धि और उनकी सहायता से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से हस्तकलाओं, हथकरघा और खादी आदि ग्रामोद्योगों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने का विचार किया गया।
- (5) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु पिछड़े क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया।
- (6) निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा अपनी क्षमता के अनाधिकृत विस्तार को नियमित करने हेतु इसके लिए कानून बनाये गये। लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक स्थापित क्षमता को कानूनी घोषित करने हेतु फेरा और एकाधिकार व प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों के सम्बन्ध में चयनात्मक आधार पर प्रस्ताव रखा गया।
- (7) बड़े उद्योगों को स्वतः विस्तार की सुविधा प्रदान की गई।
- (8) औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध में नई नीति ने स्पष्ट किया कि उन औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी जो जानबूझकर कुप्रबंध और वित्तीय गोलमाल करते हैं। जिन रूग्ण इकाइयों में पुनरुत्थान की संभावना होगी, उनका अन्य स्वस्थ इकाइयों के साथ विलय कर दिया

जाएगा। किसी इकाई की निजीकरण अन्य सभी उपायों के असफल हो जाने पर ही किया जाएगा।

### औद्योगिक नीति 1991 :-

देश के औद्योगिक तथा आर्थिक परिदृश्य की दयनीय दशा को देखते हुए 24 जुलाई, 1991 को श्री नरसिंह राव सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। अब तक की सभी औद्योगिक नीतियाँ घरेलू उद्योगों को अत्यधिक संरक्षण प्रदान करने पर बल देती थी, फलतः उनका स्वतः विकास नहीं हो सका और उनकी तकनीक भी पिछड़ी बनी रही। इसी कारण भारत की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी भी घटती गई। एक ओर तो देश के बड़े औद्योगिक घरानों का तेजी से विकास हुआ, परन्तु दूसरी ओर देश के समक्ष विकास की दर में हास हुआ। देश का व्यापार व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा था और विदेशी मुद्रा कोष लगभग खाली हो चुका था।

इन्हीं परिस्थितियों में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य देश को गम्भीर आर्थिक संकट से उबारना, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न हुए लाभों को और अधिक मजबूती प्रदान करना, उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और भारतीय उद्योगों को अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करना आदि निर्धारित किया गया। इसके लिए सरकार ने उद्योगों से सम्बन्धित अनेक नीतिगत उपायों की घोषणा की जिन्हें पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(5) अब तक सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगों की अंधाधुंध स्थापना विस्तार को नियंत्रित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक बनाए हुए थी, जिससे उद्योगपतियों को अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई नीति में सरकार की उस नियंत्रणकारी भूमिका को समाप्त करके उसे सहायता व सलाहकारी रूप प्रदान किया गया है। अब सरकार ने लाइसेंस U. S. P.

पद्धति को ही लगभग समाप्त कर देने का फैसला किया है, ताकि उद्योगों की स्थापना में अनावश्यक देरी और अन्य समस्याएं न खड़ी हों। इसके निम्न नीतिगत फैसले लिए गए हैं—

(i) नये उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है।

(ii) अब सिर्फ 14 विशिष्ट किस्म के उद्योगों के लिए ही लाइसेंस लेना जरूरी होगा, जो प्रतिरक्षा, सामाजिक कारणों, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से हानिकारक और उच्च आय वर्ग के उपभोग की वस्तुएं हैं।

(iii) नये उद्योगों को अपना उत्पादन कार्यक्रम बताने की अब आवश्यकता नहीं होगी तथा मौजूदा इकाइयां बिना लाइसेंस या अनुमति के अपना विस्तार व क्षमता में वृद्धि कर सकेंगी।

(iv) मौजूदा उद्योगों को बिना किसी अतिरिक्त पूंजी निवेश के अपने लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के किसी भी वस्तु के उत्पादन की छूट होगी।

(2) यद्यपि भारतीय उद्योग अपना निरन्तर विकास कर रहे हैं, परन्तु अभी भी उनकी तकनीकी तथा उत्पादन क्षमता निम्न है अतः उनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी बाजार व प्रबंधकीय विशेषता, निर्यात की संभावनाओं में वृद्धि करने हेतु विदेशी निवेश को अनावश्यक समझा गया और इसके लिए निम्न उपाय किये गये।

(i) जिन मामलों में मशीनों के लिए विदेशी पूंजी की उपलब्धता शेयर पूंजी के रूप में होगी, उन्हें स्वतः ही उद्योग लगाने की अनुमति मिल जायेगी।

(ii) 2 करोड़ या कुल पूंजी के 25 प्रतिशत से कम उत्पादक मशीनें बिना किसी पूर्व अनुमति के आयात की जा सकेंगी।

(iii) उच्च प्राथमिकता प्राप्त 34 उद्योगों में 51 प्रतिशत से कम की उत्पादक मशीनें विदेशी निवेश की अनुमति के बिना किसी रोक-टोक के प्रदान की जाएगी। यह सुविधा इन मामलों में ही उपलब्ध होगी जहाँ उत्पादन के लिए विदेशी पूँजी आवश्यक होगी।

(iv) यदि सम्पूर्ण उत्पादन निर्यात के लिए हो, तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का 100 प्रतिशत तक पूँजी निवेश की अनुमति भी दी जा सकती है।

(3) भारतीय उद्योगों के प्रौद्योगिकीय पिछड़ेपन को देखते हुए उन्हें विदेशों से तकनीकी आयात की सुविधा प्रदान की गयी है। विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु सरकारी अनुमति प्राप्त करने में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए सरकार ने निम्न व्यवस्थाएँ की हैं .—

(i) अब भारतीय कम्पनियाँ अपनी वाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुरूप विदेशी कम्पनियों से प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण सम्बन्धी अनुबन्धों के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगी और सरकार निर्दिष्ट मापदण्डों के भीतर इन अनुबन्धों को स्वतः अनुमोदन प्रदान करेगी।

(ii) नयी नीति में विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति या देश में ही विकसित तकनीकों का विदेशों में परीक्षण करने के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

(4) योजनाकाल के प्रारम्भ से ही देश के औद्योगीकरण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया था, परन्तु धीरे-धीरे यह क्षेत्र भयंकर घाटे का शिकार हो गया है तथा उनमें भारी कुप्रबन्ध व्याप्त हो गया है। इसीलिए नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया गया है—



(i) अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 थी जिसे नई नीति में घटाकर 6 कर दिया गया है। ये 6 क्षेत्र प्रतिरक्षा सम्बन्धी हथियार व उत्पादन, परमाणु ऊर्जा, कोयला व लिग्नाइट, खनिज तेल परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित खनिज तथा रेल परिवहन है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक सुरक्षित उद्योग धीरे-धीरे निजी क्षेत्र के लिए खोले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र को भी अब तक प्रतिबंधित क्षेत्र में विस्तार की अनुमति होगी।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में सरकारी शेयर पूंजी के कुछ भाग को वित्तीय संस्थाओं, आम जनता तथा कर्मचारियों में बेचने का प्रावधान किया गया था। इसी के तहत वर्ष 1991-92 में सरकार ने 31 सार्वजनिक उद्यमों के इक्विटी शेयर मेचुअर फंडो व वित्तीय संस्थाओं को बेचकर 5038 करोड़ रुपये तथा 1992-93 में 20 लाभदायक उद्यमों के शेयर सीधे बाजार में सूचीबद्ध कराकर प्रत्यक्ष रूप से विनिवेश कर 3500 करोड़ रुपये प्राप्त किये। इस 3500 करोड़ रुपये में से 1000 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष में तथा 2500 करोड़ रूपी वित्तीय घाटे को कम करने के लिए प्रयोग करने का प्रावधान किया गया।

(iv) निरन्तर घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों की जाँच व सहायता का कार्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड करेगा।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज की खुली समीक्षा के लिए सरकार तथा किसी अन्य उद्यम के बीच हुए इस प्रकार के सहमति पत्र की प्रति संसद में रखी जाएगी।

इस प्रकार नई नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को अपना विकास स्वयं करने हेतु आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर बल दिया गया है।

## *सार्वजनिक क्षेत्र की नीति के भावी दिशा निर्देश*

लोक उद्यमों के निष्पादन में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 1991 को नयी औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सम्वन्ध में अगलिरिखित निर्णय किए गए

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन को उन्नत करने के लिए बोध ज्ञापन की पद्धति द्वारा प्रबन्धकों को अधिक स्वायत्तता दी जायेगी और उन्हें अधिक उत्तरदायी भी बनाया जायेगा।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन उद्योगों की समीक्षा की जाएगी ताकि लोक क्षेत्र को अध सरचना हाईटेक और सामरिक महत्व के उद्योगों तक सीमित रखा जा सके। भले ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ क्षेत्र सरक्षित रखे जाए किन्तु कई अन्य क्षेत्र जो अभी तक लोक क्षेत्र के लिए रिजर्व थे, निजी क्षेत्र के लिए चयनात्मक रूप में खोल दिए जायेगे। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र को भी ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने की स्वीकृति दी जाएगी, जो इसके लिए संरक्षित नहीं थे।

(3) ऐसा सार्वजनिक उद्यम जो जीर्ण रूप में बीमार है और जिनके सक्षम बनने की कोई सभावना नहीं है, उन्हें पुनरुत्थान के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय निर्माण बोर्ड को सौंप दिया जायेगा जिससे बीमार इकाइयों की पुनः स्थापना की जा सके और उनके निष्पादन में सुधार का क्रम जारी हो सके तथा यथाशीघ्र बीमारी से मुक्त होकर स्वस्थता की ओर अग्रसर हो सके। इस बोर्ड के अधिकार सीमा में वृद्धि कर दी गई है, अब यह परिषद अस्वस्थ इकाइयों की जांच करके उनके संबन्ध में अग्रंकित निर्णय ले सकती है।

(4) श्रमिकों के हितों के रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रक्रिया कायम की जाएगी ताकि विस्थापित श्रमिकों को राहत पहुँचाई जा सके और सभी श्रमिक सुरक्षा की भावना महसूस करते हुए उत्पादन कार्य में पर्याप्त रूचि लेकर

निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाते रहे और लोग उपक्रम उन्नति पथपर अग्रसर होकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

(5) साराधान गतिमान करने एवं सार्वजनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी हिरसा-पूँजी के एक भाग को पारस्परिक निधियो वित्तीय सस्थानों और सामान्य जनता को बेचा जाएगा जिससे अधिक मात्रा में पूँजी एकत्रित हो सके और वित्तीय संकट से जूझ रही कम्पनिया वित्त की पर्याप्त मात्रा एकत्रित कर सकें और वित्त की समस्या से मुक्त होकर अपने विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकें।

(6) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के बोर्डों को अधिक व्यावसायिक बनाया जायेगा और उन्हें अधिकार दिए जाएंगे। जिससे बोर्ड के अधिकार सीमा में वृद्धि हो और बोर्ड के सभी सदस्य उत्पादन कार्य में रुचि लेकर लोक उपक्रमों के उन्नति में अधिकाधिक योगदान दें और देश की सभी इकाइयों रूग्णता से निजात पाने में सफल हो सकें।

सरकार महत्वपूर्ण एवं सामरिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के विनियोग के लिए खोल रही है। संचालन शक्ति क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों के लिए खोल दिया गया है। इसीप्रकार सरकार ने रेली संचार क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सरकार बैंको तथा बीमा कम्पनियों के निजीकरण के बारे में भी सोच रही है परन्तु मजदूर संघों के कड़े विरोध के कारण सरकार अस्थायी रूप में पीछे हट गयी है पर यह रिजर्व क्षेत्रों को निजी क्षेत्र देशी या विदेशी को खोलने की नीति को फिर लागू करने का प्रयास करेगा।

(8) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त श्रमिकों के भार को भी कम करने का भी प्रयास करती रही है। आरंभ में यह निकासी नीति के विचार को लागू करना चाहती थी। परन्तु मजदूर संघों के कड़े विरोध के कारण इस विचार **U. S. P.**

का परित्याग कर दिया। इसकी अपेक्षा सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनायी और इसमें सफल हो गयी है। वर्ष 93-94 और 97-98 के दौरान 1338 करोड़ का राष्ट्रीय नवीकरण निधि में उपलब्ध कराये गये जिससे 1 09 लाख श्रमिकों को इस अवधि के दौरान सहायता उपलब्ध करायी गयी।

(8) सरकार ने लोग उद्यमों की हिस्सा पूँजी के अविनियोग का प्रोग्राम बनाया है। 1991 से ससाधन गतिमान करने और सार्वजनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और इन्हें अधिक दायित्वपूर्ण बनाने के लिए सरकार चुने हुए उद्यमों की 20 प्रतिशत तक हिस्सा पूँजी पारस्परिक निधियों, वित्तीय विनियोग संस्थाओं, श्रमिकों तथा आम जनता को बेचेगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए सरकार ने 91-92 और 92-93 में ऐसी सरकारी उद्यमों जिनका निष्पादन रिकार्ड अच्छा था, बेचकर क्रमशः 3038 करोड़ रु० और 1912 करोड़ रु० प्राप्त किए।

अपने बजट घाटे को कम करने की प्रबल इच्छा के कारण वित्त मंत्रालय ने विनिवेश कार्यक्रम में अनुचित तेजी दिखलायी। इसी कारण कुछ आलोचकों ने अनिवेश प्रोग्राम को घाटापूर्ति निजीकरण की सजा दी है।

लोक लेखा समिति की इस तीखी आलोचना के परिणामस्वरूप सरकार ने खुली नीलामी का फैसला किया है और जैसा कि उपलब्ध सूचनाओं से पता चलता है कि चार साल पूर्व इन्हीं हिस्सों से उपलब्ध कीमत प्राप्ति की तुलना में अब कहीं अधिक कीमत प्राप्त की गयी है। इन कंपनियों में शामिल हैं महानगर टेलीफोन निगम लि०, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि०, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शी रूप में चलती रही तो अनिवेश से कीमत प्राप्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की सम्भावना है।

अनिवेश प्रोग्राम के आरम्भ से 31 मार्च 97 तक 12957 करोड रू० अनिवेश द्वारा प्राप्त किए गए। 98-99 में क्रास होल्डिंग के एक नवीन तरीके से 9000 करोड रू० अनिवेश से प्राप्त किए गए।

### **बोध ज्ञापन (Memorandum of understanding) :-**

सरकार ने लोक उद्यम नीति समीक्षा समिति अर्थात् अर्जुनसेनगुप्त समिति (1985) की सिफारिश के आधार पर बहुत से सार्वजनिक लोक उद्यमों के साथ बोध ज्ञापन के रूप में समझौते कर लिए हैं। बोध-ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य स्वायत्तता और उत्तरदायित्व में संतुलन स्थापित करना है उन लोक उद्यमों को छोड़ जो निर्देश के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय निर्माण बोर्ड को सौंपे गए, नयी औद्योगिक नीति के आधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ बोध ज्ञापन किए गए। बोध ज्ञापन नीति का मुख्य उद्देश्य "नियंत्रण की मात्रा को कम करना और उत्तरदायित्व की गुणवत्ता" को बढ़ाना है। जहां प्रत्येक लोक उद्यम के उद्देश्यों की स्पष्ट रूप से परिभाषा करनी चाहिए वहां यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक लोक उद्यम को कार्यात्मक स्वायत्तता दी जाय। बोध-ज्ञापन का वास्तविक उद्देश्य "लोक उद्यमों व्यवस्था" नियंत्रण द्वारा प्रबन्ध की अपेक्षा उद्देश्यों द्वारा प्रबन्ध के आधार पर करना है। लोक उद्यमों में सन्तुलन मात्र करने के लिये यह बेहतर होगा कि लाभ उद्देश्य को अधिक महत्व प्रदान किया जाय। सर्वाधिक उद्यमों के उद्देश्यों की पुनः परिभाषा करनी चाहिए तथा विभक्त उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक उद्देश्य के महत्व के बारे में स्पष्ट निर्णय होना चाहिए ताकि इनमें निष्पादन की कसौटियों का विकास हो सके।

1992-1993 में 98 लोक उद्यमों ने बोध-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया और 97-98 तक 108 उद्यमों ने इस प्रकार लोक उद्यम बोध-ज्ञापन

**U. S. P.**

प्रणाली के आधीन आ गए है इनका मुख्य उद्देश्य उन्हें मन्त्रालयों के नियंत्रण से मुक्त कराना है और एक स्पर्द्धात्मक पर्यावरण में स्वायत्त रूप में कार्य करने की इजाजत देना है। 97-98 के दौरान जिन 108 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने बोध-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, उनके मूल्यांकन से पता चलता है कि इनमें से 45 अति उत्तम आके गए। इससे सिद्ध होता है कि बोध-ज्ञापनों के आधीन कार्य कर रहे लगभग 77 प्रतिशत उद्यमों ने अपनी स्थिति उन्नत कर ली है और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस पद्धति को और मजबूत तथा दोषरहित बनाना चाहिए।

### **सरकारी उद्यमों के विस्तार के पक्ष में तर्क :-**

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था (Developing Economy) में कुछ उद्योगों को सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण के अन्तर्गत लाना ही पड़ेगा। अन्यथा अर्थव्यवस्था का द्रुत गति से विकास सम्भव नहीं हो पायेगा। कुछ औद्योगिक बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण और नयी इकाइयों को आरम्भ करने में अधिक विकास की गति तीव्र करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि सरकारी उद्यम भारत के आर्थिक कार्यक्रम का आवश्यक अंग है।

### **1. आर्थिक विकास की दर और सरकारी उद्यम :-**

भारत में सरकारी उद्यम का इस आधार पर समर्थन किया जाता है कि अकेला निजी क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित गति से आर्थिक विकास नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में सरकार ने जानबूझ कर विकास की ऊंची दर का जो लक्ष्य निर्धारित किया है। उसे प्राप्त करने के लिए बचत की उच्च दर प्राप्त करनी अनिवार्य थी। स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहन देकर उसे औद्योगिक विकास के लिये प्रेरित किया जा सकता है। यदि यह उपाय अपर्याप्त जान पड़े तो सरकार को एक दूसरे उपाय का सहारा लेना होगा

अर्थात् कर लगा कर अनिवार्य बचत तीव्र आर्थिक विकास के लिए बचत की उच्च दर अनावश्यक होती है। जिसका एक बड़ा भाग कर के माध्यम से अनिवार्य बचत के रूप में प्राप्त किया जाएगा। प्रोफेसर रामानाधम के शब्दों में – “साधन इकट्ठे कर चुकने पर सरकार तथा योजना आयोग जैसी नीति निर्माण करने वाली अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएँ स्वभाविक मानवीय लालसा के अधीन यह कहेंगी कि इस धन का सरकार अपनी छत्रछाया में उपयोग करे। प्रशासन के लिए इस मुसीबत से दूर रहना ही ठीक प्रतीत होता है, कि पहले तो वह निजी उद्यम को रुपये दे और फिर इस रुपये की सुरक्षा और उचित उपयोग का निश्चय करने के लिये आवश्यक प्रतिबन्ध तथा सतुलन लागू करे। ससद तथा प्रशासनिक संस्थाओं के लिये यही स्थिति श्रेयस्कर जान पड़ती है कि सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक उद्यम स्थापित किया जाए।

## **2. साधनों के आबण्टन का ढाँचा और सरकारी क्षेत्र:-**

प्रोफेसर रामानाधम के शब्दों में- सरकारी क्षेत्र के विस्तार का मुख्य कारण योजनाओं के अधीन निर्धारित साधनों के आबण्टन के ढाँचे में निहित है। प्रथम योजना में कृषि पर बल दिया गया है। किन्तु द्वितीय योजना में उद्योगों और खनन क्रियाओं पर अधिक बल दिया गया।

## **3. सरकारी उद्यमों द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना :-**

सरकारी क्षेत्र के विस्तार का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों (Regions) के सतुलित विकास की इसीलिए चेष्टा की जाती है कि क्षेत्रीय असमानता उत्तर गंभीर रूप धारण न कर लें। केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन सरकारी उद्यम उन प्रदेशों में स्थापित किये जाने चाहिये जो अल्पविकसित हैं और जिसमें स्थानीय साधन पर्याप्त नहीं हैं।

उनका एक अच्छा उदाहरण भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कायम किये इस्पात के तीन कारखाने और मद्रास में नेवेली परियोजना (Neyveli Project) के इर्द-गिर्द औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। कई बार यह अनुभव किया गया कि राज्य सरकार के पास अपने प्रदेश के विकास के लिये उचित साधन न हो, ऐसी हालत में यही उचित समझा गया कि केन्द्र सरकार ऐसे प्रदेशों में परियोजना स्थापित करे और उनके लिये वित्तीय प्रबन्ध भी करे।

#### 4. आर्थिक विकास के लिये धन का स्रोत :-

आर्थिक विकास के लिये भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सरकारी क्षेत्र आर्थिक विकास के लिये हम प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार उद्यमों से लाभ को या तो उन्हीं उद्योगों के विस्तार के लिये या अन्य उद्योगों से लाभ को या तो उन्हीं उद्योगों के विस्तार के लिये या अन्य उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि निजी उद्यम के अधीन कार्य करने वाले उद्योग भी अपने लाभ का पुन. विनियोजन (Re-investment) अधिकतर भाग को विस्तार योजनाओं में प्रयुक्त कर सकते हैं या अपने लाभ के अधिकतर भाग को विस्तार योजनाओं में प्रयुक्त कर सकते हैं। किन्तु निजी उद्यमों में लाभ हिस्सेदारी के लाभांश के रूप में घोषित किया जाता है। उससे तो जनता में आर्थिक असमानताएं ही उत्पन्न होती हैं। परन्तु सरकारी उद्यमों से प्राप्त अतिरिक्त (surplus) के लिये प्रत्यक्ष रूप में (Capital accumulation) हस्तक्षेप की जा सकती है।



## 5. समाजवादी ढंग का समाज (Socialist pattern of Society):-

समाजवादी ढंग के समाज में सरकारी क्षेत्र का विस्तार दो प्रकार से किया जायेगा। जहाँ तक उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और उनकी मात्रा इस बात का सम्बन्ध है कि वे कब तक उत्पन्न की जाये, फ्रेंच द्वारा उत्पादन का आयोजन किया जाएगा। इस लक्ष्य को निजी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्रों में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट किया गया “समाजवादी ढंग के समाज को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपनाने और आयोजित तेज विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह अनिवार्य है कि मूल तथा केन्द्रीय महत्व के सभी उद्योगों या सार्वजनिक उपयोगी में कायम (Public Utility Services) सरकारी क्षेत्र में कायम हो अन्य उद्यम भी, जिनका विकास अनिवार्य है। और जिन पर भारी मात्रा में विनियोग वर्तमान परिस्थितियों में केवल राज्य द्वारा ही किया जा सकता है, सरकारी क्षेत्र में होने चाहिये।”

भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में एक लक्ष्य यह है कि आय तथा सम्पत्ति की असमानताओं को कम किया जाए ताकि सम समाज की स्थापना हो सके। पंचवर्षीय योजनाओं में इसे आयोजन का मुख्य उद्देश्य समझा गया है, सरकारी उद्यमों का प्रयोग आय तथा सम्पत्ति के पुन वितरण के लिए लिया जा सकता है। इसके लिये निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाये जा सकते हैं (क) निजी उद्यम के अधीन इकाइयों से पर्याप्त लाभ तो निजी उद्यम कर्ताओं की जेबों में जाता है, जबकि सरकारी उद्यमों का लाभ राज्य को प्राप्त होता है। (ख) उच्चस्तरीय प्रबन्ध-कौशल उद्यमों में उच्च पदाधिकारी (Top executives) के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। (ग) सरकारी उद्यमों को ऐसी विभेदक कीमत नीति अपनानी चाहिए जिससे कि निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हो। (घ) सरकारी उद्यम में सामान्यतः कम आय प्राप्त

करने वाले कर्मचारियों की आय आसानी से उन्नत की जा सकती है। (ड०) सरकारी उद्यम सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

## 6. गैर सरकारी क्षेत्र की बुराइयाँ और सीमाएँ :-

गैर सरकारी क्षेत्र का व्यवहार और दृष्टिकोण स्वयं देश में सरकारी क्षेत्र के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कारक तंत्र रहा है। जब अमरीकी सरकार ने भारत में बोकरो पर जोर दिया तो श्री जे० आर० डी० टाटा ने जो देश में गैर सरकारी क्षेत्र के प्रबुद्ध उद्योगपतियों में माने जाते हैं। खुले रूप में यह स्वीकार किया कि गैर सरकारी क्षेत्र इस कार्य के लिए 700 करोड़ रुपये की पूँजी जुटाने में असमर्थ है यह तो ठीक है परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र की सामान्य व्यापार जोखिम उठाने सम्बन्धी अनिच्छा का क्या कारण है दूसरी योजना और उसके बाद के काल में खाद कारखाने कायम करने के लिये जारी किये गये कई लाइसेन्स गैर सरकारी क्षेत्र ने लौटा दिये जबकि देश में उर्वरक उद्योग की सख्त जरूरत थी। एक तो उत्पादन को एक कदम बढ़ाने के लिये और दूसरे उर्वरक आयात में प्रयुक्त होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत के लिये 1966-67 में शुरू हुए व्यापार प्रतिसार ने गैर सरकारी क्षेत्र को सीमेंट उद्योगों का विस्तार करने का वचन दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन हित को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया की स्थापना की। जिसके अधीन सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाया गया। औषधि उद्योग द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र में एण्टीबायोटिक्स बनाने में विफलता और उपभोक्ताओं के निर्दयी शोषण के कारण सरकारी क्षेत्र को औषधि उपयोग द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र में एण्टीबायोटिक्स बनाने में विफलता और उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिये अपने स्वामित्व में कर लेती है। भारत सरकार ने जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण बीमा करवाने वाले

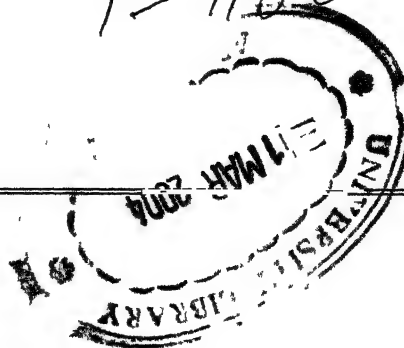
व्यक्तियों को गैर सरकारी शोषकों की लोलुपता व शोषण से बचाने के लिए किया। भारत के 20 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बैंकों की पूँजी द्वारा गैर सरकारी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक साम्राज्य स्थापित करने से रोकना था। रूग्ण सूती वस्त्र कारखानों को राजकीय स्वामित्व में लाने का कारण भी गैर सरकार की विफलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गैर सरकारी क्षेत्र न तो जनता के प्रति अपने दायित्व को समझता है, न ही न्यायोचित रूप में व्यापार चलाता है। भारत में निजी क्षेत्र के दोषपूर्ण व्यवहार का कारण यह है कि सूदखोर महाजन हाल ही के वर्षों में उद्यमकर्ता बन गये हैं, और ये औद्योगिक विकास को रोकने वाले बल के रूप में जनता के हितों को नहीं समझते।

निष्कर्ष यह है कि सरकारी क्षेत्र के विस्तार द्वारा अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं ये मुख्य उद्देश्य हैं गरीबी को दूर करना आत्मनिर्भरता की प्रगति, आय की असमानताओं में कमी, रोजगार के अवसरों का निरन्तर, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, कृषि तथा औद्योगिक विकास की गति को त्वरित करना, स्वामित्व के संकेन्द्रण (Concentration of ownership) को कम करना और निजी क्षेत्र के विस्फोट प्रभावी प्रतिकारी शक्ति के रूप में क्रियाशील होकर एकाधिकारी प्रवृत्तियों को समाप्त करना, आधुनिक तकनालॉजी द्वारा देश को स्वावलम्बी बनाना और व्यावसायिक तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कुशल श्रमिकों को तैयार करना ताकि देश को अन्ततोगत्वा विदेशी सहायता पर निर्भरता से मुक्त किये जा सके।

अध्याय तीन  
भारत के लोक उद्यमों का  
विकासात्मक अध्ययन

3777-10  
7038

T- 1182



भारतीय नियोजन पद्धति सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकाधिक विकास कार्य नीति पर आधारित रही है। स्वतंत्रता पूर्व देश की अर्थव्यवस्था का इतना अधिक दोहन हुआ था कि उसे पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना अत्यन्त दुष्कर कार्य था। उसका प्रत्येक अंग समस्याग्रस्त था। अतः सरकार ने स्वयं विकास प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का बीड़ा उठाया। देश का निजी क्षेत्र देश की आर्थिक स्थिति के सुधार में न तो सक्षम था और न ही इच्छुक, अतः सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ही विकास किया जा सकता था। वास्तव में ब्रिटिश काल में भारत का आर्थिक परिदृश्य इतना कमजोर हो गया था कि लोगों को उत्पादक गतिविधियों में विनियोग करके जोखिम उठाने की प्रवृत्ति ही समाप्त प्रायः हो गई थी। वे तो सिर्फ स्वर्ण आभूषण, कीमती रत्नों और नकद के रूप में अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के आदी हो गये थे, इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ भी नहीं थी कि वे बड़े पैमाने पर उद्योगों या व्यापार में निवेश कर सकें इन्हीं तत्वों के मद्देनजर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विकास अपरिहार्य हो गया।

हमें सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास करना है। इसे न केवल उन क्षेत्रों में विकास करना है जिसके लिए निजी क्षेत्र इच्छुक नहीं हैं या करने में असमर्थ हैं बल्कि इसे अर्थव्यवस्था के समग्र विनियोग ढाँचे को बदलने में प्रभावी कार्य अदा करना है, चाहे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप में विनियोग करे या वे विनियोग निजी क्षेत्र द्वारा किये जाएं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जिसका अधिकाधिक विस्तार हो रहा है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के एक साथ विकास की गुंजाइश है, परन्तु यदि विकास को कल्पित गति से आगे बढ़ाना है और बड़े सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी योगदान देना है, तो यह अनिवार्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र को सापेक्ष रूप से निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक गति से आगे बढ़ाना होगा।

इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया गया, जिसमें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर और एक दूसरे के पूरक बनकर देश का विकास करते हैं यद्यपि विश्व के अधिकांश विकसित देशों ने निजी क्षेत्र के अधिकाधिक विकास के आधार पर ही अपना विकास किया है, फिर भी अनेक समाजवादी देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से अपना विकास करके विश्व को चकाचौंध कर दिया। भारत के इन दोनों आर्थिक पद्धतियों—पूँजीवादी व्यवस्था तथा समाजवादी व्यवस्था के मध्य का रास्ता अपनाया और निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का मिश्रित विकास किया।

1948 और 1956 की औद्योगिक नीतियों में स्पष्टरूप से निजी और सार्वजनिक उद्यमों के कार्यक्षेत्र का विभाजन कर दिया गया था। भारी पूँजी के विनियोग वाले अर्द्धसरचनात्मक उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गयी, क्योंकि एक तो इनके लिए भारी पूँजी की आवश्यकता होती और दूसरी ओर इनमें लाभ की प्रत्याशा भी कम होती है साथ ही साथ इन उद्योगों में उत्पादन भी देर से प्रारम्भ हो पाता है। इन्हीं कारणों से निजी क्षेत्र इनमें निवेश नहीं करना चाहता था। वह तो सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और कृषि कार्य में ही अपना धन व श्रम लगाना चाहता था।

भारत में लोग उद्यमों का महत्व योजना काल में प्रारम्भ से ही बढ़ता रहा है। 1951 में जहाँ सिर्फ 5 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई अस्तित्व में थी और उनमें सिर्फ 29 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था, वहीं मार्च 2001 को इन लोक उद्यमों की संख्या बढ़कर 242 हो गयी तथा इन लोक उद्यमों में किया गया कुल विनियोग 274114 करोड़ रु० हो गया।

**तालिका - 3.1**  
**सावजनिक उद्यमों में केन्द्र सरकार का विनियोग**

वर्ष (1 अप्रैल को)	इकाइयों की संख्या	कुल विनियोग (करोड़ रु० में)
1951	5	29
1956	21	18
1961	47	948
1969	84	3897
1974	122	6237
1980	179	18150
1985	215	42673
1990	244	99329
1991	246	113896
1992	246	135445
1993	245	145587
1994	246	164332
1996	243	178628
1997	242	193121
1998	240	221984
1999	240	230140
2000	240	252745
2001	242	274114

स्रोत : भारत सरकार सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 1998-99 व योजना जुलाई 2002  
 पेज नं० 24।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया, फलस्वरूप उनकी संख्या में वृद्धि होती गयी।

वर्ष 1951 में केवल 5 उद्यम थे जिनमें मात्र 29 करोड़ रु० विनियोजित था, इनकी संख्या बढ़कर 1997 में 242 हो गयी तथा पूँजी बढ़कर 193121रु० हो गया परन्तु वर्ष 99 में इनकी संख्या बढ़कर 1997 में 242 हो गयी परन्तु विनियोग बढ़कर 230140 करोड़ हो गया जो अच्छे संकेत का सूचक है। इन सार्वजनिक उद्यमों में केन्द्र सरकार का विनियोग मार्च 2000 में 252554 करोड़ रु० हो गया जो इन उद्यमों के विकास की कड़ी का अगला कदम है।

## *विनिवेश का लक्ष्य तथा वास्तविक*

### *विनिवेश की स्थिति*

#### *तालिका-3.2*

वर्ष	विनिवेश का लक्ष्य	वास्तविक विनिवेश (करोड़ रु० में)
1990—91	2500	3038
92—93	3500	1961
93—94	2500	-48
94—95	4000	5078
95—96	7000	362
96—97	5000	455



97-98	4800	912
98-99	5000	9000
99-2000	10000	6752
2000-2001	10000	1829
2001-2002	12000	5573

स्रोत : भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2002 पेज 72

वर्ष 90-91 में विनिवेश का लक्ष्य 2500 करोड़ ₹ था जबकि वास्तविक विनिवेश 3038 करोड़ ₹ हुआ। वर्ष 9-94 में विनिवेश का लक्ष्य 2500 करोड़ ₹ था परन्तु वास्तविक विनिवेश (-48) था जो असन्तोषजनक परिणाम का द्योतक रहा है। विनिवेश के लक्ष्य में लगातार वृद्धि होती रही परन्तु वास्तविक विनिवेश में उच्चावचन की स्थिति बनी रही। वर्ष 98-99 में 5000 करोड़ ₹ के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तविक विनिवेश 9000 करोड़ का किया गया। वर्ष 99-2000 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 10000 करोड़ ₹ है। यद्यपि इस प्रवृत्ति से सरकार को तत्काल कुछ धन प्राप्त हो जाता है, जिसका वह बजट घाटे को कम करने उद्योगों का आधुनिकीकरण करने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने आदि में सदुपयोग कर सकती है।

**तालिका- 3.3**  
**लोक उद्यमों के लाभार्जन/हानि अर्जन की स्थिति**  
**(करोड़ रु० में)**

वर्ष	कुल लाभ	लाभार्जन इकाइयों द्वारा अर्जित लाभ	हानिगत इकाइया की कुल हानि
1991-92	2356	6079	3723
92-93	3271	7384	4113
93-94	4545	9768	5223
94-95	7187	12070	4883
95-96	9574	14763	5188
96-97	10286	16125	5939
97-98	13720	20279	6559
98-99	13235	22509	9274
99-2000	14331	24633	10302
2000-2001	15653	28492	12839

स्रोत : योजना जुलाई 2002 पेज न० 26

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोक उद्यमों द्वारा अर्जित कुल लाभ में निरन्तर वृद्धि हुआ है। वर्ष 91-92 में कुल लाभ 2356 करोड़ रु० हो गया इस प्रकार से कुल लाभ में वृद्धि अच्छे परिणाम का द्योतक है। लाभार्जन इकाइयों द्वारा अर्जित लाभ जो 91-92 में 6079 करोड़ रु० था बढ़कर 22509 करोड़ रु० हो गया, यह भी उत्तम परिणाम का परिचायक है परन्तु कुछ हानिगत इकाइयों के कारण लोक उद्यमों के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यदि लोक उद्यमों के

विकास का समुचित प्रबन्ध किया जाय तो निश्चय ही ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

### तालिका - 3.4

## लोक उद्यमों के लाभार्जन व हानिअर्जन इकाइयों का विवरण-

वर्ष	लाभार्जक इकाइयों	हानिगत इकाइयों	न लाभ न हानि में चलती इकाइयों
91-92	133	102	2
92-93	131	106	2
93-94	121	116	3
94-95	130	109	2
95-96	132	102	5
96-97	129	104	3
97-98	134	100	2
98-99	127	106	2
99-2000	126	105	1
2000-2001	122	111	1

स्रोत : योजना जुलाई 2002 पेज नं० 26

उपरोक्त तालिका के अनुसार लाभार्जक इकाइयों की संख्या में निरन्तर उच्चावचन की स्थिति बनी रही, वर्ष 91-92 में लाभार्जक इकाइयों की संख्या 133 थी, यह संख्या 97-98 में बढ़कर 134 हो गई। परन्तु 2000-2001 में इनकी संख्या पुनः घटकर 122 हो गयी। इसी प्रकार हानिगत इकाइयों की संख्या में भी उच्चावचन की स्थिति बनी रही, वर्ष 91-92 में जहाँ इनकी संख्या 102 थी, 97-98

मे घटकर 100 हो गई। परन्तु 98-99 में उनकी संख्या में बढोत्तरी असन्तोषजनक परिणाम दर्शित कर रहा है। न लाभ न हानि में चलने वाले इकाइयों की स्थिति में भी उच्चावचन की स्थिति बनी रही। हानिगत इकाइयों की संख्या में कमी करना अत्यन्त आवश्यक है तभी देश के लोक उद्यमों का भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा। लाभार्जन करने वाले इकाइयों की प्रबन्धन में सुधार लाकर उनके लाभदायकता में अधिक वृद्धि करने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। जिससे लोक उद्यमों के निष्पादन क्षमता में सुधार हो सके।

### तालिका 3.5

#### केन्द्रीय राजकोष में योगदान (करोड़ रु० में)

क्र०सं०	विषय	2000-01	98-99	97-98	96-97
1	केन्द्र सरकार द्वारा नियोजित पूँजी पर लाभांश व ब्याज	10895	5034 58	4146 69	3482 63
2	उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर, लाभांश कर, बिक्री कर तथा अन्य शुल्क व करों द्वारा योगदान	50083	41889 99	38145 52	35526 68

स्त्रोत : याजना जुलाई 2002 पृष्ठ 27

देश की योजना गत विकास आवश्यकताओं के लिए धन जुटाना भी सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमुख कार्य रहा है। लाभांश बटवारा, ब्याज, निगम कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं अन्य करों आदि के रूप में केन्द्रीय कोष में लोक उद्यमों ने प्रशंसनीय योगदान दिया है। राजकोष में योगदान प्रदान कर ये उद्यम

देश के वित्तीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 96-97 में कुल योगदान 39000 करोड़ रु० का दिया गया जो 2000-01 में बढ़कर लगभग 50000 करोड़ रु० हो गया। इसप्रकार राजकोष के योगदान में निरन्तर वृद्धि करके लोक उद्यमों ने सरकार के कोष में प्रमुख योगदान दिया है।

### तालिका - 3.6

#### विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ (करोड़ रु० में)

क्र०स०	विषय	2000-01	98-99	97-98	96-97
1	एफ० ओ० बी० आधार पर रामान का निर्यात	19714	14516	16203	15277
2	रायल्टी तकनीकी ज्ञान एवं सेवाओं द्वारा प्राप्त शुल्क	192	170	133	119
3	ब्याज एवं लाभांश	382	337	257	66
4	अन्य आय	4203	3804	3890	3462
	कुल	24092	18827	20483	18924

स्रोत योजना जुलाई 2000 पेज न० 25

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा अर्जन के क्षेत्र में लोक उद्यमों की स्थिति संतोषजनक है। विदेशी मुद्रा अर्जन में लोक उद्यमों में उच्चावचन की स्थिति बनी रही। वर्ष 96-97 में लोक उद्यमों द्वारा कुल 18924 करोड़ रु० अर्जित किया गया जो 97-98 में बढ़कर 20483 करोड़ रु० हो गया, परन्तु 2000-01 में इसमें पुनः गिरावट आई जो 18827 करोड़ रु० हो गया। लोक उद्यमों को विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए जिससे देश में

विदेशी मुद्रा की भरमार हो, और लोक उद्यमों की दशा में गुणात्मक सुधार हो। मुद्रा अर्जित करेगी उतना ही देश का भुगतान सतुलन पक्ष में होगा जो देश के लिए उपयोगी व हितकर होगा।

**तालिका - 3.7**  
**भारत के लोकउद्यमों का टर्न ओवर**  
**(करोड़ रु० में)**

वर्ष	टर्नओवर
91-92	133906
92-93	147266
93-94	158049
94-95	187355
95-96	226919
96-97	260735
97-98	275996
98-99	309994
99-2000	302867
2000-01	330649

स्रोत : योजना जुलाई 2002 पेज न० 26

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत के लोक उद्यमों ने काफ टर्नओवर प्राप्त किया है। वर्ष 91-92 से लगातार टर्न ओवर में वृद्धि का क्रम जारी है। वर्ष 91-92 में लोक उद्यमों द्वारा 133906 करोड़ रु० टर्न ओवर प्राप्त किया गया जो बढ़कर 2000-01 में करीब 3 गुना हो गया। लोक उद्यमों द्वारा इस प्रकार टर्नओवर प्राप्त करना अच्छे परिणाम का सूचक है लोक उद्यमों की इस प्राप्ति में अधिकाधिक वृद्धि का प्रयास करना चाहिए जिससे लोक उद्यम निरन्तर लाभार्जन कर सकें। टर्नओवर में वृद्धि करने के लिए यह परमावश्यक है कि उत्पादन व

विक्रय में निरन्तरता बनी रहे। उत्पादन में निरन्तरता बनाये रखना जरूरी होता है, जिससे टर्न ओवर अधिक से अधिक प्राप्त करके लोक उद्यम अधिकाधिक विकास व उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके।

### तालिका - 3.8

#### लोक उद्यमों की निर्यात आय (करोड़ रु० में)

वर्ष	कुल निर्यात आय
81-82	2725 78
82-83	4747 20
83-84	5532- 10
84-85	5827 22
85-86	3822 32
86-87	3941 78
87-88	4176 48
88-89	4892 32
89-90	6365 84
93-94	11872 45
94-95	13216 18
95- 96	16269 22
96-97	16385 71
97-98	20483
98-99	18827
99-2000	19714
2000-01	19714

स्रोत : योजना जुलाई 2002 पेज नं० 27

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोक उद्यमों के निर्यात आय में निरन्तर वृद्धि हुई है। निर्यात आय से अधिकाधिक मात्रा में विदेशी राजस्व की प्राप्ति

होती है और देश का भुगतान सतुलन देश के अनुकूल होता है। लोक उद्यमों की इस दिशा के अनुकूल होता है। लोक उद्यमों को इस दिशा में अधिक प्रयास करना चाहिए जिससे निर्यात आय में वृद्धि हो और देश का सतुलित विकास होता रहे।

सम्पूर्ण योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश में महत्वपूर्ण अंश रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक का कुल निवेश के आधे से अधिक रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवी तथा छठी योजनाओं में कुल विनियोग का 54%, 54%, 60%, 59%, 57.6% और 53% भाग सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया। सातवी पंचवर्षीय योजना में यह 47% पर आ गया जबकि नौवी योजना में घटाकर इसे 33% कर दिया गया। वास्तव में आठवीं पंचवर्षीय योजना तक आते-आते सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारत का निजी क्षेत्र काफी हद तक स्वावलम्बी हो गया है और देश के विकास में अधिक भागीदारी निभा सकता है।

आर्थिक विकास हेतु अधः संरचना का विकसित होना आवश्यक है। सड़क, रेल आदि परिवहन के साधन, संचार की सुविधाएँ ऊर्जा का उत्पादन तथा वितरण आदि सुविधाओं के अभाव में कृषि, उद्योग या सेवाओं का विकास असम्भव है। इन तत्वों के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान अद्वितीय रहा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का तीव्र से विकास हुआ। औद्योगीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का ही परिणाम है। लोहा व इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, भारी रसायन उर्वरक, भारी विद्युत उपकरण, कोयला, अन्य खनिज, प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योग आदि का अधिकांश विकास सार्वजनिक क्षेत्र के ही प्रयासों से हुआ है। इन विशालकाय उद्योगों के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता और लम्बी परिणाम अवधि के कारण निजी क्षेत्र की असमर्थता को सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ही पूरा किया गया है।



सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक ऐसे उद्योगों की स्थापना की गई है जिनके उत्पाद भारत को पूर्व काल में विदेशों से आयात करने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान एटीबायोटेक्स लिमिटेड आदि इकाइयों में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है।

यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य ध्येय देश की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है, परन्तु अनेक ऐसे उद्यम भी हैं, जिन्होंने निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उदाहरणार्थ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड आदि में उत्पादित वस्तुएं बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से ही नहीं की जाती, बल्कि उनका उद्देश्य जनहित होता है, इसलिए अनेक उद्यमों की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में भी की जाती है जहाँ यद्यपि उनके उपयुक्त दशाएँ उपलब्ध नहीं होती परन्तु उनकी सहायता से उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है। पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथों में संकेन्द्रित हो जाती है अतः भारत जैसे निर्धन देश में इस कुप्रथा को रोकने का काम काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र ने किया है यद्यपि देश में अनेक बड़े औद्योगिक घराने मौजूद हैं परन्तु कुल परिसम्पत्ति में उनका हिस्सा बहुत कम है।

### तालिका - 3.9

#### केन्द्रीय सार्वजनिक उद्योगों का वित्तीय निष्पादन

वर्ष	इकाइयों की संख्या	विनियोजित पूँजी	कर पूर्व सकल लाभ	कर पूर्व शुद्ध लाभ	कर पश्चात शुद्ध लाभ
91-92	237	117991	13675	4003	2355
92-93	239	140110	15957	5076	3271
93-94	240	159836	18555	6654	4544
94-95	241	162451	22630	9768	7187
95-96	239	173874	27988	14065	9878
96-97	236	202022	29399	15473	10258
98-99	235	273697	39766	19734	13235
99-2000	240	252745	25355	22037	14331
2000-01	242	274114	29544	24966	15653

स्रोत सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 98-99 व टाटा आउट लाइन  
2001-02

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उद्योगों के वित्तीय निष्पादन में निरन्तर सुधार हुआ है। वर्ष 91-92 में शुद्ध लाभ 2355 करोड़ ₹0 था। जो 2001-02 में बढ़कर 15653 करोड़ ₹0 हो गया। इस प्रकार इन उद्योगों का वित्तीय निष्पादन सन्तोषजनक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है।

## तालिका - 3.10

### सार्वजनिक क्षेत्र में क्षमता उपयोग

क्षमता उपयोग	2000-01	1998-99	1997-98	1996-97	1993-94	1991-92
75% से अधिक	144	119	118	126	115	118
50 से 75% के मध्य	33	46	37	32	59	42
50% से कम	59	69	58	56	50	50
कुल	236	234	213	214	224	210

स्रोत : योजना जुलाई 2000 पेज नं० 24

भारत के लोक उद्यमों द्वारा अपने उत्पादन क्षमता का पूर्ण सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि सभी लोक उद्यम अपने उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ हो जाते तो निश्चय ही लोक उद्यमों की स्थिति बेहतर होती। इन लोक उद्यमों द्वारा अधिकतम 75% ही उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि ये अपने उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। यदि सभी लोक उद्यम प्रयास करें तो निश्चय ही लोक उद्यम सफलता की उंचाइयों पर पहुंचने में सफल हो जायेंगे। प्रबन्धन क्षमता में भी सुधार करना पड़ेगा। तभी लोक उद्यमों द्वारा उनकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। सरकार को भी अत्याधुनिक यन्त्रों व मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। जिससे उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि हो और उत्पादन क्षमता में सुधार हो।

U. S. P.

## तालिका - 3.11

### सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर विनियोग

प0 यो0	संगठित एव खनिज उद्योग	कूटीर एव लघु उद्योग	अन्य
I	55	22	97
II	938	187	1125
III	1726	241	1967
IV	2864	243	3107
V	6888	376	7264
VI	14790	1945	16948
VII	14708	2745	22461
VIII	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	47888
IX	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	65148

स्त्रोत इकोनामिक सर्वे 87-88 व 2000-2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर विनियोग की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है। इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार निरन्तर धन की उपलब्धता बढ़ाती जा रही है। इसलिए इन उद्योगों का प्रमुख दायित्व है कि वे सरकार द्वारा विनियोजित पूँजी पर पर्याप्त लाभार्जन करे जिससे वे अपनी अस्तित्व को बनाये रखने में सफल रह सकें।

रखा गया है जिससे उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हो तथा सभी लोक उद्यम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने अस्तित्व को बनाये रखने में समर्थ कर सकें।

यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से लाभ प्राप्त करने वाले और हागि उठाने वाले उद्यमों के निष्पादन का अलग-अलग अध्ययन किया जाय तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है।

लाभ प्राप्त करने वाले उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनिया, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०, विदेश संचार निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि०, महानगन टेलीफोन निगम, इण्टरनेशनल एअर पोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया मुख्य है। जबकि घाटे में चल रहे उद्यमों में इण्डियन आयरन एव स्टील लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमि० हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमि०, दिल्ली परिवहन निगम आदि है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा कुल लाभ का 75% भाग अर्जित किया जाता है। तथा अन्य उद्यमों का लाभ बहुत कम है।

राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यमों की स्थिति तो और भी दयनीय है उनमें से अनेक स्थायी रूप से घाटा उठा रहे हैं। राज्य की सड़क परिवहन निगम राजकीय विद्युत बोर्ड राजकीय सिंचाई परियोजनाएं आदि प्रमुख घाटा उठाने वाले प्रमुख उद्यम हैं।

सार्वजनिक उद्यमों द्वारा लाभ कम अर्जित करने या उनमें घाटा होने का प्रमुख कारण उनकी अदक्षता पूँजी व समय की बरबादी गलत प्रबन्धन श्रमिकों की कामचोरी तथा अन्य प्रकार अव्यवस्थाएं हैं। जिनके फलस्वरूप इन उद्यमों का उत्पादन लागत बहुत उच्च हो जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन

उद्योगों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उत्पादन लागत को उठाया जाय और क्षमता का पूर्ण सदुपयोग किया जाय। सरकार इसके बजाय जो आसान उपाय अपनाती है। वह है इन उद्यमों के उत्पादों की प्रशासित कीमत बढ़ाना, इससे उपभोक्ताओं पर अनवश्यक बोझ पड़ता है।

सार्वजनिकक्षेत्र की इकाइयों में उत्पादन प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम दक्ष है जिससे उनका घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। ये कमियाँ अग्रलिखित हैं।

1. ये इकाइया अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही हैं। फलतः इनमें निवेशत पूँजी पर प्राप्त होने वाला प्रतिफल कम होता है।

2. ये इकाइया श्रमिकों की आवश्यकता से अधिक संख्या से बुरी तरह ग्रस्त हैं। जिससे श्रमिकों की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होती है। बहुत से श्रमिक काम करने से कतराते हैं और अधिकारियों का कुछ श्रमिकों पर निगरानी भी कम रहता है।

3. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ जिन वस्तुओं की उत्पादन करती हैं उनमें उनका एकाधिकार होता है। फलतः उनके अन्दर अपनी क्षमता में वृद्धि करने हेतु प्रतियोगी भावना उत्पन्न नहीं हो पाता।

4. ये इकाइयाँ सरकारी निर्णयों से काफी हद तक नियंत्रित एवं प्रभावित होती हैं। अतः इनके प्रबन्धक शीघ्रतापूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पाते जिससे उनकी उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

5. लोक उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमतें बाजारी शक्तियों के आधार पर नहीं बल्कि उनका निर्धारण अनेक तत्वों जैसे राजनीतिक, सामाजिक तथा जनता

की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिससे उनका लाभ कम हो जाता है।

6 इन इकाइयों में सुरक्षा तथा अन्य अनुत्पादक कार्यों पर अधिक व्यय किया जाता है जिससे उत्पादन लागत बढ़ती जाती है।

7 कर्मचारियों एवं प्रबन्धकों में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव उन्हें कामचोरी व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में मदद करती है। जिससे वे इन उद्यमों की कार्यों में रूचि नहीं लेते हैं जिससे उत्पादकता में कमी आती जाती है और इन उद्योगों का घाटा बढ़ता जाता है।

अध्याय - चार  
भारत के लोक उद्यमों में  
रुग्णता की वर्तमान स्थिति  
व रुग्णता के कारण



औद्योगिक रूग्णता की समस्या विश्वव्यापी है, परन्तु भारतीय उद्योग इस समस्या से विशेष रूप से ग्रस्त है वास्तव में आज औद्योगिक रूग्णता भारतीय उद्योगों की मुख्य समस्या बन गई है और इसका देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर अत्यन्त बुरा असर पड़ रहा है। देश में एक ओर तो विकास कार्यों के लिए वित्तीय ससाधनों की घोर कमी है वहीं दूसरी ओर इन रूग्ण इकाइयों में देश के बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का अरबों रूपया फंसा जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रूग्ण इकाई की परिभाषा इस प्रकार की है।  
 “ एक औद्योगिक इकाई जिसने बैंक के निर्माण में एक वर्ष तक नकद हानि उठाई है, वर्तमान तथा अगले वर्ष में हानि उठाने की सम्भावना है तथा जिसकी वित्तीय संरचना में असन्तुलन हो, अर्थात् वर्तमान प्राप्तियों का वर्तमान देवों से अनुपात 1 : 1 से कम हो और ऋण इक्विटी अनुपात अर्थात् कुल बाह्य दायित्वों के शुद्ध रूप से अनुपात में एक बिगड़ती हुई प्रवृत्ति हो, वह रूग्ण मानी जाएगी।

### **भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार :-**

(1) “एक रूग्ण इकाई है जो लगातार इकाई लगातार अपने आन्तरिक वित्तीय व्यवस्था करने में असफल रहती है और वित्तीय व्यवस्था के लिए बाह्य स्त्रोंतों पर निर्भर करती है।”

### **आई० डी० बी० आई० के अनुसार :-**

(२) “यदि एक संस्था अपने दायित्वों में असमर्थ है और लगातार रोकड हानि अर्जित कर रही है तो रूग्ण इकाई कहलायेगी।”

आर्थिक दृष्टि से एक उद्यम रूग्ण कहा जाता है, जब वह अपनी पूजी पर यथोचित प्रतिफल प्राप्त करने में असफल होता है मियादी ऋण देय संस्थाओं के अनुसार, एक इकाई तब रूग्ण मानी जाती है। जब निम्न में से कोई लक्षण उसमें दृष्टिगत होता है —

(1) संस्थान ऋणों के सन्दर्भ में ब्याज अथवा मूलधन के चार लगातार अर्द्धवार्षिक किस्तों की अदायगी में असमर्थ रहना।

(2) दो वर्षों की अवधि तक निरन्तर नकद हानियां या शुद्ध मूल में 50% का निरन्तर हास होना।

(3) छः महीने तक वैधानिक तथा अन्य दायित्वों के कारण बढ़ता बकाया। इस विषय पर 1985 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार रूग्ण औद्योगिक कम्पनी ऐसी औद्योगिक कम्पनी जिसका अनुज्ञापन हुए कम से कम 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया तथा नगद हानि को छोड़ दिया गया है।

इसके अलावा किसी कम्पनी की अधिकतम विशुद्ध पूजी का 50% या उससे अधिक भाग पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में नष्ट होने पर उसे आरम्भिक रूग्ण कम्पनी की श्रेणी में रखा जाएगा।

आद्योगिक रूग्णता की इस परिभाषा में निम्न कम्पनियों को शामिल नहीं किया गया है :—

- (1) वे कम्पनियाँ जिनकी स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुई है, लेकिन जिनका कार्यकाल सात वर्ष से कम रहा है
- (2) वह वित्तीय कम्पनी जिसके स्वामित्व में कोई औद्योगिक कम्पनी नहीं है।
- (3) व्यापार करने वाली कम्पनी, जिसके स्वामित्व में कोई औद्योगिक कम्पनी नहीं है।
- (4) वह कम्पनी जिसके स्वामित्व में सिर्फ लघु स्तर पर उत्पादन करने वाला अथवा सहायक उपक्रम है।

प्रारम्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ भी इस अधिनियम में शामिल नहीं थी परन्तु दिसम्बर 1991 में इस अधिनियम में संशोधन करके इन कम्पनियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।

भारत में औद्योगिक रूग्णता की समस्या किसी उद्योग विशेष तक ही सीमित नहीं है। बल्कि यह सभी उद्योगों में अपनी पहुँच बना चुका है। छोटे या बड़े सभी आकार के उद्योगों में से कुछ रूग्ण बन चुके हैं। देश के सभी राज्यों में इसका विस्तार है तथा समाज का प्रत्येक वर्ग इससे प्रभावित है। औद्योगिक रूग्णता के विषय में एक बात स्पष्ट है कि कोई भी इकाई एक दिन में पूर्णतः रूग्ण नहीं हो जाती है, बल्कि यह धीरे-धीरे एक लम्बी अवधि में पूरी होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या को इसके प्रारम्भिक चरण में ही पहचान लिया जाय और उसकी उसी समय रोकथाम की जाय ताकि इकाई पूर्णतः ध्वस्त होने से पूर्व ही पुनः शक्ति प्राप्त कर सके। इस प्रकार के कुछ प्रमुख संकेत

निम्नलिखित है जिन पर ध्यान देकर किसी भी इकाई की रूग्णता का पूर्वानुमान किया जा सकता है -

- (i) यदि किसी इकाई द्वारा दिन-प्रतिदिन के खर्चों का भुगतान करने के लिए कार्यशील पूंजी की कमी महसूस हो।
- (ii) उत्पादन तथा विक्रय में निरन्तर गिरावट आने के बावजूद भी स्टॉक एवं देनदारों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- (iii) तरल सम्पत्तियों जैसे रोकड एवं बैंक शेष, तत्काल विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ आदि में गत दो तीन वर्षों से निरन्तर कमी हो रही हो तथा अल्पकालीन दायित्वों जैसे लेनदान देय बिल आदि में इसी अवधि में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- (iv) गत दो वर्षों से इकाई के शुद्ध रोकड प्रवाह में निरन्तर कमी या हानि हो रही हो तथा भविष्य में भी इसके जारी रहने की संभावना हो
- (v) श्रमिकों को मजदूरी तथा वैधानिक बकायों के भुगतान में निरन्तर विलम्ब हो रहा हो
- (vi) गत पाँच वर्षों में इकाई को परिचालन से निरन्तर हानि हुई हो तथा भविष्य में भी इसके जारी रहने की संभावना हो।
- (vii) औद्योगिक इकाई की अक्रेषण रिपोर्ट गत दो तीन वर्षों से मर्यादित की गई हो आदि,

(viii) भुगतान के लिए सशोधनो के अभाव मे दीर्घकालीन ऋणो एव उस पर देय ब्याज में निरन्तर वृद्धि हो रही हो।

इसके अलावा उत्पादन क्षमता एव उत्पादन की मात्रा में निरन्तर गिरावट, श्रमिको की आवर्तन दर मे तेजी से वृद्धि अशो के बाजार मूल्य मे निरन्तर गिरावट आदि सकेत किसी भी औद्योगिक इकाई के चार-पाँच वर्षों के पश्चात रूग्ण हो जाने की ओर इशारा करती है।

इसके अलावा वित्त एव लेखा क्षेत्र के विभिन्न विद्वानो ने वित्तीय सूचनाओं के आधार पर अनुपात विश्लेषण तकनीक को औद्योगिक रूग्णता के पूर्वानुमान हेतु तक वैज्ञानिक एव श्रेष्ठ विधि माना है। वित्तीय अनुपातों की गणना किसी इकाई के वित्तीय विवरणे में उपलब्ध सूचनाओ के आधार पर की जाती है। विभिन्न विद्वानो ने इकाई चर विश्लेषण एव बहुचर विभेद विश्लेषण नामक तकनीको की सहायता लेकर पाँच छः अनुपात ज्ञात किये है, जो किसी औद्योगिक इकाई की रूग्णता का 5-6 वर्षों पूर्व ही पूर्वानुमान कर लेते है जैसे -

(i) ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ का कुल दृश्य सम्पत्तियों से अनुपात (कुल दृश्य सम्पत्ति = कुल सम्पत्ति - अदृश्य सम्पत्ति)

(ii) शुद्ध विक्रय का कुल दृश्य सम्पत्तियो से अनुपात।

(iii) परिचालन से प्राप्त रोकड का शुद्ध विक्रय से अनुपात

(iv) चालू सम्पत्तियों का चालू दायित्वों से अनुपात

(v) संचित लाभ का कुल दृश्य सम्पत्तियों से अनुपात

(vi) बाह्य दायित्वों का कुल दृश्य सम्पत्तियों से अनुपात इन अनुपातों की सामूहिक प्रवृत्ति के द्वारा औद्योगिक रूग्णता का पूर्वानुमान करना सम्भव है।

**तालिका 4.1**  
**औद्योगिक अस्वस्थता का विवरण**  
**अस्वस्था कमजोर इकाइयाँ**

वर्ष	बड़ी व मध्यम इकाई	लघु इकाई	कुल इकाई
दिसम्बर 1980	1401	23149	24550
मार्च 1990	2269	218828	221097
मार्च 1995	2391	268815	271206
मार्च 1996	2374	262376	264750
मार्च 1997	2368	235032	237400
मार्च 1998	2476	221536	224012
मार्च 1999	2792	306221	310081

स्रोत : टाटा सर्विसेज लिमि० स्टेटिस्कल आउट लाइन ऑफ इण्डिया

२०००-२००१ मुम्बई तालिका ८१ पेज न० ७२

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि औद्योगिक रूग्णता में तेजी से वृद्धि हुई है। बहुत से लोक उद्यम रूग्णता के शिकार लगातार होते जा रहे हैं। जिसका प्रमुख कारण प्रशासनिक अक्षमता है। जहाँ दिसम्बर 1980 में कुल रूग्ण इकाइयों की संख्या 24550 थी, उनकी कुल संख्या मार्च 99 में बढ़कर 310081 हो गयी। जो अत्यन्त ही चिन्तनीय विषय है। यदि इसी तरह रूग्णता में वृद्धि होती रहेगी तो वह दिन दूर नहीं है जब सरकार को सभी

लोक उद्यमों को निजी उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि इनकी रूग्णता के कारण सरकार पर काफी वित्तीय भार आ जाता है और सरकार के बजटीय घाटे में भी वृद्धि होती है। इसलिए सभी लोक उद्यमों का प्रमुख कर्तव्य है कि वे अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए अपने लाभार्जन में निरन्तर वृद्धि करने का प्रयास करें।

### **रूग्णता की अवस्थाएं :-**

उद्यमों में रूग्णता की विभिन्न अवस्थाएँ हैं जो निम्न हैं -

#### **(1) उपस्थित रूग्णता :-**

इस स्थिति में इकाई को लक्ष्य के पास की रूग्णता कही जाती है। यह किसी कार्यक्षेत्र में कुछ अपूर्णता के कारण हो सकता है। अवस्था की सूचनाएं - लाभ में कमी जैसे गतवर्ष की तुलना में पूर्व वर्ष की तुलना में कार्यशील पूँजी की कमी तैयार उत्पाद और कच्चे माल के इन्वेन्ट्री में वृद्धि है। यह ऐसी अवस्था है जिस पर इकाई का निदानात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए।

#### **(2) प्रारम्भिक रूग्णता :-**

यदि अवनति कार्य क्षेत्र में निरन्तर रहे। इसका परिणाम वास्तव में रूग्ण बनाता है। इस प्रकार की रूग्णता की स्थिति प्रारम्भिक रूग्णता कही जाती है विस्तृत रूप से इस स्थिति में निम्न लक्षण दिखाई देती हैं -

(अ) पिछले वर्ष में पूँजी कमी और वर्तमान वर्ष में अनुमानित पूँजी में कमी।

(ब) वर्तमान अनुपात स्थिति का क्षय पिछले वर्ष की तुलना में

(स) पहले से पूर्वानुमानित सम्पत्ति में कमी और ऋण अंश श्रेणी में भी कमी की आशा करना।

यह ऐसी स्थिति है जहाँ वित्तीय सस्थायें और उद्यमी को एक साथ बैठना चाहिए और प्रारंभिक रूग्णता के कारणों का विस्तृति परीक्षण करने के बाद कार्य योजना पर निर्णय लेना चाहिए।

### **रूग्णता :-**

यह ऐसी स्थिति है जहाँ इकाई रूग्ण जो जाती है और यह निम्न विशेष कारणों से है -

- (अ) उपरोक्त वर्णित कार्यरत क्षेत्र असक्षम होगी।
- (ब) पिछले वर्ष नकद हानियों और वर्तमान में भी हो
- (स) करेन्ट अनुपात 1 से कम हो

राज्यों में भी रूग्ण इकाइयों की संख्या काफी अधिक है सभी राज्यों को अपने रूग्ण इकाइयों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए जिससे सरकार पर कम से कम वित्तीय बोझ पड़े और सभी लोक उद्यम निरन्तर चलते रहे, नहीं तो सरकार रूग्ण इकाइयों को निजी उद्योगपतियों के हाथों में सौंप सकती है।

राज्य के रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या में सदैव उच्चावचन बना रहा। बड़ी तथा मझोली बीमार इकाइयों की संख्या विभिन्न राज्यों में अलग-अलग रही। उत्तर प्रदेश में बड़ी तथा मझोली बीमार इकाइयों की संख्या मार्च 1999 में 171 थी जो कुछ राज्यों की अपेक्षा कम तथा कुछ राज्यों की अपेक्षा अधिक था। इसी प्रकार बड़ी तथा मझोली कमजोर इकाइयों की संख्या 38 थी जो कुछ राज्यों की अपेक्षा कम तथा



कुछ राज्यों की अपेक्षा अधिक था। इसी प्रकार छोटी इकाइयों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में 35,998 थी जो कुछ राज्यों की अपेक्षा कम तथा कुछ राज्यों की अपेक्षा अधिक था। इस प्रकार रूग्ण इकाइयों की इतनी विशाल संख्या चिन्ता का विषय बना हुआ है।

## तालिका 4.2

**रूग्ण इकाइयों में अवरोद्ध राशि (करोड़ ₹0 में)**

वर्ष	वृहद एवं मध्यम	लघु इकाई	कुल
दिसम्बर 1980	1502	306	1809
मार्च 1990	6926	2427	9353
मार्च 96	10027	3722	13749
मार्च 97	10178	3609	13787
मार्च 98	11825	3857	15682
मार्च 99	15150	4313	19483

स्रोत . टाटा सर्विसेज लिमिटेड स्टैटिस्टिकल आउट लाइन ऑफ इण्डिया 2000-2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोक उद्यमों की अधिकाधिक राशि रूग्ण इकाइयों में अवरोद्ध है। जिसके कारण ये पूँजी का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इन इकाइयों में दिसम्बर 80 में कुल अवरोद्ध बैंक पूँजी 1809 करोड़ ₹0 थी। जो वर्ष 99 में बढ़कर लगभग 15 गुना हो गई। इस प्रकार ये इकाइयाँ अपनी पूँजी का पूर्ण उपयोग करने में अपने को असमर्थ पा रही हैं। जिससे ये बीमार होती जा रही हैं। इन्हें अपनी पूँजी का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए तभी ये उन्नति कर सकते हैं। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब सरकार को मजबूरन इन इकाइयों को बन्द कर देना पड़ेगा। अथवा निजी उद्योग पतियों के हाथों में सौंपना पड़ेगा।

### तालिका 4.3

बैंकों की बकाया राशि (करोड़ रु० में)

वर्ष	बड़ी एवं मध्यम इकाई	लघु इकाई	कुल
मार्च 90	6926	2427	9353
मार्च 93	9691	3443	13134
मार्च 94	10015	3680	13695
मार्च 95	10192	3547	13739
मार्च 96	10027	3722	13749
मार्च 97	10178	3609	13787
मार्च 98	11825	3857	15782
मार्च 99	15150	4313	19463

स्रोत : टाटा सर्विसेज लिमि० आउट लाइन 2000-2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोक उद्यमों पर बैंकों की बकाया राशि की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। इन लोक उद्यमों में बैंकों से बहुत सा कर्ज लिया है। इन लोक उद्यमों पर मार्च 90 में कुल बैंकों की बकाया राशि 9353 करोड़ रु० था जो मार्च 99 में बढ़कर 19463 करोड़ रु० हो गया, जो इन लोक उद्यमों के लिए चिन्ताजनक विषय है। इन लोक उद्यमों को अपने निष्पादन में सुधार करना चाहिए और बैंकों की बकाया राशि का यथाशीघ्र भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे ये अपने

अस्तित्व को बनाये रखने में समर्थ हो सके और बैंकों द्वारा इनको प्रदान की जाने वाली सुविधाएं बन्द न करनी पड़े।

## **भारत के लोक उद्यमों में रूग्णता एवं अन्य समस्याएँ**

लोक उद्यम किसी भी देश की आधारशिला है। आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लोक उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितयों इस प्रकार है कि लोक उद्योगों के समुचित विकास के बिना देश उन्नति की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकती। व्यवहार में लोक उद्यमों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो निम्न लिखित है—

### **(अ) वाह्य कारण :-**

लोक उद्यमों में रूग्णता को कई वाह्य कारण प्रभावित करते हैं जो निम्न है —

(१) अनेक औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति अनियमित है। प्रायः आयातित कच्चे माल का उपयोग करने वाली इकाइयों को उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम कच्चे माल की कमी के कारण अस्त-व्यस्त हो जाते हैं और औद्योगिक इकाइयों को हानि उठानी पड़ती हो। कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति से उत्पादन कार्य अत्यधिक अवरुद्ध होता है।

(२) देश में बिजली की आपूर्ति आज भी आवश्यकता से काफी कम है जिस कारण बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों के सामान्य रूप से काम करने में

रूकावट आती है। इन इकाइयों को 8-10 घण्टे तक विद्युत चाहिए परन्तु बीच में विद्युत में कटौती के कारण 6-7 घण्टे ही विद्युत उपलब्ध हो पाती है जिससे काम में रूकावट होती है।

(3) औद्योगिक अस्वस्थता पर सरकारी नीति का भी काफी प्रभाव पड़ता है जैसे - आयात, निर्यात, लाइसेंसिंग, करारोपण आदि के बारे में सरकारी नीति बदलने से सम्भव है कि स्वस्थ औद्योगिक इकाइयाँ अस्वस्थ हो जाएँ उदाहरण के लिए, किसी वस्तु के बारे में उदार आयात नीति से उस वस्तु या उसकी स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों को बहुत नुकसान हो सकता है, इसी तरह अन्य क्षेत्रों के लिए भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। लाइसेंसिंग नीति में भी अचानक परिवर्तन से कई उद्यमों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(4) कभी - कभी वस्तुओं की मांग में कमी के कारण बहुत अधिक मात्रा में बिना बिका हुआ माल बच जाता है। जिस कारण औद्योगिक इकाइयों को हानि उठानी पड़ती है। अनेक मंहगे उत्पादों की नियमित माग बहुत कुछ क्रेताओं को उपलब्ध साँख सुविधा पर निर्भर होती है यदि साँख पर नियन्त्रण लगा देने के कारण खरीददारों के लिए वित्त की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं होता है तो इन वस्तुओं की मांग गिर जाती है यह प्रक्रिया देर तक चलने से उत्पादकों के पास माल स्टॉक जमा होने लगते हैं और उन्हें अधिक हानि होती है। इसके फलस्वरूप सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयाँ अस्वस्थ इकाइयों की श्रेणी में आने लगती हैं।

(5) उद्यमों में रूग्णता को प्रभावित करने वाले निम्न आन्तरिक कारण भी हैं—

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विश्लेषण करने पर उनके लाभ/घाटे सम्बन्धी आकड़ों से पता चलता है कि या तो इनमें लाभ की मात्रा बहुत ही कम है या वे घाटे में ही चल रहे हैं। भारी घाटे वाले उद्यमों में राष्ट्रीय बिजली बोर्ड और सिचाई परियोजनाएँ हैं।

केन्द्र सरकार के उद्यमों ने 1980-81 में 203 करोड़ रुपये के घाटे के विरुद्ध 1987-88 में 2060 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। इससे समग्र रूप में उन्नति का संकेत मिलता है परन्तु कुल लाभ का 65% पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा केवल तेल की कीमतों में वृद्धि करके कमाया गया। अतः सरकार की प्रत्येक घाटे वाली कम्पनी का मूल रूप से अध्ययन करना चाहिए। राज्यों में लगातार घाटे दिखाने वालों में सिचाई एवं बहुददेशीय परियोजनाओं में हानि की मात्रा बढ़कर 1989-90 में 1917 करोड़ रु० बिजली बोर्डों की 4104 करोड़ रुपये राज्य सड़क परिवहन को 359 करोड़ रु० हो गयी थी। राज्य सरकारों के उद्यमों का समग्र घाटा जो 1984-85 में 1819 करोड़ रु० था बढ़कर 1989-90 में 6174 करोड़ हो गया। यह परिस्थिति अच्छी नहीं है अतः देश में सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन की समीक्षा आवश्यक है। वर्ष 98-99 में लोक उद्यमों ने कुल 9274 करोड़ रु० हानि हुई।

(ii) सरकारी उद्यमों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनमें अधिपूजीयन विद्यमान है या परियोजनाओं में अदा-प्रदा अनुपात प्रतिकूल है स्टडी टीम ने अनेक सरकारी कम्पनियों हैवी इंजीनियरिंग का कारपोरेशन, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स आदि में अधिपूजीयन की ओर संकेत किया। स्टडी टीम के अनुसार अधिपूजीयन के मुख्य कारण हैं, आयोजन का अभाव विलम्ब से विनिर्माण और अनावश्यक व्यय अतिरिक्त मशीनी क्षमता, परियोजनाओं का अलाभकर स्थिति-निश्चयन मकान आदि सुविधाओं को उदारता के साथ उपलब्ध कराना आदि। अधिपूजीयन के कारण वित्त का समुचित उपयोग नहीं हो पाता तथा पूँजी का अनुप्रयोग होता है जो लोक उद्यमों के सामक्ष वित्तीय संकट के रूप में विद्यमान हो जाता है।

(iii) सरकारी उद्योगों में आवश्यकता से अधिक मानव शक्ति का प्रयोग किया जाता है। श्रमिकों की तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव है। सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों को विशेष सुविधाओं और प्रोत्साहनों के न मिलने से वह उद्यमों की नौकरियों स्वीकार कर लेते हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव शक्ति आयोजन घटिया किस्म का हैं लोक उद्यमों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। जिसके परिणामस्वरूप मानव शक्ति का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। श्रमिकों पर अधिक धन व्यय करने के कारण आर्थिक क्षति भी वहन करना पड़ता है।

(iv) सार्वजनिक उद्यमों द्वारा उत्पन्न कीमते पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है। जिससे लगता है कि सरकार का उद्देश्य इस सम्बन्ध में एकाधिकारी स्थिति का प्रयोग कर अधिक लाभ कमाना है। इसे जनता पर अप्रत्यक्ष कराधान माना जा सकता है। अतः सरकार को चाहिए कि तकनीकी उन्नति द्वारा उत्पादन लागत को कम करके प्रशासित कीमतों को बढ़ाने के उपाय का कम प्रयोग करे क्योंकि सामान्य जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कीमत का निर्धारण केवल कीमत द्वारा जनहित को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है तभी दोषपूर्ण कीमत नीति पर समुचित नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

(v) अनेक छोटे-छोटे उद्यमकर्ता बिना सोचे-समझे ही मशीनें खरीद लेते हैं तथा उत्पादन की तकनीक का चुनाव कर लेते हैं। यदि ये मशीनें पुरानी हों तो उद्यमकर्ता का सम्पूर्ण उत्पादन कार्य असन्तुलित तथा उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। और उत्पादन करने वाली इकाइयों को लागत और कीमत की दृष्टि से असुविधा होती है। पुराने और दोषपूर्ण मशीनों से उत्पादन लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। लक्ष्य पूर्ण न होने पर विक्रेताओं को सन्तुष्ट भी नहीं किया जा सकेगा। जब विक्रेता संतुष्ट नहीं होंगे तो भविष्य में आदेश भी नहीं प्राप्त होगा। जिससे मांग में कमी आयेगी।

6. विश्व के गलाकाट प्रतियोगिता को देखते हुए विकसित देशों द्वारा नये तकनीकों का प्रयोग करके उद्योगों को उन्नति की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा अब भी पुरानी तकनीकों

और मशीनों से उत्पादन किया जाता है। जिससे उत्पादन में कमी होना सुनिश्चित है। यहां के प्रबन्धक नये तकनीको से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। उन्हें यह नहीं ज्ञात है कि नये विधियो व तकनीको को किस प्रकार प्रयोग करे। भारत देश में उत्पादित मशीने तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। जिससे उनके द्वारा तीव्र गति से कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों को तीव्र गति से कार्य व उत्पादन करने वाली मशीनों का आविष्कार करना चाहिए, जिससे देश में उत्पादन कार्य तेजी से सम्भव हो सके। यदि उत्पादन कार्य तीव्र व अधिक मात्रा में किया जायेगा तो उपभोक्ताओं के माग को आसानी से पूर्ण करके अधिकाधिक लाभार्जन किया जा सकता है। और जनता में सन्तुष्टि की भावना का भी तीव्र गति से विकास सम्भव हो सकेगा।

7. विश्व के अन्य देश उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यथासम्भव आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन करते रहते हैं। जिससे उनका उद्योग न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके लाभार्जन में वृद्धि कर सके। परन्तु भारत में लोक उद्यमों को सरकारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर अपने परियोजनाओं को निर्जन एवं पिछड़े स्थानों पर स्थापित करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएं वहां स्थापित हो जाती हैं, जहां पर कच्चे माल व सरचनात्मक सुविधाओं का पर्याप्त अभाव रहता है। तथा अन्तिम उत्पाद के लिए बाजार भी दूर होने की परिस्थिति में उद्यम को अतिरिक्त लागत व्यय करनी पड़ती है। जिससे लाभदायकता समाप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को लोक उद्यमों पर अधिक राजस्व व्यय करना पड़ता है। जो सरकार पर अधिक भार हो जाता है। और यही



अधिभार सरकार पर बोझ हो जाता है। लोक उद्यमों के स्थान निर्धारण में राजनैतिक हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोक उद्यमों की स्थापना ऐसे स्थानों पर करवाते हैं, जहां उनका निजी लाभ निहित हो। वे जनता व सरकार के लाभ पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। यहां पर जनता के सुख-सुविधाओं का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। परन्तु राजनीतिज्ञ गण को केवल अपना ही स्वार्थ दिखता है। इसलिए राजनीतिज्ञों को लोक उद्यमों की स्थापना में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

8 नये-नये तकनीकों एवं विधियों के खोज के कारण लोक उद्यमों के परियोजनाओं में दिन-प्रतिदिन परिवर्तन इस उद्देश्य से किया जाता है कि इनकी लाभार्जन क्षमता में वृद्धि हो, इन नये परियोजनाओं को उपयोग में लाने के लिए अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता पड़ती है जिसकी पूर्ति बजट के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार बजट का अनुचित उपयोग होता है। दिन-प्रतिदिन नये-नये तकनीकों के खोज के कारण लोक उद्यमों को अपनी योजनाओं में भी परिवर्तन करना पड़ता है। यदि समय के साथ इसमें परिवर्तन न किया जाय तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में लोक उपक्रम सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पायेंगे।

9. लोक उद्यमों के कर्मचारियों को इनके कार्यानुसार भुगतान नहीं किया जाता मजदूरी के भुगतान में अत्यधिक भिन्नता है। उच्च पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अधिक वेतन और कार्मिकों को कम वेतन के भुगतान के कारण श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त रहता है। निजी उद्यमों में वेतन अधिक

प्रदान करने के कारण लोक उद्यम के श्रमिक निजी उद्यमों के तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। निजी उद्योगों के श्रमिकों द्वारा अधिक निष्पादन करने पर प्रेरणात्मक बोनस दिया जाता है। जबकि लोक उद्यमों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, जबकि श्रमिक किसी भी उद्यम के प्राण होते हैं उनके अभाव में पूरा उद्यम ही निष्प्राण रहता है। मशीन संचालन से लेकर उत्पादन तक का सभी कार्य श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है। उनको मेहनत के अनुसार पारिश्रमिक अवश्य मिलनी चाहिए। जिससे उत्पादन कार्य में किसी प्रकार का बाधा न उत्पन्न हो।

10 लोक उद्यमों की स्थापना के विषय में सरकारी नीतियों का पालन करना आवश्यक है। सरकारी नीतियों के पालन के कारण ही कभी-कभी लोक उद्यमों में संसद सदस्यों के द्वारा संसद में अनावश्यक प्रश्नों को उठा करके उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है। जिससे उनका विकास कार्य अवरुद्ध हो जाता है। जब संसद में इनके बारे में प्रश्न उत्पन्न किया जाता है तो इन उद्यमों को उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए अनावश्यक आकड़ों को एकत्रित करके उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करके एक निश्चित समय के भीतर संसद में उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। जिससे इन उद्यमों पर अनावश्यक कार्य बोझ बढ़ जाता है। लोक उद्यमों के दैनिक कार्यों में संसद सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण कठिनाई उत्पन्न होती है इसलिए संसद सदस्यों को इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

11 कोई भी उद्योग बिना उचित नियोजन के सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुँच सकता। नियोजन ही सफलता की कुंजी है। लोक उद्यमों में

कुशल विशेषज्ञ के अभाव में आन्तरिक नियोजन, निगम नियोजन, वार्षिक योजना एवं भावी योजना तैयार नहीं किया जाता जिससे एक सुनियोजित ढंग से कार्य सम्पादित नहीं होता और लोक उद्यम उचित नियोजन के अभाव में लाभ के बजाय हानि की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नियोजन भावी कार्यक्रम का पूर्वानुमान है, यह सफलता की प्रथम सीढ़ी है। सुनियोजित योजना के अभाव में पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त रहती है। सर्वप्रथम लोक उद्यमों को दोषपूर्ण आन्तरिक नियोजन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिसमें निगम योजना, वार्षिक योजना एवं भावी योजनाओं पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए, यह प्राथमिक कार्य है। यह उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसको श्रमिक प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। प्रबन्धकगण भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को दिशा निर्देश प्रदान करते रहते हैं जिससे वे दिशाहीन न हो व उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके उद्यम को अधिकाधिक लाभान्वित करें।

12 लोक उद्यमों में उच्च अधिकारियों व प्रमुख कर्मचारियों के नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसके कारण योग्य अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाती। योग्य कर्मचारी किसी भी उद्यम की आधारशिला होते हैं यदि नींव ही कमजोर होगा तो पूरा उद्यम चरमरा जायेगा। अयोग्य अधिकारियों के कारण आदेशों का कर्मचारियों के बीच उचित संयोजन न होने से पूरी व्यवस्था ही संदेह के घेरे में रहता है। लोक उद्यमों में रिक्त पदों को भरने के लिए जब भी आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है तो आवेदकगण राजनीतिज्ञों से सम्पर्क बनाकर उन पदों पर

नियुक्ति के लिए प्रयासरत होते हैं। जिस व्यक्ति की नेताओं से अच्छा सम्बन्ध होता है उनकी नियुक्ति के लिए नेताओं द्वारा लोक उद्यमों पर दबाव डाला जाता है। मजबूरन लोक उद्यमों को इन नेताओं के आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। जिसके परिणाम स्वरूप उच्च पदों पर अयोग्य व अकुशल कर्मचारी की नियुक्ति हो जाती है जो उचित रूप से प्रबन्ध नहीं कर पाता व कर्मचारियों को भी पूर्णतया नियन्त्रित नहीं कर पाता जिससे पूरे लोक उद्यम में कर्मचारियों के मध्य सदेह का वातावरण बना रहता है व उत्पादन कार्य बाधित होता है और उपक्रम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं और धीरे-धीरे उद्यम हानि अर्जन करने लगते हैं जो कई वर्षों तक चलता रहता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह उद्यम रूग्णता की स्थिति में पहुँच जाता है।

13 लोक उद्यमों के विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे उत्पादन की क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। श्रमिक व नियोक्ता के बीच विवादों को मिटाने के लिए श्रमिक संघ की स्थापना श्रमिकों द्वारा की जाती है। परन्तु वर्तमान समय में लोक उद्यमों के श्रमिक संघ राजनीति से प्रेरित होते हैं और अपने व्यक्तिगत लाभ की ओर अधिक ध्यान देते हैं। जिससे लोक उद्यमों के विकास की प्रक्रिया में ये हड़तालें, काम रोकों आन्दोलन आदि के माध्यम से बाधा पहुँचाने का काम करते हैं। जबकि लोक उद्यमों में उनके बीच मधुर संबंध स्थापित होना चाहिए और किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होने पर उसे आपस में समझौता करके निपटाना चाहिए।

13 देश में स्थित रूग्ण इकाइयों के कारण भी बहुत सी समस्या उत्पन्न होती है। लोक उद्यमों द्वारा जिन रूग्ण इकाइयों को अपने हाथ में लिया गया है उनकी उत्पादन तकनीक तथा उपलब्ध सुविधाएँ अब अप्रचलित हो गयी हैं। इसलिए लोक उद्यमों के समक्ष इनके आधुनिकीकरण तथा बहुविधिकरण की समस्या है। इसके लिए उन्हें पर्याप्त वित्तीय साधन की आवश्यकता है। क्योंकि इन कार्यक्रमों को समय से न लागू करने के कारण इनके द्वारा उठाये जाने वाली हानि बढ़ती जा रही है। तथा लोक उद्यमों की वित्तीय स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। एकत्रित हानि, उत्पाद माग का अभाव, विक्रय क्षमता में कमी आदि के कारण इनकी तरलता स्तर निम्न स्तर पर पहुँच गयी है। उच्च प्रबन्धकीय चातुर्य तथा प्रयासों के दृष्टिकोण से रूग्ण इकाइयों का प्रबन्धन एक समस्या के रूप में उभरी है। लोक उद्यमों द्वारा अनुगृहीत रूग्ण इकाइयों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है, और जो भी है वह कार्यकुशलता की दृष्टि से अनुपयुक्त है। लोक उद्यमों के समक्ष समस्या यह है कि आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की छटनी किस प्रकार की जाय अथवा उत्पादन कुशलता की दृष्टि से उन्हें किस प्रकार सार्थक बनाया जाय। कुछ लोक उद्यमों की बाजार छवि अच्छी न होने के कारण, उत्पादन स्तर में लगातार गिरावट, लगातार हानि अर्जन तथा ऋण अनुपलब्धता, ब्याज का भारी बोझ, पुरानी मशीनरी एवं पुरानी तकनीकी का प्रयोग आदि के कारण मजबूरन सरकार को उन्हें बन्द करने के लिए सोचना पड़ रहा है।

अध्याय पांच

इलाहाबाद जनपद के प्रमुख

रुग्ण लोक उद्यम-

बी० पी० सी० एल० व टी० एस० एल०

का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन

## इलाहाबाद जनपद का सामान्य परिचय

प्राचीन काल में इसका नाम प्रयाग था, यह देवताओं की नगरी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का पवित्र संगम पूरे विश्व में विख्यात है। जिसके पावन तट पर प्रत्येक बारहवें वर्ष कुम्भ का मेला लगता है। इस पावन पर्व पर देश-विदेश के व्यक्ति आकर संगम के पवित्र तट पर स्नान करके परम आनन्द की अनुभूति करते हैं। अकबर ने अपने शासकाल में अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा।

### स्थिति और सीमाएं :-

उ० प्र० राज्य में स्थित इला० जनपद 24°47' और 25°47' अक्षांश उत्तर तथा 80°9' और 82°21' देशान्तर पूर्व के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 101 किमी० तथा पूर्व से पश्चिम तक इसका लम्बाई 117 किमी० है। इला० के पूर्व में वाराणसी, दक्षिण-पूर्व में मिर्जापुर, दक्षिण में म० प्र० राज्य, दक्षिण-पश्चिम में जिला बोंदा और पश्चिम में जिला फतेहपुर स्थित है। इस जिले की उत्तरी सीमा पर प्रतापगढ़ और उत्तर पूर्व में जौनपुर जिला है और गंगा नदी लगभग 35 किमी० की दूरी तक प्रतापगढ़ जिले को इस जिले से पृथक् करती है।

### क्षेत्रफल और जनसंख्या :-

इलाहाबाद जनपद का कुल क्षेत्रफल 7254 वर्ग किमी० है। इसके में वर्ष प्रतिवर्ष में थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। क्योंकि यहां की प्रमुख नदियां अर्थात् गंगा और यमुना विशेषतया गंगा अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे इलाहाबाद जनपद का क्षेत्रफल प्रत्येक वर्ष घटती बढ़ती

रहती है। 2001 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद की कुल जनसंख्या लगभग 60 लाख है।

### **स्थलाकृति :-**

इलाहाबाद जनपद को तीन प्राकृतिक भागों अर्थात् गंगा पार का मैदान, दोआब— यह भूभाग उत्तर में गंगा और दक्षिण में यमुना नदियों के बीच स्थित है, तथा यमुना पार का मैदान में विभाजित किया जा सकता है जिसका सृजन गंगा और इसकी सहायक नदी यमुना द्वारा हुआ है।

### **जलवायु:-**

इस जिले की जलवायु में विभिन्नता पायी जाती है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु लम्बी और गर्म होती है। वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु काफी सुहावना होता है। शीत ऋतु नवम्बर से प्रारम्भ होकर फरवरी तक रहता है तत्पश्चात् ग्रीष्म ऋतु आती है जो जून के मध्य तक रहती है उसके पश्चात् दक्षिण-पश्चिम में मानसून के आने पर वर्षा प्रारम्भ होती है और यह वर्षा ऋतु सितम्बर के अन्त तक रहती है।

जिले में राज्य के वन विभाग के अधीन 15801 हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं। जिसमें से 10701 हेक्टेयर वन क्षेत्र तहसील मेजा में और 5100 हेक्टेयर वन क्षेत्र तहसील करछना व बारा में है। तहसील मेजा व परगना बारा की पथरीली भूमि में वेर, तेन्दु, जामुन, आम, महुआ, सलई, और बास के झुण्ड पाये जाते हैं। तहसील करछना के दक्षिणी भूभाग में बबूल और मन्दार के वृक्ष पाये जाते हैं।



## भौमिकी :-

इस जनपद में सामान्य रूप से पाये जाने वाले खनिज उत्पाद कौंच, बालू, इमारती पत्थर, ककड, ईंट बनाने की मिट्टी व रेह, काच का बालुका, उत्तरी भारत में अधिकांश काच बनाने वाले कारखानों की आवश्यकता पूर्ति यहीं से होती है। रेह गंगा पार के भू-भाग में सफेद पपड़ी के रूप में पाया जाता है। रेह से सोडा ऐस निकाला जाता है जिसका उपयोग साबुन और काच बनाने के लिए तथा खारा पानी को मीठा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रगाई उद्योग तथा गंधक निकालने में भी किया जाता है।

## इलाहाबाद जनपद में औद्योगिकरण हेतु प्रमुख योजनाएं

### 1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम :-

यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में प्रारम्भ किया गया था। इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में जारी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पता लगाये गये ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने के लिए समर्थ बनाना है। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी डी० आर० डी० ए० को उपलब्ध करायी जाती है।

इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित होने वाले परिवारों में कम से कम 50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के होने चाहिए, लाभार्थियों में कम से कम 40% महिलाएं तथा 3% शारीरिक रूप से विकलांग लोग लिए

जाने चाहिए। कार्यक्रम प्रारम्भ से लेकर अब तक कुल 495 लाख से अधिक परिवारों को सहायता दी जा चुकी है।

### **जवाहर रोजगार योजना :-**

सातवी योजना के अन्तिम वर्ष में एक अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम नामक दोनों कार्यक्रमों का विलय करके जवाहर रोजगार योजना नामक एक बड़ा ग्रामीण रोजगार प्रारम्भ किया गया। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले पुरुष तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजन करना है। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को लक्ष्य बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और मुक्त बधुआ मजदूरों को प्रथमिकता दी गयी। रोजगार के 30% अवसरों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। योजना पर होने वाले व्यय को केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा 80:20 के अनुपात में वहन किया जाता है।

### **इलाहाबाद जनपद के उद्योग :-**

प्राचीन समय से ही इलाहाबाद शहर एक आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई था। जहाँ पर अपनी आवश्यकतानुसार वस्त्र, कृषि यंत्र तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। चीनी यात्री फाह्यान ने जो पाँचवी शताब्दी के प्रारम्भ में प्रयाग आया था लिखा है कि प्रयाग के पातालपुरी मन्दिर के उत्तर तथा पश्चिम की ओर दुकानों की 15 कतारे बनी हुयी थी। इस व्यापारिक केन्द्र पर देश के दूर-दूर स्थानों से हजारों ग्राहक आते थे यहाँ अच्छे कपड़े, सोने, चाँदी, ताबे, तथा पीतल के बर्तन, बहुमूल्य दुर्लभ रत्न, हाथी दाँत एवं खुदी हुई चीजें, चन्दन की लकड़ी, संगमरमर,

रत्नाभूषण, और आभूषण तथा मसाले, फल तथा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बिकने आते थे। अरबी यात्री अलबरूनी जो ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारम्भ में इलाहाबाद आया था उसने अपने यात्रा वृत्तान्त में लिखा है कि इलाहाबाद एक वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्र है उसने यह भी बताया था कि यहाँ एक बड़ा तथा विकसित नौका उद्योग है जिसमें 20000 व्यक्ति काम करते हैं एवं प्रति वर्ष 10000 से 12000 तक विभिन्न प्रकार की नावे तैयार की जाती हैं, और लगभग 20000 हजार व्यक्ति प्रस्तर शिल्प उद्योग में लगे हुए हैं।

मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में इलाहाबाद कालीन उद्योग का प्रमुख केन्द्र बन गया था। जो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही समाप्त हो गया। अंग्रेजों के अधीन विदेशी व्यापार से प्रतियोगिता में हथकरघा व्यवसाय को बड़ी हानि उठानी पड़ी और उत्पादन बन्द हो गया। मुख्यतया स्थानीय उत्पादकों को उनके व्यवसाय में हतोत्साहित करने की अंग्रेजों की नीति के कारण देशी उद्योग की हालत उत्तरोत्तर गिरती गयी जिसके फलस्वरूप अधिकाधिक लोगों को अपना पेशा छोड़कर कृषि कार्य अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, तथापि 1881 में सूती उद्योग में 36506 लोहा उद्योग तथा इस्पात उद्योग में 4360 इमारत बनाने के व्यवसाय में 2860 तथा छपाई उद्योग में 729 व्यक्ति लगे हुए थे इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के उद्योग जैसे वाद्य यन्त्र तैयार करने छपाई तथा चित्र बनाने पत्थरों की नक्काशी तथा मूर्ति निर्माण खेल का सामान डिजाइनें तथा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, हाथी दात, लाख, खाल तथा पंख बनाने के उद्योग, कांच का सामान, नमक एवं सोने, चांदी तथा कीमती पत्थरों के आभूषण बनाने में 107454 व्यक्ति कार्यरत थे। ये औद्योगिक इकाइयां धीरे-धीरे बन्द होने लगीं क्योंकि 1865 में रेल प्रणाली आरम्भ किये जाने तथा बाजारों में सस्ता

विदेशी माल अधिक मात्रा में आने लगा 1914-18 में प्रथम विश्व युद्ध के समय अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से कुछ स्थानीय उद्योग प्रारम्भ किये गये। और इलाहाबाद पुनः एक औद्योगिक केन्द्र बन गया।

1930 के दशक की आर्थिक मंदी के कारण कीमते गिर गयी और लाभ में कमी के कारण उद्योगपतियों को अपनी औद्योगिक इकाइया बन्द कर देनी पड़ी। 1939-45 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कीमते पुनः बढ़ीं और कपड़ा, लाख की चूड़िया, फर्नीचर, धातु का सामान तथा खाद्य पदार्थ निर्मित करने वाले उद्योग पुनः शुरू हो गये तथा औद्योगीकरण में पुनः तेजी आयी और वर्ष 1957 में नैनी में एक विशाल औद्योगिक केन्द्र की स्थापना की गयी। नैनी में लोक उद्यमों की स्थापना से पूरे इलाहाबाद में लोक उद्यमों का तीव्र गति से विकास हुआ। जनपद में गत वर्षों में औद्योगिक विकास कार्य तेजी से हुआ, लेकिन वह केवल नैनी व फूलपुर के नगरीय क्षेत्रों में ही केन्द्रित होकर रह गया। जनपद में औद्योगिक आस्थानों की संख्या वर्ष 2000-2001 में 7 थी। शेडों की संख्या आबटित 41 तथा कार्यरत 28 था। प्लांटों की संख्या आबटित 219 तथा कार्यरत 79 था। रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या 230 तथा उत्पादन 3735 हजार करोड़ रु० था। नैनी इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स के लिए 2800 एकड़ भूमि अधिगृहित की गयी है। अब तक 2000 एकड़ भूमि का आबटन हो चुका है। नैनी श्रमिक समस्या होने के कारण छोटे-छोटे उद्यमी हतोत्साहित हो रहे हैं। अतएव जनपद में वृहद उद्योगों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

इलाहाबाद जनपद में फूलपुर और नैनी प्रमुख औद्योगिक स्थल हैं। फूलपुर का सबसे प्रमुख लोक उद्यम इफको है। नैनी के प्रमुख लोक

उद्यमों में आई० टी० आई०, भारत पम्पस एव कम्प्रेसर्स लिमि० व त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमि० प्रमुख हैं। इन लोक उद्यमों में भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स व त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स का नाम भारत के रूग्ण लोक उद्यमों की सूची में है। चूँकि मेरे शोध-प्रबन्ध का शीर्षक भारत में लोक उद्यमों में रूग्णता एव चक्रीय प्रबन्ध (इलाहाबाद विशेष के सन्दर्भ में) है, इसलिए मैंने इलाहाबाद के इन दोनों लोक उद्यमों का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन करने का बीड़ा उठाया और इन दोनों उद्यमों में व्याप्त रूग्णता के कारणों व समाधान का विस्तृत अध्ययन किया।

### **इलाहाबाद के प्रमुख रूग्ण लोक उद्यम भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमि० का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन**

इस लोक उपक्रम की स्थापना एक सरकारी कम्पनी के रूप में 1 जनवरी 1970 को नैनी इलाहाबाद में हुई। इस कम्पनी द्वारा अपसेन्द्री पम्प पश्चाग्रामी पम्प तथा पश्चाग्रामी सम्पीडीज का निर्माण किया जाता है। इधर के वर्षों में सरकार ने इस कम्पनी को उच्च दबाव वाले बिना जोड़ के गैस सिलिण्डरों के निर्माण का कार्य भी सौंपा है। इस प्रकार इस कम्पनी के पास अब दो प्रभाग हैं।

(1) पम्प तथा कम्प्रेसर्स निर्माण प्रभाग तथा (2) गैस सिलिण्डर निर्माण प्रभाग और ये दोनों संयंत्र नैनी में ही स्थापित हैं। यह कम्पनी अप्रैल 1987 से भारत यंत्र निगम लिमि० की एक सहायक कम्पनी बन गयी है। मार्च 1987 तक यह एक स्वतन्त्र कम्पनी के रूप में काम कर रही थी।

## बी० पी० सी० एल० में रूग्णता के कारण

### 1. आदेशों के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होना :-

यह कम्पनी मुख्य रूप से अपसेन्द्रीपम्प, पश्चाग्रगामी सम्पीडीज तथा उच्च दबाव वाले बिना जोड के गैस सिलेण्डरो के निर्माण का कार्य करती है। इस कम्पनी में 2001-02 के लिए उत्पादन लक्ष्य 120 करोड रूपये का निर्धारित किया था। परन्तु यह अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही इसी प्रकार इस कम्पनी ने 99-2000 में 64 करोड रू० का आदेश प्राप्त किया था परन्तु उत्पादन 42.53 करोड रू० का ही करने के कारण यह पूर्ण रूप से आदेशों की पूर्ति करने में असफल रही जो इसकी रूग्णता का सबसे प्रमुख कारण है। वर्ष 2000-2001 में इस कम्पनी को 80 करोड रू० का आदेश प्राप्त हुआ था परन्तु इस वर्ष भी यह कम्पनी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इस कम्पनी को विभिन्न उत्पादों के लिए जो आदेशित लक्ष्य प्राप्त हैं उनका विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेगा।

### तालिका- 5.1

#### बी० पी० सी० एल० के प्रमुख उत्पादों के लिए

#### आदेशित लक्ष्य (लाख रू० में)

उत्पाद समूह	99-2000	2000-2001	2001-2002
सेन्द्रीफुगल पम्प	10	15	15
रेसीप्रोकेटिंग पम्प	5	10	15

कम्प्रेसर्स	10	20	25
स्पेयर पार्ट्स	15	20	25
गैस सिलेण्डर	10	12	15
कुल योग	50	77	95

स्त्रोत स्वयं के सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकड़े

उपरोक्त तालिका में उत्पादों के लिए आदेशित लक्ष्य का विवरण दिया गया है। परन्तु यह लोक उद्यम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है। जिसके कारण ग्राहक इस कम्पनी को आदेश देने में कतराते हैं।

मैंने इस कम्पनी का सर्वेक्षण करते समय इस कम्पनी के उत्पादन विभाग के प्रबन्धक से इसके लक्ष्य को प्राप्त करने की असफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रश्न किए जिसका जवाब उन्होंने निम्न प्रकार से दिया –

प्र० 1 बी० पी० सी० एल० अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर असफल क्यों हो रही है?

उत्पादक प्रबन्धक का जवाब – उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त न करने के निम्नलिखित कारण हैं – (i) विद्युत की आपूर्ति निरन्तर बाधित होना (ii) नई तकनीक का प्रयोग न करना (iii) पुरानी मशीनों का उत्पादन कार्य में प्रयोग किया जाना।

इस इकाई का सर्वेक्षण करने के दौरान मुझे ज्ञात हुआ कि इस इकाई में वर्ष 2000-2001 के लिए उत्पादन लक्ष्य 85 करोड़ निर्धारित किया है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न नारा चारों ओर लिख दिया

गया है। जिससे सभी अधिकारी गण कर्मचारी गण व श्रमिक तन-मन-धन से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील रहे—

- 1 हर छोर में एक ही शोर, उत्पादन 85 करोड़।
2. सतत प्रयत्न शील रहना होगा, उत्पादन उत्तम करना होगा।
- 3 उत्पादन मेरा धर्म, गुणवत्ता मेरा कर्म।

वर्ष 2000-2001 के लिए इस इकाई के लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है — 1 उत्पादन लक्ष्य 85 करोड़ 2 लाभ लक्ष्य 133 लाख 3 आदेश लक्ष्य 80 करोड़ 4 स्टॉक लक्ष्य 5 करोड़

वर्ष 2001-02 के लिए लक्ष्य इस इकाई द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया — (i) उत्पादन लक्ष्य 200 करोड़ ₹0 (ii) वास्तविक उत्पादन लक्ष्य 150 करोड़ ₹0 (iii) अन्तिम स्टॉक 50 करोड़ ₹0 (iv) लाभ लक्ष्य 5 करोड़ ₹0

उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण व श्रमिकगण एक जुट प्रयास में जुट गये परन्तु वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए।

इस इकाई द्वारा अपसेन्द्री पम्प, पश्चाग्रगामी पम्प तथा पश्चाग्रगामी सम्पीडीज का निर्माण किया जाता है जो पम्पिंग लाइन को बिछाने में उपयोग किया जाता है। यह उपक्रम ओ० एन० जी० सी० के आदेशानुसार कई बार गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य सम्पादित कर चुका है। पहले यह इकाई केवल पम्पों के निर्माण का कार्य सम्पादित करता था। परन्तु वर्तमान में यह गैस सिलेण्डरों के निर्माण कार्य भी सम्पादित करता है। यह लोक उद्यम अमोनिया गैस, फ्लोरिन गैस, फ्रियान गैस, सिरेंजी गैस



तथा डिहाइड्रेटेड, एसीडिटिंग गैस आदि को भरने तथा उपयोग करने के लिए सिलेण्डरो का निर्माण करता है। इन सिलेण्डरो का वजन 70-73 किग्रा० तक रहता है तथा यह गैसों को उनकी आवश्यकतानुसार भरने के लिए तैयार की जाती है। यह सरकारी कारखानों तथा उपभोक्ताओं को भी खुले बाजार में एक निश्चित कीमत पर उनके आदेशानुसार बेचता है। गैस सिलेण्डरो के निर्माण के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया गया है। जिसमें केवल सिलेण्डरो का निर्माण तथा विक्रय के सम्बन्ध में निर्णय लेकर उत्पादन लक्ष्य को निर्धारित करके उसको प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाता है।

इस कम्पनी द्वारा बड़े पैमाने पर सेण्ट्रीफुगल पम्प्स का निर्माण करके बिक्री किया जाता है। वर्ष 99-2002 में इस कम्पनी ने 10 करोड़ रु० का पम्प निर्माण करके बेचा है। इसी तरह से इसकी बिक्री में वृद्धि हुई जो वर्ष 2000-2001 में बढ़कर 15 करोड़ रु० हो गयी। इस पम्प का प्रयोग बहुत से उद्देश्य में किया जाता है। इसलिए इसकी माग निरन्तर बनी रहती है। वर्ष 2001-02 में भी 15 करोड़ रु० रहा, इस प्रकार इस वर्ष यह गत वर्ष के बराबर ही बिक्री करने में सफल रहा।

यह कम्पनी रेसीप्रोकेटिंग पम्प्स का भी निर्माण करती है। इस कम्पनी ने ऑयल और नेचुरल गैस कारपोरेशन बडौदा के आदेश पर 16 नं० प्लन्गर पम्प्स तैयार करके इस कारपोरेशन को इसी वर्ष बेचा है। इसी कम्पनी ने एफ० सी० आई० सिन्दरी के आदेश पर 1 न० डी० वी० एम० पम्प का निर्माण करके इस कम्पनी को बेचा है। तथा इसी वर्ष 5 प्लन्गर पम्प्स , आई० ओ० सी० एल० मथुरा को बेचा है।

बनाये रख सकती है। इसलिए इस कम्पनी को यह प्रयास करना चाहिए कि यह आधिक्य अर्जन अवश्य करे। इसके हानि अर्जन का तुलनात्मक विश्लेषण निम्न तालिका में प्रदर्शित है -

### तालिका : 5.3

#### नकद हानि का विवरण (करोड़ रु० में)

वर्ष	नकद हानि
1995-96	- 7 65
96-97	- 2 44
97-98	- 7 43
98-99	- 24 60
99-2000	- 25.19
2000-2001	0 50

स्त्रोत महत्वपूर्ण वित्तीय सकेताक भारत यन्त्र निगम

रूग्ण उद्योग कम्पनी एक्ट 1985 के अनुसार जब कोई कम्पनी लगातार कई वर्षों तक हानि अर्जित करता है तो वह कम्पनी रूग्ण हो जाती है। सर्वेक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह कम्पनी वर्ष 95-96 से लगातार हानि अर्जित कर रही है। इस कम्पनी ने वर्ष 99-2000 में 25.19 करोड़ रु० नकद हानि अर्जित करके अपने असन्तोषजनक स्थिति को प्रदर्शित किया है। बी० आई० एफ० आर० की सूची में इस कम्पनी का नाम दर्ज होना इसके प्रबन्धकों के लापरवाही का सूचक है। इलाहाबाद का यह कम्पनी रूग्ण घोषित हो चुकी है यदि यह इसी प्रकार की हानि आगामी वर्षों में भी अर्जित

करती रहती है तो सरकार को मजबूरन इसे निजी उद्योगपतियों के हाथों में सौंपना पड़ेगा।

इस कम्पनी के सर्वेक्षण के दौरान मैंने वहाँ के वित्त प्रबन्धक से इसके लगातार नकद हानि के बारे में पूछा —

प्र० 1. — आपकी यह कम्पनी निरन्तर नकद हानि क्यों अर्जित कर रही है?

उत्तर — वित्त प्रबन्धक ने जवाब दिया कि नकद हानि अर्जन के निम्न कारण हैं— (i) वित्त की कमी होना (ii) ऋण की आवश्यकता नुसार अनुपलब्धता (iii) सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पूँजी में वृद्धि न करना।

### 3. नेट वर्थ का लगातार ऋणात्मक होना :—

बी० पी० सी० एल० का नेटवर्थ कई वर्षों से लगातार ऋणात्मक रहा है जो इसके असन्तोषजनक निष्पादन को प्रदर्शित करता है। किसी भी कम्पनी का नेटवर्थ यदि शून्य के कम हो जाता है तो वह रूग्ण हो जाती है। इस कम्पनी को अपने नेटवर्थ में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब सरकार को मजबूरन इसका निजीकरण करना पड़ेगा। इसका विस्तृत विवरण नीचे की तालिका में प्रदर्शित है—

#### तालिका - 5.4

#### नेटवर्थ का विवरण (करोड़ ₹ में)

वर्ष	नेटवर्थ का विवरण
1994-95	-16.09
95-96	-17.80
96-97	-18.31
97-98	-18.20

98-99	-31 10
99-2000	-37 99
2000-2001	-36 62

स्त्रोत: महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतांक भारत यत्र निगम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस कम्पनी के नेटवर्थ का परिणाम सन्तोषजनक नहीं है। नेटवर्थ सदैव ऋणात्मक ही रहे है। नेटवर्थ में लगातार कमी रूग्णता का महत्वपूर्ण कारण है। यदि इसी प्रकार नेटवर्थ की स्थिति बनी रहेगी तो वह दिन दूर नहीं है जब सरकार को इस कम्पनी को बन्द करना पड़ेगा अथवा निजीकरण करना पड़ेगा।

#### 4. सरकार द्वारा कई वर्षों से लगातार समान पूँजी प्रदान करना :-

इस उद्योग में कई वर्षों से पूँजी का अभाव बना हुआ है। बढ़ते महगाई, नवीन तकनीको व मशीनों को क्रय करने के लिए इनके पास पर्याप्त पूँजी का अभाव है जिससे ये अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर असफल रहे हैं। सरकार द्वारा कई वर्षों से पूँजी में वृद्धि नहीं किया जा रहा है, जबकि बढ़ते महगाई व नवीन तकनीको को प्रयोग करने के लिए इन्हें अधिक पूँजी की आवश्यकता है। पूँजी का विस्तृत विवेचन नीचे की तालिका में किया गया है—

### तालिका - 5.5

सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजी का विवरण (करोड़ रु० में)

वर्ष	अधिकृत पूँजी	प्रदत्त पूँजी
96-97	55	52 03
97-98	65	52 03
98-99	65	52 03
99-2000	65	52 03
2000-2001	65	52 03

स्रोत महत्वपूर्ण वित्तीय सकेताक, भारत यत्र निगम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजी वर्ष 96-97 से 2000-2001 तक समान रही है अतः इससे प्रदर्शित होता है कि सरकार लोक उद्यमों को अधिक पूँजी प्रदान करने में असमर्थ है। जबकि महगाई में लगातार वृद्धि होने के कारण इन लोक उद्यमों को अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। कम पूँजी की उपलब्धता के कारण ये लोक उद्यम अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान मैंने वित्त प्रबन्धक से पूछा -

प्र०- सरकार द्वारा लगभग समान वित्त कई वर्षों से क्यों प्रदान किया जा रहा है?

वित्त प्रबन्धक का जवाब .- (i) सरकार के पास उद्यमों के लिए बजट की कमी होना (ii) धन का लोक उद्यमों द्वारा पूर्ण उपयोग न किया जाना।

## 5. श्रमिकों व कर्मचारियों का आधिक्य :-

बी० पी० सी० एल० में अब भी श्रमिकों व कर्मचारियों की अधिकता है। इन श्रमिकों व कर्मचारियों को वेतन के रूप में भुगतान करने के लिए काफी धन व्यय करना पड़ता है। यदि कर्मचारियों व श्रमिकों की संख्या कम हो जाय तो यह कम्पनी इस धन का प्रयोग अन्य कार्यों में करके अपने हानि अर्जन को लाभार्जन में बदलने का प्रयास कर सकती है। कर्मचारियों का विस्तृत विवेचन इस प्रकार है -

**तालिका - 5.6**  
**कर्मचारियों का विवरण**

वर्ष	कुल कर्मचारियों की संख्या	अधिकारियों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
95-96	1762	275	1487
96-97	1740	301	1439
97-98	1707	295	1412
98-99	1704	326	1378
99-2000	1654	306	1348
2000-2001	1604	1604	286

स्रोत महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतांक, भारत यंत्र निगम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बी० पी० सी० एल० में अब भी कर्मचारियों की अधिकता है। जबकि नई मशीनों तथा कम्प्यूटर के आ जाने के कारण बहुत से कर्मचारियों पर कार्यभार कम हो गया है। सरकार धीरे-धीरे इन कर्मचारियों की घटाने का कार्य कर रही है। अधिक कर्मचारी

होने के कारण सरकार द्वारा उनके वेतन पर अधिक खर्च आता है। यदि इस धन का उपयोग उद्योग के विकास के लिए किया जाय तो उद्यमों का अधिक विकास किया जा सकता है।

### विपणन रणनीति :-

बी० पी० सी० एल० मुख्यतया निम्न ग्राहकों को उनके आदेशानुसार उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

- (1) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमि०
- (2) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि०
- (3) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि०
- (4) कोचीन रिफाइनरीज
- (5) मंगलौर रिफाइनरी
- (6) मद्रास रिफाइनरी लि०
- (7) रिलायन्स पेट्रोलियम
- (8) टाटा केमिकल्स लि०
- (9) हिन्दुस्तान लीवर लि० आदि।

यह इकाई अपने उत्पादित वस्तुओं को सरकार के आदेशानुसार कारखानों व जनता को सीधे एक निश्चित दर पर बेचता है। इसके मूल्य का निर्धारण उत्पादों के लागत मूल्य में कुछ लाभ जोड़कर निर्धारित किया जाता है। इस इकाई द्वारा भी विपणन रणनीति पहले से तैयार नहीं किया जाता है। जिसके कारण सही समय पर आदेश को पूरा करने में यह उपक्रम निरन्तर असफल रही है। इसी कारण से कारखाने के मालिकगण इस इकाई

को आदेश देने में हिचकते हैं। इस इकाई को अपने विपणन रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा तभी यह अपने स्थिति में सुधार ला सकता है। प्रबन्धक गण को एक विपणन विशेषज्ञ की नियुक्ति करनी चाहिए जिससे विपणन निष्पादन में सुधार लाया जाता है।

### बी० पी० सी० एल० की सर्वेक्षणात्मक प्रश्नावली सूची

प्र० 1 — यह लोक उद्यम निरन्तर नकद हानि क्यों अर्जित कर रही है ?

उत्तर — वित्त प्रबन्धक ने जवाब दिया कि वित्तीय सस्थाओं व बैंकों से अधिक ब्याज पर ऋण प्राप्त होने के कारण ब्याज के रूप में अधिक धन का भुगतान करना तथा सरकार द्वारा आवश्यकता से कम पूँजी उपलब्ध कराना।

प्र० 2 — यह इकाई अपने नेटवर्थ में सुधार क्यों नहीं कर पा रहा है?

उत्तर — वित्त प्रबन्धक ने जवाब दिया कि यह इकाई वित्त का समुचित उपयोग करने में निरन्तर असफल हो रहा है तथा कर्मचारियों व श्रमिकों पर वेतन के रूप में अधिक खर्च आ रहा है। जिससे नेटवर्थ निरन्तर ऋणात्मक स्थिति को बनाये हुए है।

प्र० 3 — इस इकाई का उत्पादन क्यों नहीं सुधर रहा है?

उत्तर — उत्पादक प्रबन्धक ने जवाब दिया कि मशीनों की मरम्मत व देख-रेख न होने के कारण वे सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और वित्त के अभाव में नये मशीनों व यन्त्रों को क्रय करने में यह कम्पनी असमर्थ है। उत्पादन में कमी होने का एक प्रमुख कारण श्रमिकों की उदासीनता व कार्य के प्रति लापरवाही है।

प्र० 4.— इस इकाई की बाजार रणनीति सफल क्यों नहीं हो पा रही है?



उत्तर— बाजार प्रबन्धक ने जवाब दिया कि विज्ञापन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण ये उद्यम ग्राहकों को आकर्षित करने में निरन्तर असफल हो रहा है तथा ग्राहकों को सुविधानुसार परिवहन की भी व्यवस्था करने में असफल रहता है जिससे इसकी बाजार रणनीति सफल नहीं हो पा रही है।

प्र० 5 — इस इकाई में नये मशीन व तकनीक का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं?

उत्तर — उत्पादक प्रबन्धक ने जवाब दिया कि इंजीनियरों व विशेषज्ञों में नये तकनीक के प्रयोग के बारे में जानकारी न होना तथा उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था के अभाव के कारण नये तकनीक व मशीनें का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।

प्र० 6 — श्रमिकों की हड़ताल तालाबन्दी व कामरोंको आन्दोलन पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं?

उत्तर — उत्पादक प्रबन्धक ने जवाब दिया कि श्रमिक संघों का राजनीति से प्रेरित होने के कारण हड़ताल, तालाबन्दी आदि की समस्या उत्पन्न होती है जिससे उत्पादन कार्य में बाधा उत्पन्न होता है। श्रमिकों के मध्य मधुर सम्बन्धों की स्थापना करके उनको समझा-बुझाकर काम पर बुलाया जाता है परन्तु कभी-कभी श्रमिकों व प्रबन्धकों के मध्य समझौता न होने पर कार्य में बाधा उत्पन्न होता है। सरकार ने इसपर रोक तो लगाया है पर पूर्णतया प्रतिबन्धित न होने के कारण हम लोग इसको पूर्णतया रोकने में असफल रहते हैं।

## त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमि० में कृष्णाता के कारण

इस कम्पनी की स्थापना 3 जुलाई 1965 में नैनी इलाहाबाद में एक सरकारी कम्पनी के रूप में हुई। वास्तव में यह एक संयुक्त उपक्रम है जो कि भारत सरकार तथा वोयेस्ट अलपाइन आस्ट्रिया के बीच हैं कम्पनी का मुख्य उद्देश्य ढाँचे का निर्माण करना, अनुषंशी इकाइयों की स्थापना करना तथा सम्बन्धित क्षेत्र में उत्पादन विकास को विकसित कर रोजगार अवसर में वृद्धि करना है। कम्पनी विद्युत सम्प्रेषण के लिए टॉवर दूर संचार औद्योगिक एवं इमारती ढाँचा तथा जल विद्युत उपकरणों एवं टैंकों का निर्माण कर रही है। अप्रैल 1987 से यह कम्पनी भारत यंत्र निगम की एक सहायक कम्पनी बन गयी है।

इस इकाई का सर्वेक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसको रेलवे बैगनों के मरम्मत व पुल निर्माण की ठेकेदारी प्राप्त हुई है। इस इकाई ने अभी तक विद्युत सम्प्रेषण के लिए टॉवर, दूर संचार, औद्योगिक तथा इमारती ढाँचा तथा जल विद्युत उपकरणों एवं टैंकों के निर्माण के कार्य को सम्पादित करने की दिशा में कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपक्रम ने एशियाड के लिए 150 मी० फ्री स्पैन सुपर डोम छत का निर्माण इन्दौर स्टेडियम में, एल० डी० कन्वर्टर शाप टिस्को के लिए, मोबाइल सर्विस टावर एण्ड लान्च पेडस्टाल फार पी० एस० एल० वी० इसरो हरिकोटा के लिए, री हीटर सेपरेटर नैरोरा एटोमिक पावर प्रोजेक्ट के लिए, 400 केवी० ट्रान्समिशन लाइन एन्गिल टावर एन० टी० पी० सी० के लिए स्पिलवे रैडियल गेट श्री सेलम में, एरियल रोपवे नैनीताल में, फ्लड लाइट टावर एसियाड स्टेडियम के लिए, 25500 मिमी० लम्बा ईंधन गैस एमाइन एबजाव्वर, 200 टन रोप ड्रम होस्ट, एन्गिल लाइन मशीन, समतल बोरिंग मशीन, प्लेट रोलिंग

मशीन, नारलू का पुल, नीपको के लिए कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बी० एल० पी० के लिए मिक्सिंग ड्रम, बैगेन रिफाइनरी के लिए रिटर्न मेथाइन डिस्टिलेशन, 230 किलोवाट डी० सी० ट्रान्समिशन लाइन प्रोजेक्ट थाइलैण्ड में, 300 मी० गुवेड मस्त बी० एल० एफ० कम्यूनिकेशन सिस्टम, 150 मी० टी० वी० टॉवर, माइक्रो वेव टॉवर, हवा के लिए एफ० एम० टॉवर, 80 हजारगैस होल्डर बी० एस० पी० के लिए उपकरणों तथा वस्तुओं का निर्माण करके देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है।

इस वर्ष के लिए इस इकाई को रेलवे बैगनो का मरम्मत तथा पुल निर्माण का कार्य सौंपा गया है जिसे जिम्मेदारीपूर्वक सम्पन्न करने के लिए इस उपक्रम के सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण तथा श्रमिकगण एकजुट प्रयास में जुट गये हैं। यही प्रयास इस उपक्रम को हानि अर्जन को लाभार्जन में परिवर्तित कर सकती है।

### इसकी कृष्णता के निम्न कारण हैं

1 आदेश की पूर्ति समय से न करने के कारण आदेश मिलने में कठिनाई :-

इस उपक्रम को जो भी कार्य अभी तक सौंपा गया है पिछले कई वर्षों से उन कार्यों को समय से पूरा करने में यह इकाई पूर्णतया असफल रही है। जिससे सरकार इस इकाई को नया ठेका देने में हिचकती है। यही कारण है कि इस लोक उपक्रम द्वारा निरन्तर हानि अर्जित किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से निरन्तर यह आदेशों की पूर्ति समय से पूरा करने में असमर्थ रही है। इसकी असमर्थता का प्रमुख कारण वित्त की कमी, नई तकनाकों व मशीनों का उपलब्ध न होना आदि रहा है जिससे यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने निरन्तर असफल रहा है।

## 2. नकद हानि का लगातार अर्जन करना :-

यह लोक उद्यम निरन्तर नकद हानि अर्जित कर रही है। जिसके कारण यह इकाई रूग्ण हो गई है। इसे अपने कार्य निष्पादन द्वारा नकद हानि अर्जन को कम करने का प्रयास करना चाहिए जिससे यह रूग्णता से मुक्ति पा सके। इसके नकद हानि का विवरण निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।

### तालिका - 5.7

#### नकद हानि का विवरण (करोड़ ₹0 में)

वर्ष	नकद हानि
95-96	- 7 65
96-97	- 2 44
97-98	- 7 43
98-99	- 24 06
99-2000	- 25 19
2000-2001	- 23 76

स्रोत महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतांक, भारत यंत्र निगम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यह लोक उद्यम निरन्तर हानि अर्जित कर रहा है। रूग्ण उद्योग कम्पनी एक्ट 1985 के अनुसार जब कोई कम्पनी लगातार कई वर्षों तक हानि अर्जित करता है तो वह कम्पनी रूग्ण हो जाती है। निरन्तर हानि अर्जन के कारण इस कम्पनी का निष्पादन पूर्णतया असन्तोषजनक हो गया। बी0 आई0 एफ0 आर0 की सूची में इस

कम्पनी का नाम दर्ज होना इसके प्रबन्धको के लापरवाही का सूचक है। यदि यह कम्पनी आगामी वर्षों में भी इसी तरह हानि अर्जित करती रही तो निश्चय ही सरकार को इस कम्पनी को या तो बन्द करना पड़ेगा या निजीकरण करना होगा।

सर्वेक्षण के दौरान वित्त विभाग के प्रबन्धक से नकद हानि अर्जन के बारे में पूछा —

प्रश्न — यह लोक उद्यम निरन्तर नकद हानि क्यों अर्जित कर रही है?

वित्त प्रबन्धक का जवाब — इस उद्यम के निरन्तर हानि अर्जन के निम्न कारण — (i) वित्त की कमी (ii) समय से कार्य का पूरा न कर पाना (iii) श्रमिकों की लापरवाही।

### 3. नेटवर्थ का निरन्तर ऋणात्मक होना :—

इलाहाबाद के इस लोक उद्यम का नेटवर्थ विगत कई वर्षों से निरन्तर गिरता जा रहा है। जो इसके असन्तोषजनक निष्पादन को प्रदर्शित करता है। जब किसी भी इकाई का नेटवर्थ निरन्तर गिरता रहता है तो वह इकाई कुछ वर्षों में रूग्ण हो जाती है। इस कम्पनी को अपने नेटवर्थ में निरन्तर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए जिससे यह रूग्णता से मुक्त हो सके।

## तालिका - 5.8

## नेटवर्थ का विवरण (करोड़ ₹0 में)

वर्ष	नेटवर्थ
95-96	- 40 44
96-97	-42 99
97-98	-48
98-99	-72.74
99-2000	-62.52
2000-01	-101 24

स्रोत महत्वपूर्ण वित्तीय सकेताक, भारत यत्र निगम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस कम्पनी का नेटवर्थ अत्यन्त असन्तोषजनक है। इस कम्पनी का नेटवर्थ ऋणात्मक होना अत्यन्त सोचनीय विषय है। नेटवर्थ का ऋणात्मक होना रुग्णता का एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि इसी प्रकार नेटवर्थ में ऋणात्मक वृद्धि जारी रही तो वह दिन दूर नहीं है जब सरकार को इस इकाई का भी निजीकरण न करना पड़े।

#### 4. विक्रय और लाभार्जन में निरन्तर कमी होना :-

टी0 एस0 एल0 की विक्रय क्षमता में निरन्तर कमी आती जा रही है। यह अपने विक्रय निष्पादन को सुधारने में निरन्तर असफल हो रहा है। यदि सभी उत्पादित वस्तुओं का विक्रय नहीं होगा तो यह लाभार्जन कैसे करेगा, इसलिए इसे अपने विक्रय निष्पादन में सुधार करना चाहिए। यह

उद्यम कई वर्षों से निरन्तर हानि भी अर्जित कर रहा है, जो इसके असन्तोषजनक परिणाम का सूचक है। इसे हानि अर्जन को लाभार्जन में बदलने का प्रयास करना चाहिए तभी यह अपने अस्तित्व को बनाये रख सकती है।

### तालिका - 5.9

#### विक्रय और लाभार्जन निष्पादन का विवरण (करोड़ ₹0 में)

वर्ष	विक्रय	शुद्ध लाभ/हानि
97-98	42 50	- 8.08
98-99	20 54	- 24 73
99-2000	13 39	- 26 77

स्त्रोत : भारत यंत्र निगम के महत्वपूर्ण वित्तीय सकेतांक

इस उद्यम द्वारा उत्पादन के अनुसार विक्रय क्षमता में निरन्तर कमियां आयी है। जिसके परिणामस्वरूप इस उद्यम का शुद्ध हानि लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 97-98 में केवल -808 करोड़ ₹0 ही हानि अर्जित की थी लेकिन यह 99-2000 में बढ़कर करीब तीन गुना से भी अधिक हो गये। यह इस कम्पनी के असन्तोषजनक निष्पादन को प्रदर्शित करता है।

#### 5. उत्पादन लक्ष्य को निरन्तर प्राप्त करने में असफल होना:-

इस इकाई का उत्पादन, निष्पादन कई वर्षों से सन्तोषजनक नहीं रहा है इस इकाई में नये यंत्रों व संयंत्रों की कमी व नये तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण यह अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में

निरन्तर असफल हो रहा है, जो इसकी रूग्णता का प्रमुख कारण है। इस इकाई को अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

### तालिका - 5.10

#### उत्पादन निष्पादन का विवरण (लाख रु० में)

उत्पाद	97-98	98-99	99-2000
बिल्डिंग स्ट्रक्चर	3085	225	270
टॉवर	1755	513	537
प्रेसर वेशेल्स	281	54	322
पाइप/पेनस्टाक	577	1059	56
गेट्स एण्ड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर	88	26	485
विविध	115	9	48
कुल योग	5896	1886	1396

स्रोत . भारत यत्र निगम के महत्वपूर्ण संकेतांक

इस लोक उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पादन नहीं किया जा रहा है। जिससे ग्राहकों को सन्तुष्ट करने में यह उद्यम निरन्तर असफल हो रहा है जिसके कारण यह निरन्तर हानि अर्जित कर रहा है। इसे अपने कार्य निष्पादन में सुधार करना चाहिए।

#### 6. आदेशपूर्ति निष्पादन का असन्तोषजनक होना :-

यह इकाई सरकार द्वारा आदेशित वस्तुओं का निर्माण करने में निरन्तर असफल हो रहा है। आदेशपूर्ति निष्पादन का असन्तोषजनक होना इस इकाई के लिए अत्यन्त अहितकर है। यह इकाई समय से किसी भी कार्य



को पूरा करने में निरन्तर असफल हो रहा है, जो इसकी रूग्णता का प्रमुख कारण है।

### तालिका - 5.10

#### आदेशपूर्ति निष्पादन (लाखों में)

वर्ष	कुल आदेश	आदेश पूर्ति	पेण्डिंग आदेश
95-96	388	184	204
96-97	244	57	187
97-98	99 82	23 82	76
98-99	72 40	18	54 40
99-2000	65 57	12 07	53 50

स्त्रोत स्वयं के सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध आकड़े

इस उद्योग का सर्वेक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह ग्राहकों के आदेश को पूरा करने में निरन्तर असफल हो रहे हैं। जब ग्राहक सन्तुष्ट नहीं होते तो वे आगामी आदेश भी नहीं देते हैं। तो यह लोक उद्यम कैसे लाभ को प्राप्त करेगा। इसलिए इस लोक उद्यम को आदेश के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करके उत्पादन कार्य करना चाहिए जिससे सभी ग्राहकों को सन्तुष्ट कर सके। उत्पादन विभाग के अधिकारी से सर्वेक्षण के दौरान मैंने पूछा—

प्रश्न — यह लोक उद्यम को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर असफल क्यों हो रहा है?

उत्पादक अधिकारी का जवाब - इसके असफल होने के निम्न कारण हैं-

- (i) विद्युत की अधिकाधिक कटौती (ii) नई मशीनों तथा तकनीकों का अभाव
- (iii) श्रमिकों द्वारा उत्पादन कार्य में रुचि न लेना।

### 7. पूँजी की कम उपलब्धता :-

सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त न उपलब्ध होने के कारण व इन इकाइयों के निरन्तर हानि अर्जन के कारण इनके पास पूँजी का सदैव अभाव रहता है जिससे ये अपने विकास क्रम को आगे बढ़ाने में निरन्तर असफल हो रहे हैं। विगत कई वर्षों से मंहगाई में वृद्धि होने पर भी सरकार द्वारा समान पूँजी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे पूँजी का अभाव इस इकाई में बना रहता है।

#### तालिका - 5.11

#### पूँजी का विवरण (करोड़ ₹0 में)

वर्ष	अधिकृत अंश पूँजी	प्रदत्त पूँजी
95-96	15	20 63
96-97	30	20 63
97-98	30	21 02
98-99	30	21 02
99-2000	30	21 02
2000-2001	30	22.52
2001-02	30	22.52

स्रोत : भारत यंत्र निगम के वित्तीय संकेतांक

इस लोक उद्यम को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पूँजी लगभग कई वर्षों से समान रही है। जबकि इधर के वर्षों में मंहगाई में वृद्धि होने के कारण इस लोक उद्यम को अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा अधिक पूँजी न उपलब्ध कराने के कारण यह उद्यम सुचारु रूप से उत्पादन कार्य व नई मशीनों व तकनीको का उपयोग करने में अपने को असमर्थ पा रहे है। जिससे उत्पादकता में निरन्तर गिरावट, लाभार्जन क्षमता में कमी तथा ग्राहकों को सन्तुष्ट करने में यह इकाई असमर्थ हो रही है।

### 8. कर्मचारियों व श्रमिकों के आधिक्य के कारण समस्या :-

टी0 एस0 एल0 में कर्मचारियों व श्रमिकों का अब भी आधिक्य है। इनको ऐच्छिक सेवानिवृत्ति देकर इनकी संख्या में कमी करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, फिर भी इन पर अधिक धन व्यय होने के कारण यह इकाई अपना विकास कार्य करने में असमर्थ हो रही है।

#### तालिका 5.12

#### कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

वर्ष	कुल कर्मचारियों की सं०	अधिकारियों की संख्या	श्रमिकों की सं०
96-97	1380	190	1190
97-98	1267	179	1088
98-99	1266	179	1087
99-2000	1210	164	1046
2000-01	766	110	656

स्रोत . भारत यंत्र निगम, महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतांक

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस लोक उपक्रम में कर्मचारियों की संख्या निरन्तर घटाई जा रही है। वर्ष 2001 में बहुत से कर्मचारियों ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। जिससे कर्मचारियों की सं० में कमी आयी है। इस कमी के कारण ही यह लोक उद्यम उत्पादन लक्ष्य को अब भी प्राप्त करने में असमर्थ हो रही है।

### विपणन रणनीतियाँ

यह लोक उद्यम विद्युत सम्प्रेषण के लिए टॉवर दूर संचार औद्योगिक एवं इमारती ढाचा, तथा जल विद्युत उपकरणों एवं टैंकरो के निर्माण का कार्य अभी हाल में ही इस कम्पनी को रेलवे बैगनों के मरम्मत व पुल निर्माण की ठेकेदारी प्राप्त हुई है। यह लोक उद्यम सरकार के आदेश पर सभी निर्माण कार्य सम्पादित करता है। यह लोक उद्यम मांग के अनुसार पूर्ति करने में असमर्थ रहती है क्योंकि प्रबन्धकों द्वारा विपणन की नीतियाँ पहले से ही तैयार नहीं किया जाता हैं आदेशों की पूर्ति न करने के कई कारण हैं। जैसे पुराने यन्त्रों और मशीनों का प्रयोग श्रमिकों का कार्य के प्रति लापरवाही विपणन रणनीति का पहले से नियोजन न करना।

बी० पी० सी० एल० व टी० एस० एल० का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन लोक उद्यमों में रूग्णता के सभी लक्षण विद्यमान हैं। जैसे— 1. नकद हानि का लगातार अर्जन करना, 2. नेटवर्थ की ऋणात्मक स्थिति, 3. शुद्ध हानि में निरन्तर वृद्धि, 4. उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर असफलता। इन सभी लक्षणों के कारण इन दोनों लोक उद्यमों को पूर्णतया रूग्णता की श्रेणी में रखा जा सकता है।

## टी० एस० एल० की सर्वेक्षणात्मक प्रश्नावली :-

प्र० 1 — ठेका पर काम लेने पर यह इकाई समय से पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है?

उत्तर — प्रबन्धक ने जवाब दिया कि आधुनिक यन्त्रों व मशीनों के अभाव, कर्मचारियों व श्रमिकों की लापरवाही व श्रमिकों की अधिकता से काम लेने में कठिनाई आदि के कारण यह कार्य समय से पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहा है।

प्र० 2 — इस इकाई की बाजार रणनीति क्यों असफल हो रही है?

उत्तर — बाजार प्रबन्धक ने जवाब दिया कि बाजार रणनीति का पहले से नियोजन न करना व बाजार विशेषज्ञों द्वारा बाजार का अनुसंधान व नये बाजारों की खोज न करने के कारण इस इकाई की रणनीति असफल हो रही है।

प्र० 3 — इस इकाई में नये यन्त्रों व तकनीकों का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?

उत्तर — वित्त प्रबन्धक ने जवाब दिया कि पूँजी की कम उपलब्धता तथा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं द्वारा समय पर ऋण न उपलब्ध कराये जाने के कारण यह इकाई नये यन्त्रों व तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है।

प्र० 4 — यह इकाई निरन्तर हानि क्यों अर्जित कर रही है?

उत्तर — वित्त प्रबन्धक ने जवाब दिया कि ऋण पर ब्याज के रूप में अधिक भुगतान करना तथा वेतन के रूप में कर्मचारियों को धन का भुगतान करना तथा समय पर उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर असफल होने के कारण यह इकाई निरन्तर हानि अर्जित कर रही है।

इलाहाबाद के लोक उद्यमों में रूग्णता के प्रमुख कारण

### 1. पॉवर/शक्ति की कमी एवं अनियमितता के कारण रूग्णता :-

यह लोक उद्यमों की रूग्णता का सबसे प्रमुख कारण है। इस जनपद के लगभग सभी उद्यमों को विद्युत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती जिससे उत्पादन में कमी आती है। सर्वेक्षण के अनुसार इन उद्योगों को 8-10 घण्टे लगातार विद्युत की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्युत पूरे समय तक उपलब्ध नहीं हो पाती। बी० पी० सी० एल० को अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 घण्टे लगातार विद्युत चाहिए लेकिन काम के समय विद्युत न उपलब्ध होने के कारण ये अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर असफल हो रहा है। इसी प्रकार टी० एस० एल० को भी पूरे समय विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाती जिससे यह उद्यम भी अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इन उद्यमों को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत अवश्य चाहिए जिससे श्रमिक गण उत्पादन कार्य में पर्याप्त रुचि लेकर उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सकें।

### 2. पूँजी का अभाव एवं उपलब्धता :-

पूँजी का अभाव एवं अपर्याप्तता इन दोनों उद्यमों की रूग्णता का प्रमुख कारण है। इन दोनों उद्यमों में बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से नहीं लिया है। यदि किसी इकाई द्वारा लगातार ब्याज की चार तिमाही किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे रूग्ण माना जाता है। इस उद्योग द्वारा

उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की माग अधिक है पूर्ति कम। इसका प्रमुख कारण वित्त की अपर्याप्तता है। क्योंकि पूँजी के अभाव में ये अपना उत्पादन बढ़ाने में असफल हैं। वर्तमान युग में नये मशीनों व यन्त्रों की सहायता से ग्राहकों के आवश्यकतानुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। बी० पी० सी० एल० व टी० एस० एल० में रुग्णता का प्रमुख कारण उचित मात्रा में पूँजी की अनुपलब्धता ही है।

### 3. मांग के अभाव के कारण रुग्णता :-

इन इकाइयों द्वारा उत्पादित माल का बाजार में मांग का अभाव है। बी० पी० सी० एल० जो पम्प तथा कम्प्रेसर्स व गैस सिलिण्डर के निर्माण का कार्य करता है। बाजार में अपने उत्पादकों के माग में कमी के कारण रुग्ण होती जा रही है। टी० एस० एल० द्वारा उत्पादित वस्तुओं की भी माग में निरन्तर कमी आयी है। इन दोनों उद्यमों द्वारा ग्राहकों के मांग के अनुसार पूर्ति न करना। इनके माग में कमी का एक प्रमुख कारण है।

### 4. कम उत्पादन के कारण रुग्णता :-

इलहाबाद के इन दोनों उद्यमों की उत्पादन क्षमता काफी कम है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कच्चे माल की निरन्तर उपलब्धता व पूँजी की आवश्यकता होती है। बी० पी० सी० एल० व टी० एस० एल० अपने लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन करने में निरन्तर असफल हो रहे हैं। जिससे बाजार में इनकी छवि धूमिल हो रही है। ग्राहकों को समय पर वस्तुओं के उपलब्ध न होने के कारण वे पुनः इन उद्यमों को आदेश देने में कतराते हैं। कम उत्पादन का एक प्रमुख कारण पुराने यन्त्रों एवं मशीनों का प्रयोग भी है। परन्तु निरन्तर हानि अर्जन व पूँजी की अनुपलब्धता के कारण ये दोनों उद्यम नये तकनीकों व मशीनों को क्रय करने को अपने को असफल पा रहे हैं।

## 5. कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग करने में निरन्तर असफल होना :-

इन दोनों उद्यमों के सर्वेक्षण के दौरान मैंने कारखाना प्रबन्धक से पूछा कि—

प्र०— ये दोनों उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में क्यों असफल हो रहे हैं?

कारखाना प्रबन्धक का जवाब — (i) श्रमिकों में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव (ii) कार्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता तथा (iii) पुराने यन्त्रों व मशीनों के प्रयोग के कारण ये उद्यम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में निरन्तर असफल हो रहे हैं। ये अपनी पूरी क्षमता का अधिकतम 75% ही उपयोग कर पा रहे हैं जबकि इन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए तभी उनके निष्पादन में सुधार हो सकता है।

## 6. प्लांटों की बंद्दुस्ति मरम्मत व्यवस्था का अभाव :-

दोनों उद्यमों के उत्पादन कार्य में संलग्न यन्त्र व सयंत्र काफी पुराने हो चुके हैं, उनके रखरखाव व मरम्मत की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन्जीनियरों व तकनीक विशेषज्ञों पर है। लोक उद्यम होने के कारण ये सभी अपने कार्य के प्रति पूर्णतया लापरवाह हैं। जिससे प्लांटों के मरम्मत की समुचित व्यवस्था के अभाव से उत्पादन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ये इकाइयां अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती हैं।

इन दोनों उद्यमों के अस्वस्थता के वाह्य कारण — 1. कच्चे माल का सही समय पर उपलब्ध न होना, 2. उत्पादों के विपणन में



कठिनाइयां, 3 साख की समुचित अनुपलब्धता के कारण कठिनाइया, 4 बैंको व वित्तीय संस्थाओं से समय पर ऋण की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई।

## 7. गुण नियन्त्रण का अभाव :-

इलाहाबाद के इन दोनों लोक उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुएं उच्च गुण के न होने के कारण ग्राहकों को आकर्षित करने में निरन्तर असफल रहे हैं। जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़ने के बजाय निरन्तर घटती जा रही है। इस वर्ष से बी० पी० सी० एल० ने गुणवत्ता नीति के रूप में "अपने उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता के लिए, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर समस्त कर्मचारियों के सहयोग से ख्याति अर्जित करना व उसे निरन्तर बनाये रखना" आई० एस० ओ० 9001 द्वारा निर्धारित को स्वीकार किया है। जिससे गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

टी० एस० एल० भी अपने कार्यों व उत्पादनों में सुधार करने के लिए गुणवत्ता नीति को अपनाने के लिए तत्पर है, क्योंकि इसके कार्य निष्पादन से सरकार पूर्णतया असन्तुष्ट है इसलिए इस इकाई को अपने गुणवत्ता में निरन्तर सुधार की आवश्यकता है।

## इन दोनों उद्यमों के अस्वस्थता के आन्तरिक कारण

1. उचित बजट और वित्तीय योजनाओं की अनुपस्थिति
2. वित्तीय संस्थाओं से अपर्याप्त सहायता
3. स्थान, प्लांट, तकनीक आदि का अनुचित चुनाव
4. पुराने यन्त्रों व संयन्त्रों का उत्पादनकार्य में प्रयोग होना।
5. श्रमिक व प्रबन्धकों के मध्य आपसी मनमुटाव के कारण उत्पादन कार्य अवरुद्ध होना।

- 6 कम ग्राहकों पर अत्यधिक निर्भरता
- 7 माग पूर्वानुमान का सही न होना
8. खराब विपणन योजना के कारण माल बेचने में कठिनाई
- 9 विपणन खोज में निरन्तर कमी का अभाव
- 10 बेकार उत्पाद मिलान से निम्न कोटि का उत्पाद होना
- 11 खरीद व विक्रय कीमत पर सरकारी निर्देश के कारण समस्या
- 12 राष्ट्रीय बाजारों में अवनति से व्यापारिक मन्दी
13. ग्राहकों को आकर्षित करने में विज्ञापनों आदि का अभाव
- 14 आवश्यकता से अधिक श्रमिकों व कर्मचारी के कारण काम लेने में कठिनाई
- 15 प्रबन्धकीय और स्टाफ प्रशिक्षण का अभाव
16. कर्मचारियों की अनुवपस्थिति के कारण उत्पादन कार्य में विलम्ब होना
17. राजनीतिक हस्तक्षेप या नौकरशाही हस्तक्षेप से प्रबन्धकों की नियुक्ति में पक्षपात
- 18 खराब उच्च स्तरीय समन्वय और नियन्त्रण
- 19 मुख्य प्रबन्धकों की श्रेणी में विरोध या फूट
- 20 कार्य बल में निम्न योग्यता नीति
- 21 प्रबन्धन में असावधानी।

## बी० पी० सी० एल० वे टी० एल० एल० में व्याप्त कठिनाता के निराकरण के लिए उपाय

1. विद्युतशक्ति की निरन्तर आपूर्ति — इन इकाइयों को कम से कम 18 घण्टे विद्युत की आवश्यकता होती है। परन्तु इन्हे विद्युत 8—10 घण्टे ही उपलब्ध हो पाती है। जिससे इसके उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा ये दोनों इकाई अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य को निरन्तर प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। यदि उन्हें विद्युत पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे तो ये अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करके ग्राहकों को सन्तुष्ट करते हुए अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। सरकार द्वारा औद्योगिक आस्थानों में अलग विद्युत उत्पादन केन्द्र खोला जाना चाहिए अथवा सौर्य ऊर्जा स्थापित किया जाना चाहिए जिससे इन्हें निरन्तर विद्युत की सुविधा उपलब्ध रहे और उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो सके। इन लोक उद्यमों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा किस्त प्रणाली पर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा किस्त की रकम न्यूनतम होनी चाहिए जिससे उद्योगों को अदा करने में कोई कठिनाई न हो। विद्युत विभाग को भी अपने कार्य में सुधार करना चाहिए, सड़क और गलियों में दिन भर जलने वाली बिजली को बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा विद्युत चोरी को भी रोका जाना चाहिए जिससे शक्ति को बचा करके लोक उद्यमों को अधिक बिजली दी जा सके और भविष्य में विद्युत से होने वाली समस्या से आसानी से रोका जा सके।

2. मांग की समस्या को दूर करने से सम्बन्धित उपाय :— इलाहाबाद के इन दोनों उद्यमों के मांग में निरन्तर कमी आ रही है। इन्हें अपने मांगों में वृद्धि करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना चाहिए इसके माध्यम से ये

ग्राहकों को अधिक आकर्षित कर सकते हैं। पुराने ग्राहकों को समय पर उनके मांग के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके उनको सन्तुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए। जिससे पुराने ग्राहक इन दोनों इकाइयों को आदेश देने के लिए भविष्य में सदैव तत्पर रहे।

3 उत्पादन में होने वाली समस्या को रोकने का उपाय — उत्पादन कम रहने के कारण होने वाली रूग्णता को अधिक क्षमता द्वारा कम किया जा सकता है तथा भविष्य में रोका जा सकता है। कभी-कभी उत्पादन क्षमता में कमी संयंत्रों की कमी या संयंत्रों के पुराने हो जाने के कारण होती है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उद्यमियों को अपने संयंत्रों का उचित रख-रखाव करना चाहिए तथा समय-समय पर जांच कराना चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि उद्यमी संयंत्रों का उचित रख-रखाव नहीं करते। यदि उत्पादन में कमी संयंत्रों की कमी के कारण हो रही है तो उसे तुरन्त क्रय करना चाहिए। श्रमिकों की लापरवाही के कारण यदि उत्पादन कम हो रहा है तो उत्पादक प्रबन्धक को श्रमिकों पर विशेष निगरानी रखना चाहिए जिससे श्रमिक पूरी मेहनत व लगन के साथ उत्पादन कार्य करे।

4. वित्तीय समस्या को दूर करने से सम्बन्धित उपाय — भारत के अधिकांश उद्यम वित्त की समस्या से जूझ रहे हैं। वित्त के अभाव में बहुत सी इकाइयां रूग्ण हो गई हैं। सरकार द्वारा इन इकाइयों के लिए पूँजी सही समय पर उपलब्ध कराना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों को लोक उद्यमों को कम ब्याजदर पर तथा लम्बे समय के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए जिससे लोक उद्यमों में पर्याप्त धन की उपलब्धता सदैव बनी रहे और ये संस्थाएं अपने निष्पादन में निरन्तर सुधार करते रहे। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की लम्बी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा

करने में ही बहुत समय लग जाता है। यह प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक होना चाहिए जिससे ऋण आसानी से सही समय पर लोक उद्यमों को उपलब्ध कर सके और वे इस धन का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम हो सकें।

5. नकद हानि अर्जन को रोकने के उपाय - इलाहाबाद के दोनों उद्यमों द्वारा निरन्तर नकद हानि अर्जित किया जा रहा है। इन्हें अपने निष्पादन में सुधार करके कम से कम उतना धन अवश्य अर्जित करना चाहिए जितना इन्होंने अपने यहां विनियोजित किया है। श्रमिकों के सहयोग से उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए तथा ग्राहकों को सही समय पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए तथा धन का सही समय पर सही कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। जिससे इन उद्यमों में अधिपूजीयन व अल्प पूजीयन की अवस्था न उत्पन्न हो। इन उद्यमों के प्रबन्धाकगणों, कर्मचारियों व श्रमिकों को तन-मन-धन से अपने वित्तीय स्थिति सुधार में करने का प्रयास करना चाहिए।

6. नेटवर्थ में सुधार के लिए सुझाव - बी० पी० सी० एल० व टी० एस० एल० इकाइयों का नेटवर्थ कई वर्षों से ऋणात्मक रहा है। जब कोई भी उद्यम निरन्तर हानि अर्जित करता रहता है तो वह रूग्ण हो जाता है। इन उद्यमों का नेटवर्थ कई वर्षों से ऋणात्मक होना यह प्रदर्शित करता है कि ये इकाइयां पूर्णतया रूग्ण हो गयी हैं। इन इकाइयों को अपने नेटवर्थ में निरन्तर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए जिससे ये अपने अस्तित्व को बनाये रखने में सफल हो सकें। सरकार हानि अर्जन करने वाले उद्यमों के निजीकरण पर विचार कर रही है। इन्हें अपने निष्पादन में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब सरकार इन उद्यमों को निजी उद्योगपतियों को बेच देगी।

7. विपणन रणनीति में सुधार के लिए सुझाव - बी० पी० सी० एल० व टी० एस० एल० को अपने विपणन रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता है। तभी ये अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आसानी से विक्री करने में सफल हो सकेंगे। इन्हें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना चाहिए तथा मुफ्त उपहार योजना प्रदान करके ग्राहकों को क्रय करने के लिए आकर्षित करना चाहिए। विपणन प्रबन्धक को उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व विपणन रणनीति तैयार कर लेना चाहिए। जिससे विपणन समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सके। वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए परिवहन की भी व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिससे ग्राहक पूर्णतया सतुष्ट रहे और भविष्य में आदेश देने के लिए लालायित रहें।

8 कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सुझाव इलाहाबाद के इन दोनों उद्यमों द्वारा अपनी क्षमता का अधिकतम 75% ही प्रयोग किया जा रहा है। जबकि इनको अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। श्रमिकों में अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जगाना चाहिए। जिससे श्रमिक उत्पादन कार्य में पर्याप्त रुचि लेकर समय पर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें। पुराने यन्त्रों व मशीनों के स्थान पर नये यन्त्रों एवं मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिससे उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो और ये दोनों इकाई अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें।

9. प्लांटों की मरम्मत व उचित रखरखाव के लिए सुझाव - दोनों उद्यमों के उत्पादन कार्य में सलग्न यंत्र व संयंत्र काफी पुराने हो चुके हैं। उनके मरम्मत व रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी इंजीनियरों व तकनीक

विशेषज्ञों पर है। उन्हें प्लांटों के मरम्मत व रख रखाव की समुचित व्यवस्था करना चाहिए। जिससे सभी संयंत्र सुचारु रूप से कार्य करते रहे और उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो आवश्यकतानुसार नये यंत्रों व मशीनों को क्रय करने के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न उत्पन्न हो।

10 रूग्णता के अन्य कारणों को दूर करने का उपाय -

(i) सही बजट और वित्तीय योजनाएँ वर्ष के प्रारम्भ में ही तैयार कर लिया जाना चाहिए, जिससे वित्तीय समस्या न उत्पन्न हो।

(ii) आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थाओं से सहायता ली जानी चाहिए, जिससे पूँजी की कमी के कारण उत्पादन कार्य में बाधा न उत्पन्न हो।

(iii) स्थान प्लांट, तकनीक आदि का चुनाव सोच-विचार कर किया जाना चाहिए जिससे लोक उद्यमों के उत्पादन कार्यों पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

(iv) अत्याधुनिक यंत्रों व मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त किया जा सके।

(v) श्रमिकों व प्रबन्धकों के मध्य मधुर सम्बन्धों की स्थापना होगी चाहिए, जिससे हड़ताल, तालाबन्दी, काम रोको आन्दोलन आदि को रोका जा सके।

(vi) इन दोनों उद्यमों को नये ग्राहकों का खोज करना चाहिए, जिससे लाभार्जन में अधिकाधिक वृद्धि हो सके।

(vii) मांग पूर्वानुमान का सही ढंग से अनुमान करके उत्पादन कार्य किया जाना चाहिए, जिससे स्टॉक के रूप में वस्तुएं बची न रहे।

(viii) विपणन योजना उत्पादन कार्य पूर्ण हो जाने पर ही तैयार कर लिया जाना चाहिए, जिससे माल बेचने में कठिनाई न हो।

(viii) उच्च कोटि के वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाना चाहिए, जिससे जनता वस्तुओं का प्रयोग करने के बाद इन्हीं उद्यमों को ही पुनः आदेश दे।

(ix) लोक उद्यमों को मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए, जिससे ये उचित कीमत निर्धारित करके लाभ अर्जित कर सकें।

(x) आवश्यकता से अधिक श्रमिकों व कर्मचारियों को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति दे देना चाहिए, जिससे आवश्यकता से अधिक श्रमिकों व कर्मचारियों के कारण कार्य में बाधा न उत्पन्न हो।

(xi) कर्मचारियों को प्रशिक्षित व नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे वे नये मशीनों का प्रयोग करने में सक्षम हो सकें।

(xii) राजनीतिक हस्तक्षेप को पूर्णतया नियंत्रित होना चाहिए, जिससे प्रबन्धकों की नियुक्ति में पक्षपात न हो।

(xiii) उद्यमों के प्रबन्धन का नियोजन समन्वय व नियंत्रण पूर्ण सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, जिससे ये दोनों इकाई अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करके रूग्णता से मुक्त हो सकें।



अध्याय छः

लोक उद्यमों में रुग्णता के निराकरण  
के लिये चक्रीय प्रबन्ध

निरन्तर रुग्णता की ओर अग्रसर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में एक नई एवं निश्चित नीति का प्रतिपादन सरकार के लिये चिन्ता का विषय रहा है। बाजार अर्थव्यवस्था के वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र की भूमिका का पुनरावलोकन अत्यावश्यक हो गया है। साथ ही यह भी महसूस किया जा रहा है कि समस्याओं से निपटने के लिये सुधारों की मात्रा के बजाय उनकी निरन्तरता पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये।

विगत वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालने वाले भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण के दौरान सरकार द्वारा निम्न नीतिगत प्रस्तावों की घोषणा की गई:—

- ऐसी कम्पनियों का पुनर्गठन किया जायेगा जो स्वायत्त हो सकने की क्षमता रखती हो।
- उन कम्पनियों को बंद किया जायेगा जिनका पुनर्वास किन्हीं कारणों से संभव न हो
- गैर-जरूरी समझे जाने वाले सभी उपक्रमों में सरकारी निवेश घटाकर 26 प्रतिशत अथवा जरूरी समझा गया तो उससे भी कम किया जायेगा।
- कर्मचारियों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जायेगी एवं

- निजीकरण एवं विनिवेश द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की जरूरतों की पूर्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के पुनरुत्थान एवं सार्वजनिक ऋण के भुगतान के लिये किया जायेगा।

आयोजनों के आरम्भिक वर्षों में तीव्र आर्थिक विकास, औद्योगिक संरचना के निर्माण एवं समतावादी सामाजिक ढाँचे की स्थापना के जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास एवं विस्तार हुआ, उसकी पूर्ति में वह काफी हद तक सफल भी रहा। परन्तु 70 का दशक आते-आते भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस क्षेत्र के बढ़ते भार के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की जाने लगी। 80 के दशक में इस क्षेत्र के लिये आरक्षित कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिये खोलने का निर्णय किया गया। परन्तु सरकार उपरोक्त उद्देश्यों के मददेनजर कुछ स्पष्ट कहने में झिझकती रही। नब्बे के दशक में पूर्व सोवियत संघ का पतन चीन द्वारा ताईवानी मॉडल की मौन स्वीकृति पूर्व यूरोपीय देशों में हुये परिवर्तन आदि घटनाओं के सचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के पुनर्गठन को मजबूर हुई एवं 1991 में घोषित नई आर्थिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुये निर्णय किये गये। (i) रुग्ण सार्वजनिक उद्यमों के पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करने के लिए उन्हें औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण संघ को सौंपा जाय (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के प्रवेश को एवं गैर-आरक्षित क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति प्रदान की जाय (iii) संसाधनों की उगाही एवं बेहतर जन-भागीदारी के उद्देश्य से इन उपक्रमों के शेयर वित्तीय कम्पनियों,

म्युचुअल फंडो, कर्मचारियों एवं आम जनता को बेचे जाए तथा (iv) इन उद्यमों के संचालन एवं कार्यकुशलता में सुधार हेतु इन्हें प्रबन्ध में अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाय।

भारत के सन्दर्भ में औद्योगिक अस्वस्थता को एक 'सामाजिक समस्या' के रूप में देखा जाता है। लोक उद्यमों में रुग्णता भारत के लिये एक अभिशाप है। इसी कारण से भारत का तीव्र गति से आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में लोक उद्यम कई विकट समस्याओं का सामना कर रहा है। इन समस्याओं का समाधान करना अत्यन्त समीचीन है। लोक उद्यमों में व्याप्त रुग्णता का सामना करने के लिये निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं।

#### १. बैंकों द्वारा उठाये गये कदम (Steps taken By Banks):-

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को अपनी स्थिति सुधारने के लिये व्यापारिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली प्रमुख रियायतें हैं (i) इन इकाइयों को अतिरिक्त कार्यशील पूँजी की सुविधा प्रदान करना (ii) ब्याज की न्यूनतम दरों पर वसूली करना (iii) ब्याज का भुगतान और बकाया ऋणों के एक अंश की वसूली कुछ समय के लिये रोक देना। इसके अतिरिक्त बैंकों के संगठनात्मक दृष्टि से कुछ और कदम उठाये गये हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं।

i. रिजर्व बैंक में एक अस्वस्थ औद्योगिक उपक्रम विभाग स्थापित किया गया है जो अस्वस्थ इकाइयों के विषय में जानकारी देने के अतिरिक्त

सम्बन्धित समस्याओं से निपटने के लिये सरकार, बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं और अन्य संगठनों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिये कार्य करेगा।

**ii.** रिजर्व बैंक की बैंकिंग क्रिया एवं विकास विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राज्य स्तर पर अन्तरसंस्थागत समितियाँ स्थापित की गयीं इनका उद्देश्य बैंकों, राज्य सरकारों केन्द्र और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं और अन्य संगठनों के बीच तालमेल बैठाना है।

**iii.** रिजर्व बैंक ने एक स्थाई समन्वय समिति गठित की है। जिसका काम व्यापारिक बैंको और दीर्घकालीन ऋण को देने वाली संस्थाओं के बीच समन्वय मुद्दों पर नियमित रूप से विचार करना है।

**iv.** औद्योगिक विकास के औद्योगिक पुनरुद्धार हेतु वित्त प्रभाव के अन्तर्गत एक विभाग की स्थापना की गयी है। जो बैंको से आने वाले अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों के मामलों पर गौर करेगा।

## 2. सरकारी नीति का ढाँचा:

सर्वप्रथम अक्टूबर 1981 में केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के मार्गदर्शन की दृष्टि से औद्योगिक अस्वस्थता की समस्या से निपटने के लिये सरकारी नीति का स्पष्टीकरण किया गया था इस नीति के सिद्धान्तों में फरवरी 1992 में कुछ संशोधन किये गये थे। इन सिद्धान्त की प्रमुख बातें निम्न थी:-

**i.** सरकार की प्रशासनिक मंत्रालयों की यह विशेष जिम्मेदारी होगी कि वे अपने दायित्व में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में अस्वस्थता को रोकें तथा अस्वस्थ इकाईयों की समस्याओं को हल करने के लिये उपाय करें।

**ii.** वित्तीय संस्थायें औद्योगिक व्यवस्था के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाली व्यवस्था सबल बनाने की दिशा में काम करेगी। जिससे आरम्भिक अस्वस्थता को जरूरी उपाय करके रोका जा सके।

**iii.** यदि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थायें किसी औद्योगिक इकाई को अस्वस्थता को पचा जाने में असमर्थ हो तो वे अपने बकाया वसूली ऋणों की वसूली के लिये सामान्य बैंकिंग कार्यविधि के अनुसार कार्यवाही करेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले वह इस सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट देगी ताकि सरकार निर्णय करे कि इकाई विशेष का राष्ट्रीयकरण ही करना है या किन्हीं उपायों के तहत उसको फिर अस्वस्थ बनाना है।

**iv.** यदि बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो शुरू में उसको छ माह के लिये सरकार उद्योग अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अपने हाथ में लेगी ताकि इस अवधि में यह राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कार्यवाही पूरा कर सके।

### 3. उद्योग (विकास और नियमन) के अन्तर्गत प्रतिबंधित इकाईयां—

सरकार ने अनेक इकाईयों का प्रबन्ध उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत अपने हाथ में इसलिये लिया ताकि विभिन्न उपायों द्वारा उन्हें फिर से स्वस्थ बनाया जाये। परन्तु सरकार इस क्षेत्र में ठीक से सफल नहीं हुई वर्तमान में सरकार तभी किसी इकाई का प्रबन्ध अस्थायी रूप में अपने हाथ में लेती है जब किसी अस्वस्थ इकाई का राष्ट्रीयकरण करना होता है। अक्टूबर 1981 में घोषित नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार उद्योग (विकास

### 5. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक :-

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना सरकार ने अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों को सहायता देने के उद्देश्य से की थी इसकी अधिकृत और प्रदत्त पूँजी क्रमशः 25 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये थी। इसके प्रमुख कार्य निम्न थे -

- i. अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता पहुँचाना।
- ii. इन इकाईयों को प्रबन्धकीय एवं तकनीकी सहायता देना।
- iii. समामेलन, विलगन आदि के लिये मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना और
- iv. बैंकों को अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों के बारे में परामर्श सेवाएँ प्रदान करना।

#### औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यों का विवरण

वर्ष	मामले आये	पजीकृत मामले	रद्द मामले	अनुमोदित मामले	न्यायालय को भेजे गये मामले
सितम्बर 1993	1924	1409	272	415	242
मार्च 1998	3148	2415	425	625	579
नवम्बर 1998	3441	2404	452	637	606
नवम्बर 1999	4001	284	1516	646	652

स्रोत: अरुणेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था अभिव्यक्ति प्रदर्शन इलाहाबाद

## औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निष्पादित मामले :-

वर्ष	निष्पादन
1996	275
1997	188
नवम्बर 1998	127
नवम्बर 1999	223

स्रोत: अरुणेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था अभिव्यक्ति प्रकाशन इलाहाबाद, 1999

1991 की औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर दिया गया है जिससे लोक उद्यमों में व्याप्त अस्वस्थता का शीघ्रातिशीघ्र पता लगाकर उसके निराकरण के उपाय निर्धारित करे। 30 नवम्बर 1999 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 71 मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में दर्ज किये गये हैं। इनमें से 31 मामले अनुरक्षणीय कहकर रद्द कर दिये गये। 53 मामलों में पुनर्गठन योजनाओं को स्वीकार कर लिया गया जबकि 29 मामलों (9 केन्द्रीय व 20 राज्यों) में सम्बन्धित उच्च न्यायालयों से यह सिफारिश की गई कि इन इकाईयों को बन्द कर दिया जाये। 6 सार्वजनिक इकाईयों (2 केन्द्रीय व 4 राज्य उद्यम) अब पुनर्गठन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर चुकी है और अब उन्हें अस्वस्थ इकाईयों की श्रेणी में से हटा दिया गया है।



214 कम्पनियों को रूग्ण नहीं माना गया और योजना के कार्यान्वयन के बाद उन्हें लाभोन्मुख स्थिति के आधार पर रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम की सीमा से हटा दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 225 सन्दर्भों में से 157 सन्दर्भों (केन्द्र सरकार के 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) को नवम्बर 1998 तक पंजीकृत किया गया था। केन्द्र सरकार के 21 सार्वजनिक उपक्रमों तथा राज्य के 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये पुनर्वास योजनाये स्वीकृति की गयी थी। यह सिफारिश की गयी थी कि केन्द्र सरकार के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य के 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब रूग्ण नहीं माना गया है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निष्पादित मामलों में गिरावट आई है। यह वर्ष 1996 में, 275 से घटकर वर्ष 1997 में 188 हो गये तथा वर्ष 1998 (नवम्बर तक) में इसमें और गिरावट होकर 127 मामले रह गये।

रूग्ण इकाईयों के सम्बन्ध में नवम्बर 1999 तक बी0आईएफ0आर0 के पास निजी कम्पनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में 4001 मामले आये। 2841 पंजीकृत मामलों में से 516 मामलों को रद्द कर दिया गया, 646 मामलों में पुनर्निर्माण योजनाओं को अनुमोदन दिया गया। जबकि 656 मामलों को विभिन्न हाईकोर्टों में भेज दिया गया ताकि परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की जा सके। पुनर्निर्माण योजनाओं

को सफलतापूर्वक लागू करने के कारण 223 कम्पनियों को अस्वस्थ इकाईयों की श्रेणी में से हटा दिया गया।

अपनी स्थापना से लेकर नवम्बर 1999 तक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के तहत निजी कम्पनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में 4001 मामले आये। 2841 पंजीकृत मामलों में से 516 मामले को रद्द कर दिया गया, 646 मामलों में पुनर्निर्माण योजनाओं को अनुमोदन दिया गया जबकि 658 मामलों को विभिन्न हाईकोर्टों में भेज दिया गया ताकि परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की जा सके। पुनर्निर्माण योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने के कारण 223 कम्पनियों को अस्वस्थ इकाईयों की श्रेणी में से हटा दिया गया।

बोर्ड यदि आवश्यक समझे तो किसी कार्यशील संस्था को आदेश द्वारा अस्वस्थ औद्योगिक इकाई के मामले को जाँचकर रिपोर्ट देने के लिये कह सकता है। जाँच जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिये और इस कार्य के लिये 60 दिन से ज्यादा समय नहीं लगाया जाना चाहिये। यह निश्चित हो जाने पर कि औद्योगिक इकाई अस्वस्थ ही है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यह तय करेगा कि इस इकाई के बारे में किस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में तीन बातें की जा सकती हैं।

१. कम्पनी विशेष को समय दिया जाय ताकि वह बैंको अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा शुरू की गई योजना के अनुसार उचित समय में अपनी विशुद्ध पूँजी की मात्रा को ठीक कर सके।

२. किसी भी कार्यशील कम्पनी के माध्यम से कम्पनी विशेष के बारे में पुनरुद्धार योजना तैयार करवाये।

३. यदि किसी कार्यशील सस्था के द्वारा अस्वस्थ औद्योगिक इकाई को फिर से स्वस्थ बनाने के लिये योजना तैयार करना तय होता है तो निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं -

i. अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी का पुनर्निर्माण अथवा पुनरुद्धार,

ii. अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी के प्रबन्ध के उचित व्यवस्था के लिये प्रबन्ध को बदलना या प्रबन्धन अपने हाथ में ले लेना।

iii. अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी को किसी अन्य कम्पनी में मिला देना

वर्ष 1998 की एक अधिसूचना के द्वारा सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को एक संवैधानिक निगम में बदल दिया और इसका नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक रखा गया इस बैंक की अधिकृत और प्रदत्त पूँजी क्रमशः 200 करोड रुपये और 50 करोड रुपये है। मार्च 1999 के अन्त तक इस पुनर्निर्माण बैंक ने कुल 1,500 करोड रुपये की सहायता मन्जूर की जिसमें से 1100 करोड रुपयों के ऋणों का वितरण हुआ।

**6. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) :-**

अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत भारत सरकार ने जनवरी 1987 में औद्योगिक वित्त एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की थी। अस्वस्थ और कमजोर औद्योगिक

इकाईयों के लिये यह जरूरी है कि ये अपनी स्थिति के बारे में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को लिखें। बोर्ड के लिये अस्वस्थ इकाईयों के बारे में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। यदि बोर्ड आवश्यक समझे तो किसी कार्यशील संस्था द्वारा अस्वस्थ औद्योगिक इकाई के मामले की जाँच करवा सकता है। परन्तु जाँच में 6 दिन से ज्यादा समय नहीं लगाया जाना चाहिये यदि बोर्ड को विश्वास हो जाये कि यह कम्पनी वास्तव में अस्वस्थ है तो बोर्ड ही कम्पनी के बारे में कार्यवाही के लिये नीति निर्धारित करेगा।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास सितम्बर 1993 तक अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के तहत 1924 मामले आये जिनमें से 506 मामले को आरम्भिक जाँच के बाद अस्वीकार कर दिया। 1409 पंजीकृत मामले में से 272 मामलों को रद्द कर दिया गया, 415 मामले में पुनर्निर्माण योजनाओं को अनुमोदन दिया गया जबकि 242 मामलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में भेज दिया गया ताकि परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की जा सके।

मार्च 1998 तक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के 3143 मामले आये। इनमें से 2415 पंजीकृत मामलों में से 425 को रद्द कर दिया गया, 625 मामलों में पुनर्निर्माण योजनाओं का अनुमोदन किया गया जबकि 579 मामलों को परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही के लिये विभिन्न हाईकोर्टों में भेज दिया गया।

नवम्बर 1998 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को 3441 सन्दर्भ प्राप्त हुये हैं जिसमें केन्द्र और राज्य के 225 लोक उपक्रम शामिल थे। इनमें से 2404 सन्दर्भ रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत पंजीकृत थे। जबकि 452 सन्दर्भों को अधिनियम के अधीन सुरक्षित न रखने योग्य मानकर खारिज कर दिया गया। बी० आई० एफ० आर० द्वारा 28 योजनाओं सहित 637 पुनर्वास योजनाओं को स्वीकृत किया गया था और 606 कम्पनियों को जल्द बन्द करने की सिफारिश की गयी थी।

### 7. गोस्वामी समिति की रिपोर्ट :-

औद्योगिक क्षेत्र के विकास में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करने के लिये तथा असक्षम इकाईयों को जल्दी सक्षम बनाने तथा सक्षम इकाईयों के पुनर्निर्माण के लिये सुझाव देने हेतु सरकार ने मई 1999 में औद्योगिक अस्वस्थता तथा निगम पुन संरचना से सम्बन्धित एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी थे तथा इस समिति ने जुलाई, 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे।

- i. इस समिति ने सुझाव दिया कि पूर्ण अस्वस्थता तक इन्तजार करने की अपेक्षा आरम्भिक अस्वस्थता पर अधिक ध्यान देना चाहिये। इस परिभाषा के अनुसार वह औद्योगिक इकाई अस्वस्थ मानी जानी चाहिये जो वित्तीय संसाधन प्रदान करने वाली संस्थाओं को कम से कम 180 दिन तक किश्तों

का भुगतान न कर पाई हो, तथा जिसकी नकदी-साख में कम से कम 180 दिन तक अनियमितताएँ बनी रही हो।

**ii.** समिति के अनुसार, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड मामले का निपटारा करने में बहुत देरी लगता है। जिसका अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः समिति ने सुझाव दिया कि बोर्ड को परिसमापन से सम्बन्धित कदम उठाने चाहिये ताकि अक्षम इकाईयों को जल्दी बन्द किया जा सके।

**iii.** समिति ने अक्षम इकाईयों को बन्द करने से सम्बन्धित कार्यवाही को जल्दी पूरा करने के उद्देश्य से पाँच परिसमापन अधिकरण मुम्बई, दिल्ली, बंगलोर, मद्रास व कलकत्ता में स्थापित करने का सुझाव दिया।

**iv.** समिति ने औद्योगिक इकाईयों से ऋणों की वसूली के लिये पाँच वसूली अधिकरण गठित करने का सुझाव दिया। जिसमें केवल 50 लाख रुपये से अधिक राशि वाले मामले पर ही विचार किया जायेगा।

**v.** चूँकि वर्तमान में अस्वस्थ औद्योगिक इकाई के लिये यह कानून जरूरी है कि वह औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में अपना मामला दर्ज कराये। परन्तु समिति ने यह सुझाव दिया कि बोर्ड में मामला दर्ज कराना अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होना चाहिये। इस सम्बन्ध में समिति ने विश्वास व्यक्त किया कि अनेक मामलों का निपटारा इकाईयों बोर्ड से बाहर आपसी बातचीत द्वारा कर लेती है।

**vi.** समिति ने यह सुझाव दिया कि अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों के लिये श्रमिकों को निकालते समय अथवा इकाई को बन्द करते समय सरकारी

अनुमति आवश्यक नहीं होनी चाहिये। अतः इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अधिनियम में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

इस प्रकार समिति के उपरोक्त सुझावों से बात स्पष्ट होती है कि समिति ने अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों के पुनर्निर्माण करने की अपेक्षा उन्हें बन्द करने पर अधिक जोर दिया है। अतः इन सुझावों के परिणाम कुछ हद तक प्रतिकूल भी हो सकते हैं।

**अस्वस्थता जल्दी पता लगाने के लिये उठाने गये कदम:—**

रिजर्व बैंक ने समय-समय पर प्रारम्भिक अवस्था में ही अस्वस्थता का पता लगाकर उसे दूर करने के उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जिन वर्गों की औद्योगिक इकाईयों अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत नहीं आती उनके बारे में रिजर्व बैंक ने बैंकों को सुझाव दिया है कि जैसे ही इनमें से कोई भी औद्योगिक इकाई कमजोर हो जाती है अर्थात् उसकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक विशुद्ध पूँजी नष्ट हो जाती है वैसे ही उसको पुनः स्वस्थ बनाने के लिये उपाय शुरू कर देना चाहिये। अब तक रिजर्व बैंक ने व्यवहार में अपनाये जाने वाले जो भी निर्देशक सिद्धान्त अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों के बारे में जहाँ अस्वस्थता व्यापक है नियमित रूप से जानकारी प्रदान करता है। जूट और चीनी उद्योग के लिये रिजर्व बैंक में स्थायी समितियों गठन हुआ है। ये समितियाँ समय-समय पर अपनी बैठकों में अपने-से सम्बन्धित उद्योगों की समस्याओं पर विचार कर उचित उपायों को निर्धारित करती हैं।

## वित्तीय समस्या जो सम्बन्धित उपाय :-

अधिकतर उद्योग वित्त के अभाव में ही रुग्ण हो गयी है। अधिकांश रुग्ण इकाईयाँ वित्तीय संस्थाओं एवं बैंक द्वारा प्राप्त करने वाली इकाईयाँ हैं। इनको आवश्यक पूरी पूँजी एक साथ उपलब्ध नहीं की जाती तथा पूँजी की मात्रा भी कम रहती है अतः पूर्ण वित्त के अभाव में संक्षम उत्पादन न कर पाने के कारण रुग्ण हो जाती है। वित्त प्राप्त करने के लिये लम्बे प्रावधान हैं, इन प्रावधानों में अधिक समय लगता है। और इकाईयाँ रुग्ण हो जाती हैं। अतः वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण पर्याप्त मात्रा में तथा कम समय में ही उपलब्ध कराये जाय तथा वित्त प्राप्त करने वाले प्रावधानों को सरल एवं ग्राह्य बनाया जाय। ताकि अन्य इकाईयाँ जो इस समय वित्त की सहायता से कार्यरत हैं तथा भविष्य में स्थापित होने वाली हैं वित्त के अभाव एवं अपर्याप्तता से रुग्ण न होने पायें। रुग्णता की स्थिति में पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत भी एक महीने के निर्धारित समय से कई महीने या वर्ष लग जाते हैं। वेक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा एक कार्यदल का गठन किया जाय जो समय-समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करे तथा आवश्यक सुझाव दे जिससे इकाईयाँ रुग्ण न होने पायें।

## शक्ति/ऊर्जा जो होने वाली रुग्णता का समाधान :-

ऊर्जा या शक्ति की अनियमितता एवं कमी उद्योगों को रुग्णता की श्रेणी में खड़ी करती चली जा रही है। यदि शक्ति/विद्युत का तुरन्त उपचार नहीं किया गया तो रुग्णता की स्थिति को और अधिक जटिल बना



देगी। यदि रागय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में और इकाईयाँ रुग्ण हो जायेगी। उद्योगों को रुग्णता से बचाने के लिये विद्युत केन्द्र खोलें जाय, ऊर्जा की कमी से रुग्ण होने वाली इकाईयो को तुरन्त ऊर्जा या जनरेटर की व्यवस्था की जाये। लोक उद्योगों को जनरेटर खरीदने के लिये 50% की सब्सिडी दी जाती है लेकिन इससे उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है इसके फलस्वरूप रुग्णता भी बढ़ सकती है। लोक उद्योगों को जनरेटर सेट किस्त प्रणाली पर दिया जाय तथा किस्त की रकम न्यूनतम हो जिससे उद्योगों को अदा करने में कोई कठिनाई न हो। दूसरी तरफ विद्युत विभाग को अपने कार्यों में सुधार की आवश्यकता है। सड़क और गलियों में बिजली दिन भर जलती रहती है उसको दिन में बुझाने की व्यवस्था हो, इससे भी कुछ ऊर्जा बचेगी जो उद्योगों में काम आ सकती है। इसके साथ विद्युत चोरी को रोका जाय इससे ऊर्जा की बचत होगी जिससे उद्योगों की रुग्णता को कम किया जा सकता है और भविष्य में विद्युत से होने वाली रुग्णता को रोका जा सकता है। सरकार द्वारा औद्योगिक आस्थानों में अलग विद्युत उत्पादन केन्द्र खोला जाय अथवा सौर ऊर्जा स्थापित किया जाय इसके अतिरिक्त उद्योग भी व्यर्थ शक्ति बरबाद न करें विद्युत की बचत से विद्युत का उत्पादन होगा जो उद्योगों के काम में आयेगी अतः इस प्रकार उद्योगों को रुग्णता से बचाया जा सकता है। और भविष्य में विद्युत की कमी से होने वाली रुग्णता से बचा जा सकता है।

## माँग के अभाव में होने वाली कठ्णता से सम्बन्धित उपाय :-

माँग के अभाव में इकाईयाँ रुग्ण हो जा रही हैं। अतः रुग्णता न होने देने के लिये लोक उद्योगों द्वारा उत्पादित मालो की माँग बढ़ायी जानी चाहिये। इसके लिये निदेशालय द्वारा एक विक्रय सस्थान खोला जाना चाहिये जहाँ ऐसी इकाईयो द्वारा उत्पादित मालो का ही विक्रय हो। इसके अतिरिक्त उद्योगो को अपनी वृद्धि बढ़ाने के लिये उत्पादो के साथ मुफ्त उपहार योजना को आरम्भ करना चाहिये इससे उनकी मालो की माँग में वृद्धि होगी। उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिय उचित किस्म तथा कम मूल्य निर्धारित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त मेलो, प्रदर्शनियों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे उद्यमी अपने उत्पादों को सामने ला सकें और विक्री में वृद्धि हो सकें। इस प्रकार जो रुग्ण हो रही है या रुग्ण हो होने वाली है उनको बचाया जा सकता है।

## उत्पादन के अभाव में होने वाली कठ्णता की रोकथाम:-

उत्पादन कम रहने के कारण होने वाली रुग्णता को अधिक क्षमता द्वारा कम किया जा सकता है तथा भविष्य में रोका जा सकता है। कभी-कभी उत्पादन क्षमता में कमी संयंत्रों की कमी या संयंत्रों के पुराने हो जाने के कारण होती है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये उद्यमियों को अपने संयंत्रों का उचित रख-रखाव करना चाहिये तथा समय-समय पर जाँच पड़ताल कराना चाहिये। प्रायः देखा गया है कि उद्यमी संयंत्रों का उचित रख-रखाव नहीं करते उन्हें चाहिये कि उस पर ध्यान दे तथा समय-समय

पर जॉच पडताल करें, उपकरणों की क्रियाशीलता तथा उत्पादन की अबाध सम्पन्नता, सुनियोजित कारखाना अनुरक्षण पर भी निर्भर करता है। इससे श्रेष्ठ कार्य क्षमता एवं कम लागत आती है। यदि उत्पादन में कमी सयत्रों में कमी के कारण हो रही है तो अविलम्ब उसकी पूर्ति करना चाहिये। जिला निदेशालय द्वारा उत्पादन बढ़ाने के तरीकों को ऐसे उद्योगों में एक दल समय-समय पर भेज कर उद्योगों की समस्याओं आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहिये तथा उन समस्याओं का निदान करने तथा उनके उत्पादन बढ़ाने के तरीकों की समीक्षा करनी चाहिये इस प्रकार वर्तमान में उद्योगों में रुग्णता को दूर किया जा सकता है और भविष्य में इस कारण से होने वाली रुग्णता को रोका जा सकता है।

### **गुण नियंत्रण के अभाव से होने वाली रुग्णता के उपाय:-**

गुण नियंत्रण के अभाव के कारण रुग्ण उद्योगों को बचाने के लिये जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संचालित गुण चिन्हांकन के द्वारा तुरन्त लाभान्वित किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी लोक उद्योगों को चिन्हांकन योजना की तहत लाया जाय या उनके लिये अनिवार्य बनाया जाय। आवश्यकता इस बात की है कि जनपद में एक ही केन्द्र पर सभी प्रकार की वस्तुओं का चिन्हांकन किया जाय। इसके अतिरिक्त निश्चित समय पर उनका पुनः निर्धारण किया जाय। और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाये। उद्यमियों को भी चाहिये कि अपनी वस्तुओं की किस्म अच्छी रखे तभी उनकी वस्तुएं बार-बार बिकेंगी तथा अधिक मात्रा में बिक पायेंगी। इस

प्रकार उच्च गुण नियन्त्रण बनाये रखकर वर्तमान तथा भविष्य के उद्योगों को रुग्णता से बचाया जा सकता है।

### **प्रबन्धकीय अक्षमता एवं अज्ञानता सम्बन्धी रुग्णता को दूर करना :-**

यदि उद्योग के प्रबन्धक के पास प्रबन्धकीय निर्देशन, नियन्त्रण, वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कार्यक्षमता नहीं है तो उसका उपयोग नहीं कर पाते और इकाई रुग्ण होती चली जाती है। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक वर्तमान तथा भविष्य में संचालित तरह-तरह की सुविधाओं, आधुनिक तकनीकों आदि की जानकारी न रखने के कारण उसका लाभ नहीं उठा पाते फलस्वरूप उद्योग रुग्णता के कगार पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार की रुग्णता की रोकथाम के लिये वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा केवल उन्हीं उद्यमियों को ऋण दिया जाय जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रबन्धकीय योग्यता प्राप्त किये हों। उद्यमी प्रबन्धकीय क्षमता की उचित प्रयोग कर अपने उद्योगों के रुग्णता को नहीं आने देता है। जिला उद्योग निदेशालय द्वारा भी उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि उद्यमियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो और निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण पर और अधिक ध्यान दिया जाय। वर्तमान में तथा भविष्य में इस कारण से होने वाली रुग्णता के निदान के लिये प्रशिक्षण व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाय तथा समय-समय पर गोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाय और उद्यमी को इस सम्बन्ध में जानकारी दी जाय। इस प्रकार वर्तमान

में तथा भविष्य में इस कारण से होने वाली रुग्णता को काफी सीमा तक हल किया जा सकता है।

### **सामाजिक कारणों से होने वाली रुग्णता की रोकथाम के उपाय :-**

समाज में अक्सर ऐसी घटनायें घटती रहती हैं जिससे उद्योगों को भारी क्षति पहुँचती है। इस असम्भाविकता को टाला नहीं जा सकता। इस प्रकार से होने वाली रुग्णता से बचाव के लिये उद्योग निदेशालय या अन्य ऐसी किसी संस्था का निर्माण करे जो लोक उद्यमों का बीमा कराये। इस योजना में प्रीमियम की राशि न्यूनतम रखी जाय। इस प्रकार सामाजिक कारणों से भविष्य में होने वाली रुग्णता को दूर किया जा सकता है।

### **मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाली रुग्णता की रोकथाम के उपाय :-**

उद्योगों की रुग्णता का मनोवैज्ञानिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक कारण ही सभी प्रकार की रुग्णता का आधार है। इस प्रकार की रुग्णता से बचाने के लिये उद्यमियों को अपने आप को नम्र तथा विनम्र बनाये रखना चाहिये तथा दूसरों के साथ सहयोग का सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये। प्रबन्धकों को दूसरों तथा श्रमिकों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये। मानवीय सम्बन्ध श्रमिकों के मनोबल, कार्यप्रेरणा एवं सहयोग की भावना को प्रेरित करती है। प्रबन्धकों को श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये यदि श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं तो श्रमिकों का मनोबल बढ़ेगा और वे उन्हें सहयोग प्रदान कर

उद्यम की कार्यकुशलता में वृद्धि करेंगे। प्रायः देखा जाता है कि प्रबन्धक अपने को बहुत उच्च समझने लगते हैं और श्रमिकों को बहुत निम्न दृष्टि से देखते हैं इससे श्रमिकों का मनोबल गिर जाता है। अतः प्रबन्धकगण श्रमिकों को जीवन निर्वाह हेतु उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुविधायें, उचित आचरण, अवकाश आदि देने की सुविधाये देकर इस प्रकार की रुग्णता से बच सकते हैं।

### **औद्योगिक अस्वस्थता के परिणाम :-**

भारत जैसी आयोजित और अल्प विकसित अर्थ व्यवस्था में जिसमें श्रम की आपूर्ति जरूरत से ज्यादा है, औद्योगिक अस्वस्थता के निम्नलिखित गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

#### **1. रोजगार की सम्भावना को धक्का लगना :-**

भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें श्रम की आपूर्ति जरूरत से ज्यादा है। यहाँ पर रोजगार चाहने वालों की तुलना में रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी औद्योगिक इकाई के बन्द हो जाने पर जो मजदूर होंगे उन्हें फिर से काम मिलने की गुंजाईस कम ही होगी। इस दृष्टि से समस्या उस समय बहुत ही गम्भीर होगी जब बन्द होने वाली अस्वस्थ औद्योगिक इकाई सूती कपड़ा मिल की तरह बहुत हो और उसमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा हो।

#### **2. औद्योगिक अशान्ति की सम्भावना :-**

अस्वस्थ औद्योगिक इकाई अगर कड़ी हो तो उससे बेरोजगारी बढ़ने के साथ-साथ औद्योगिक शान्ति भंग होने का खतरा रहता है। ऐसी

स्थिति में अन्य औद्योगिक इकाईयों से जुड़े श्रम सघ भी अस्वस्थ इकाई को बन्द करने का विरोध करते हैं और व्यापक स्तर पर हड़तालें होती हैं। इससे औद्योगिक वातावरण की शान्ति भंग होता है। जिसके फलस्वरूप अनेक औद्योगिक इकाईयों में उत्पादन का स्तर गिरता है और उन्हें मुनाफों की दृष्टि से नुकसान होता है।

### 3. साधनों का अपव्यय :-

अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था में साधनों में कमी होती है ऐसी स्थिति में यदि कोई भी औद्योगिक इकाई अस्वस्थ होकर बन्द हो जाये तो उसमें लगे हुये साधन बेकार हो जाते हैं। यह समस्या उस समय बहुत गम्भीर हो जाती है। जब अस्वस्थ इकाईयों बहुत बड़ी होती हैं और उनमें मशीनों और संयंत्र में पूँजी का भारी निवेश होता है। इन इकाईयों में उत्पादन बन्द हो जाने पर पूरे उद्योग का उत्पादन गिर जाता है और कीमती पूँजीगत उपकरण के रूप में उपयोगी बचतें फँस जाती हैं।

### 4. सम्बन्धित इकाईयों पर बुरा असर :-

बहुत बार औद्योगिक इकाई अग्रगामी और पश्चगामी सम्बद्धताओं के द्वारा दूसरी औद्योगिक इकाईयों से जुड़ी होती है। अतः एक इकाई अस्वस्थ हो जाने पर उसका दूसरा इकाईयों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उदाहरण के लिये, लोहा और इस्पात उद्योग, एक ओर लोहा, कोयला, मैंगनीज, चूना आदि खनन उद्योगों से जुड़ा होता है तो दूसरी ओर उसका सम्बन्ध भारी इंजीनियरिंग, मशीनी औजार, भवन निर्माण, रेल परिवहन इत्यादि उद्योगों से होता है। उसी स्थिति में यदि लोहा और इस्पात का

उत्पादन करने वाला बड़ा कारखाना अस्वस्थ हो जाये तो उसका उपरोक्त उद्योगो पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

### 5. निवेशकों और उद्यम कर्ताओं पर बुरा प्रभाव :-

किसी बड़ी अस्वस्थ औद्योगिक इकाई के बन्द हो जाने पर निवेशकों में निराशा उत्पन्न होती है। अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों के शेयरों की कीमते एकदम नीचे गिरती है। और उसमें उत्पन्न व्यापक निराशा के वातावरण में सम्पूर्ण शेयर बाजार की स्थिति बिगड़ सकती है। इसके अलावा एक इकाई की असफलता उन दूसरे उद्यमकर्ताओं को हतोत्साहित करती है जो उसी उद्योग में उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहे होते हैं। कुल मिलाकर इस तरह का औद्योगिक विकास के लिये अनुकूल नहीं होता।

### 6. बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं को हानियाँ :-

अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों के बन्द हो जाने पर उन बैंकों और दूसरी संस्थाओं को भारी नुकसान होता है। इन इकाईयों को सयत्रा और मशीनें खरीदने और उत्पादन के लिये कार्यशील पूँजी जुटाने के लिये ऋण दिया होता है। अस्वस्थ इकाईयों में पूँजी फँस जाने पर बैंकों और दूसरी संस्थाओं को उधार कार्यक्रम साधनों की कमी के कारण अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। हम पहले बता आये हैं कि भारत में मार्च 1998 के अन्त में बड़ी अस्वस्थ इकाईयों के पास 3,857 करोड़ रुपये के ऋण का बकाया था यद्यपि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थायें ऋण वापस न करने वाली औद्योगिक इकाईयों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हैं लेकिन एक तो इसमें समय बहुत लगता है और दूसरे उधार दिया गया पूरा रुपया वापस नहीं मिलता।



અધ્યાય-સાત

મુખ્ય નિષ્કળાં એવં સુજ્ઞાવ

आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र के तीव्र आर्थिक विकास में लोक उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत एक विकासशील देश है। भारत के त्वरित आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विषमता में कमी, रोजगार के अवसर का सृजन व जनसेवा के लिये लोक उद्यम अपरिहार्य है। हमारी राष्ट्रीय सरकार एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है। जिसमें देश में तीव्र गति से होने वाले औद्योगीकरण एवं राष्ट्रीय उत्पादन में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले। इसी कारण से उत्पत्ति हुई 'राजकीय हस्तक्षेप' एवं 'राजकीय उपक्रम' की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी जनतन्त्रात्मक सरकार ने 'समाजवादी समाज' की स्थापना का व्रत लिया है तथा इसकी प्राप्ति हेतु योजना बद्ध अर्थ प्रबन्धन के पुनीत कर्तव्य का सहारा लिया।

लोक उद्यमों का विकास बीसवीं शताब्दी की अत्यन्त क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। एक अर्थव्यवस्था में लोक उद्यमों की कार्यशीलता सामान्य रूप से जनता के लिये तथा विशेषकर आर्थिक क्रिया कलापो के लिये काफी लाभप्रद होती है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जनता के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिये सरकार को ही उत्तरदायी ठहराया गया है। इस प्रकार वर्तमान में सरकार नागरिकों एवं उद्यमियों के संरक्षक, नियन्त्रक तथा रक्षक की स्वयं भूमिका ग्रहण कर एक सक्रिय सहभागी के रूप में उभर कर आया है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पर जनता के आर्थिक कल्याण के लिये नियोजित आर्थिक विकास की भावना अपनायी गयी है।

## लोक उद्योग का आशय :-

लोक उद्योग से तात्पर्य सरकारी सरकारी स्वामित्व में स्थापित एवं नियंत्रित ऐसी स्वशासित अथवा अर्धस्वशासित निगमों एवं कम्पनियों से है जो औद्योगिक और वाणिज्यिक क्रियाओं में लगी हो।

इस प्रकार उद्यम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार द्वारा स्थापित सभी उद्योग सम्मिलित हैं, भारतवर्ष में राज्य स्तर पर लोक उद्यम व केन्द्रीय सरकार के अधीन भी लोक उद्यम कार्य कर रहे हैं। इसी तरह लोक उद्यम में विभागीय उद्योग कम्पनियाँ एवं सवैधानिक नियम सभी सम्मिलित किये जाते हैं चाहे उनकी स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी हो अथवा सरकार व स्थानीय सरकार द्वारा की गयी हो।

## लोक उद्यमों का औचित्य :-

भारत जैसे विकासशील देश के चतुर्दिक विकास में लोक उद्यमों का योगदान प्रशंसनीय है लोक उद्यमों ने देश को औद्योगिक क्षेत्र को सबल व आत्मनिर्भर बनाया है। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के पश्चात् ही देश त्वरित आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हुआ है। भारत देश के लिये लोक उद्यमों की स्थापना के अग्रलिखित औचित्य हैं:-

१. लोक उद्यमों के विकास पर ही नियोजन की सफलता निर्भर करती है। निजी उद्यम नियोजन की सफलता के लिये कोई भी कार्य नहीं करते हैं क्योंकि निजी उद्योगपतियों का हित निजी उद्यम में विद्यमान रहता है। सामाजिक व

आर्थिक विकास में तीव्रता एवं स्वामित्व लाने के लिये ही लोक उद्यमों की स्थापना की जाती है जबकि निजी उद्योगपति इन कार्यों में अपनी हित की अविद्यमानता के कारण विनियोजन करने के लिये तत्पर नहीं होते।

2. देश के त्वरित आर्थिक विकास में लोक उद्यमों का योगदान अद्वितीय है। वस्तुओं के उत्पादन एवं पूँजी निर्माण दर को बढ़ाने के लिये सरकार का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के विकास के लिये परम आवश्यक होता है।

3. निजी उद्यमों में कम विनियोग कर अल्पसमय में अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति होती है। जबकि देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिये रेलवे, सड़क, दूर-संचार, ऊर्जा, वायु यातायात, डाक, बैंक तथा बीमा सम्बन्धी सुविधाओं का विकास होना आवश्यक है। इन सुविधाओं को विकसित करने के लिये काफी धन एवं समय की भी जरूरत पड़ती है। जो निजी उद्योग द्वारा संभव नहीं था इसलिये सरकार ने लोक उद्यमों के माध्यम से इन सुविधाओं का विकास किया जिससे कि देश में कृषि एवं उद्योगों का विकास शीघ्रता से किया जा सके।

4. आधारभूत उद्योगों के विकास के लिये काफी मात्रा में विनियोग की आवश्यकता होती है जो निजी उद्योगपतियों द्वारा संभव नहीं था इसलिये आधारभूत उद्योगों की स्थापना केवल लोक उद्यमों के रूप में की गयी जिससे देश के उद्योगों का तत्पर गति से विकास हुआ। आधारभूत उद्योगों से

तात्पर्य ऐसे उद्योगों से होता है, जिसके विकास से अन्य उद्योगों का विकास सम्भव हो जाता है।

५. प्राकृतिक ससाधनों के समुचित विदोहन व सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के लिये आर्थिक क्रिया-कलापों में सरकार का हस्तक्षेप परमावश्यक था जिससे देश निर्धन तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित की जा सके तथा क्षेत्रीय असमानता की खाई को पाटा जा सके।
६. भारत के संविधान में समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया गया है समाजवादी सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वह समाज को उद्योगपतियों व व्यवसायियों के शोषण से बचाने के लिए लोक उद्यमों की स्थापना करे।
७. सरकार को ठोस तकनीकी और पूँजी आधार की उपलब्धि के लिये भी लोक उद्यमों की स्थापना करनी पड़ती है इसलिये सरकार को लोक उद्यमों की स्थापना देश के आर्थिक विकास के लिये करनी पड़ती है।
८. भारत के लोक उद्यम सरकार द्वारा घोषित नीतियों, मूल्य स्थिरीकरण, औद्योगिक नियोजन तथा आयात प्रतिस्थापन आदि के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लोकोपयोगी सेवाओं की उपलब्धिता में लोक उद्यमों की एकाधिकार जैसी स्थिति है।

६ आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को लोक उद्यमों की सहायता से आसानी से रोका जा सकता है। लोक उद्यमों कमचारियों के नियुक्ति तथा श्रमिक सहभागिता का विकास करके प्रजातन्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।

१० लोक उद्यम अपने कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा, कैंटीन सुविधा, बीमारी के लिये चिकित्सा सुविधा, आने-जाने के परिवहन साधन आदि सुविधायों प्रदान करके आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभा रहा है। जबकि निजी उद्यम ऐसी सुविधाएँ नहीं प्रदान करते हैं वे अधिकतम लाभार्जन के लालच में जनता का शोषण करते हैं इसलिये लोक उद्यम रोजगार प्रदान करके व सेवा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करके आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभा रहे हैं।

### **भारत में लोक उद्यमों की आवश्यकता :-**

भारत एक विकासशील देश है किसी भी देश के आर्थिक विकास में लोक उद्यमों का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी देश बिना लोक उद्यमों के विकास के उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आसीन ही नहीं हो सकता। संसार के विकसित देशों के उत्तरोत्तर प्रगति का मूल आधार लोक उद्योग ही है। भारत के त्वरित आर्थिक विकास क्षेत्रीय विषमताओं में कमी रोजगार के अवसर का सृजन व जनसेवा के लिये लोक उद्यम अपरिहार्य है। प्राचीन काल में निजी उद्यमों का प्रचलन न था। अधिक लाभ प्राप्ति के प्रलोभन में जब निजी उद्योगपतियों द्वारा जनता को अधिक मूल्य पर वस्तु प्रदान करके

उनका शोषण किया जाने लगा तो सरकार को हस्तक्षेप करना ही पडा। जनसेवा की भावना व सवैधानिक प्रावधान के कारण सरकार को जनता की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लोक उद्यमों की स्थापना करनी ही पडी।

इन उद्योगों की स्थापना के अन्य महत्वपूर्ण कारण निम्न है।

1 सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है। पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथों में सकेन्द्रित हो जाती है। अतः भारत जैसे निर्धन देश में इस कुप्रथा को रोकने का काम काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र ने किया है। यद्यपि देश में अनेक बड़े औद्योगिक घराने मौजूद हैं परन्तु कुल परिसम्पत्ति में उनका हिस्सा बहुत कम है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र ने अनेक प्रकार से आर्थिक समानता लाने और गरीबी निवारण के लिये प्रयास किया है। सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त लाभों का प्रयोग निर्धनों के विकास एवं कल्याण हेतु विभेदात्मक नीति अपना सकती है। उन्हें अनेक प्रकार के छूट तथा सहायता दे सकती है। इसी प्रकार वह उपभोक्ता वस्तुओं को कम कीमत पर उपलब्ध करा सकती है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से ही नहीं की जाती बल्कि उनका उद्देश्य जनहित होता है। इसीलिये ऐसे उद्यमों की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में ही की जाती है जहाँ यद्यपि उनके लिए उपयुक्त दशाएं उपलब्ध नहीं होती परन्तु उनकी सहायता से उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर

किया जा सकता है। उदाहरणार्थ भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के इस पिछड़े क्षेत्र में करने का एकमात्र उद्देश्य क्षेत्रीय विकास तथा वहाँ विकास की लहरे उत्पन्न करना रहा है पूर्वोत्तर राज्यों उड़ीसा, बिहार आदि पिछड़े राज्यों में भी अनेक उद्योग स्थापित किये गये हैं।

3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का तीव्र गति से विकास हुआ औद्योगीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का ही परिणाम है। लोहा व इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, भारी रसायन, उर्वरक, भारी रसायनिक उर्वरक, भारी विद्युत उपकरण एवं अन्य खनिज प्रतिरक्षा सम्बन्धी आदि का अधिकांश विकास सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रयासों से हुआ है। इन विशालकाय उद्योगों के लिये भारी पूँजी की आवश्यकता लोक उद्यमों और लम्बी परिचालन अवधि के कारण निजी क्षेत्रों की असमर्थता को सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से ही पूरा किया गया है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र जिन उपभोक्ता वस्तुओं की ओर अधिक झुकाव रखते हैं, उनका उत्पादन भी सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा लोहा व इस्पात, विद्युत उत्पादन और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों के आधार पर ही हुआ है।

4. सम्पूर्ण योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश में महत्वपूर्ण अंश रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक का कुल निवेश आधे से अधिक रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवी तथा छठी योजनाओं में कुल विनियोग का 54%, 54%, 60%, 59%, 57.7% और 53% भाग सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया, सातवी पंचवर्षीय योजना में यह 47%



रखा गया जो आठवी पंचवर्षीय योजना में और घटकर 45% पर आ गया। वास्तव में आठवी पंचवर्षीय योजना तक आते-आते सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारत का निजी क्षेत्र काफी हद तक स्वावलम्बी हो गया है और देश के विकास में अधिक भागीदारी निभा सकता है।

यदि पूँजी निर्माण के आंकड़ों का अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश का कुल घरेलू पूँजी निर्माण सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 7% ही था, जो सातवी पंचवर्षीय योजना में 22-8% तक पहुँच गया। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र का भाग इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः 35% से बढ़कर 42.1% हो गया। इस योजना अवधियों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के पूँजी निर्माण योगदानों का अनुपात क्रमशः 33.67 से 47.53 हो गया।

जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्रों में कुल बचत में योगदान का प्रश्न है, यह उत्साहजनक नहीं रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 17% था तो छठी पंचवर्षीय योजना में 36% तक ही पहुँच सका। सापेक्षिक रूप में प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसका योगदान 17% था जो चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल बढ़कर 21% हो गया परन्तु इसके पश्चात् से इसमें ह्रास होने लगा और छठी पंचवर्षीय योजना में 18% और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 11% के स्तर पर आ गया। इस ह्रास के लिये अनेक कारण उत्तरदायी हैं। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक उद्यमों ने तो

बचत करने में अपना योगदान बढ़ाया है परन्तु प्रशासनिक विभाग सदैव घाटे में चलते रहे हैं और बचत में उनका योगदान ऋणात्मक रहा है। आठवीं पंचवर्षीय व नौवीं पंचवर्षीय योजना में यह 43% व 45% बनी रही। इस प्रकार पूँजी की निर्माण दर में उच्चावचन की स्थिति बनी रही।

5. आर्थिक विकास हेतु अध. सरचना का विकसित होना आवश्यक है। सड़क, रेल आदि परिवहन के साधन संचार की सुविधाएँ, ऊर्जा का उत्पादन तथा वितरण आदि सुविधाओं के अभाव में कृषि उद्योग या सेवाओं का विकास असम्भव है। इन तत्वों के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान अद्वितीय रहा है। इन सेवाओं तथा उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र का 30 हजार करोड़ रु० से भी ज्यादा निवेशित है। वास्तव में भारत का वर्तमान औद्योगिक विकास सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा तैयार किये गये मजबूत अध. सरचनात्मक आधार पर ही हुआ है।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत सिर्फ वस्तु उत्पादक इकाईयों में ही नहीं, बल्कि सेना प्रशासनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, शोध आदि गतिविधियों में भी रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं। लोक उद्यमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है जिससे भारत के शिक्षित नवयुवकों को रोजगार आसानी से उपलब्ध हो सके।

7. सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक ऐसे उद्योगों की स्थापना की गई है जिनके उत्पाद भारत को पूर्वकाल में विदेशों से आयात करने पड़ते थे। जैसे— भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन 'ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, तेल एवं

प्राकृतिक गैस आयोग, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान ऐटीबायोटेक्स लिमिटेड आदि इकाईयों में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है।, जो देश के लिये अत्यन्त आवश्यक है और देशी उत्पादन न होने पर उनका विदेशों से आयात अनिवार्य होता है। यद्यपि अभी देश इन वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र के इन वस्तुओं का उत्पादन करके बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत की है।

8. सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है। पूँजीवादी समय में आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथों में सकेन्द्रित हो जाती है, अतः भारत जैसे—निर्धन देश में इस कुप्रथा को रोकने का काम काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा किया गया है। यद्यपि देश में अनेक बड़े औद्योगिक घराने मौजूद हैं परन्तु कुल परिसम्पत्ति में उनका हिस्सा बहुत कम है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र ने अनेक प्रकार से आर्थिक समानता लाने और गरीबी निवारण के लिये प्रयास किया है। सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त लाभों का प्रयोग निर्धनों के विकास एवं कल्याण हेतु किया जाता है। सरकार छोटे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने हेतु विभेदात्मक नीति अपना सकती है उन्हें अनेक प्रकार के छूट तथा सहायता दे सकती है अपने उद्यमों में विभेदात्मक वेतन नीति अपना सकती है। इसी प्रकार वह उपभोक्ता वस्तुओं को कम कीमत पर उपलब्ध करा सकती है।

## कठ्ठाता के निष्पत्ति के लिये उपाय :-

१. विद्युत व कच्चे माल की नियमित आपूर्ति
२. सरकारी नीति का सदुपयोग
३. माग में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयास
४. साख पर समुचित नियंत्रण
५. लाभार्जन में वृद्धि का प्रयास
६. पूँजी का समुचित उपयोग
७. मानव शक्ति का समुचित उपयोग
८. कीमत नीति में सुधार
९. संयंत्र एवं मशीनों का आधुनिकीकरण
१०. सामर्थ्य का समुचित प्रयोग
११. कुशल प्रबन्धन
१२. समुचित आयोजन एवं नियंत्रण
१३. श्रमिक सहभागिता का विकास
१४. सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग
१५. उत्पादन लागत में कमी का प्रयास
१६. अत्याधुनिक तकनीक व मशीनों का प्रयोग
१७. उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण

१८. स्पष्ट उद्देश्यो एवं लक्ष्यो का निर्धारण

१९. संगठनीय समस्याओं का निराकरण

२०. विपणन का समुचित प्रबन्ध

२१. लोक उद्यमों की प्रत्येक मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये

२२. रुग्ण इकाईयों के पुनरुद्धार के लिये वित्तीय एवं पुनर्निर्माण परिषद को सौंप देना चाहिये।

### **प्रमुख निष्कर्ष :-**

भारत जसे विकासशील देश में लोक उद्यमों की स्थापना राजकोष में योगदान, समाजवादी समाज की स्थापना, जनता को कम मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धि तथा आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाते हुये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये की गयी थी। लोक उद्यमों ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। परन्तु कुछ समस्याओं के कारण ये आशाजनक सफलता प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। यदि सरकारी राजनीतिक व सामाजिक तत्वों तथा प्रबन्धक कर्मचारी व श्रमिकों द्वारा एकजुट प्रयास किया जाय तो निश्चय ही लोक उद्यमों में व्याप्त समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। यदि सही समय पर इसकी समस्याओं के निराकरण के लिये प्रयास किया जाय तो निश्चय ही लोक उद्यम अपनी समस्याओं से निजात पा लेंगे और ये सफलता की ऊँचाइयों पर अवश्य ही पहुँच जायेंगे। लोक उद्यमों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिये यदि प्राथमिक स्तर पर ही उपचार की व्यवस्था की जाय तो निश्चय ही लोक उद्यमों का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। जब लोक उद्यमों का भविष्य उज्ज्वल रहेगा तो देश

औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा तथा देश का सन्तुलित त्वरित विकास होगा।

लोक उद्यमों का विस्तृत व विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत के त्वरित आर्थिक विकास में लोक उद्यमों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार क्षेत्रीय विषमताओं में कमी, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार अवसर सृजन आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिसके विकास में लोक उद्यमों ने अद्वितीय योगदान दिया है परन्तु लोक उद्यमों ने आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में आशा के अनुरूप अधिक सफलता नहीं प्राप्त की है। व्यवहार में इन लोक उद्यमों को कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण ये आशाजनक सफलता प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। ये समस्याएँ अग्रांकित हैं.—

#### A. बाह्य कारण :-

१. सरकार की आयात निर्यात, औद्योगिक लाइसेंस तथा कराधान आदि की नीतियों में अचानक परिवर्तन से कठिनाई।
२. विद्युत की अनियमित आपूर्ति
३. कच्चे माल तथा अन्य आगतों की अपर्याप्त और अनियमित आपूर्ति
४. सरकारी नीति की अनुपयुक्तता
५. मांग में निरन्तर कमी
६. साख सम्बन्धी दोषपूर्ण नीति के कारण कठिनाई

## B. आन्तरिक समस्याएं :-

१. बढ़ती हुई हानियाँ
२. अधिपूँजीयन के कारण पूँजी की व्यवस्था करने में कठिनाई
३. आवश्यकता से अधिक मानव शक्ति का प्रयोग
४. दोषपूर्ण कीमत नीति
५. दोषपूर्ण संयंत्र एवं मशीनें
६. सामर्थ्य का अनुचित प्रयोग
७. दोषपूर्ण नियंत्रण
८. अकुशल प्रबन्ध
९. आयोजना एवं निर्माण की दशा में दोष
१०. श्रमिक एवं नियोक्ता के बीच टकराव
११. वित्त की पर्याप्त अनुपलब्धता
१२. उत्पादन लागत में वृद्धि
१३. तकनीकी पिछड़ापन
१४. उत्पादन के साधनों के जुटाव की समस्या
१५. स्पष्ट उद्देश्यों का अभाव व उद्देश्यों में टकराव
१६. उपयुक्त संगठन के चुनाव की समस्या
१७. विपणन में कठिनाई
१८. नियन्त्रण और हिसाब देयता सम्बन्धी समस्या

१६. उद्योगों के स्थापन-स्थान सम्बन्धी समस्या

२०. यंत्रों व संयंत्रों के उचित रख रखाव की समस्या

२१. रुग्ण इकाईयों से सम्बन्धित समस्याएँ

लोक उद्यमों में व्याप्त रुग्णता का निराकरण किया जाना समीचीन है। सरकार इस समस्या से निजात पाने के लिये 1991 से ही बहुत से लोक उद्यमों के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया है जिससे निजी उद्योगपति भी उन्नति कर सकें। टेलीफोन उद्यमों, विद्युत उद्योग जैसे महत्वपूर्ण लोक उद्यमों को भी सरकार द्वारा निजी उद्योगपतियों के हाथ में सौंपना निजीकरण का प्रमुख उदाहरण है। निजीकरण से ही समस्या का निदान नहीं होगा। रुग्णता के समस्या के निराकरण के लिये निम्न कदम भी प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं

### **रुग्ण इकाईयों से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने**

#### **के उपाय:-**

लोक उद्यमों में जो भी रुग्ण इकाईयें हो उन्हें बन्द कर दिया जाय। स्वस्थ लोक उद्यम इकाईयों के साथ रुग्ण इकाईयों को मिलाने से रुग्णता और फैलेगी। यह बेहतर होगा कि स्वस्थ लोक उद्यमों से कुछ योग्य प्रबन्धकों को रुग्ण इकाईयों में नियुक्त किया जाय तथा उन्हें एक निश्चित कार्यकाल की गारन्टी दी जाय। इसके साथ-साथ रुग्ण इकाईयों के पुनर्वास से



सम्बन्धित कार्यक्रम के लिये औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण परिषद को सौंप देना चाहिये। जिन लोक उद्यमों में वित्तीय समस्याएँ व्याप्त हो उनके लिये सरकार को हस्तक्षेप करके वित्तीय संस्थाओं से वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करवाना चाहिये। सतत रुग्णता तथा दीर्घकालीन ऋण दायित्व से इन रुग्ण इकाईयों में ऋण समय अनुपात काफी उच्च हो गया है। अतः एक स्वस्थ वित्तीय सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये। लोक उद्यमों के उत्पाद राजस्व अथवा करों की वसूली से एक विशिष्ट कोष बनाया जाना चाहिये जिससे कि उनके पुनर्वास हेतु स्ववित्तीयकरण सुविधा जुटाई जा सके। लोक उद्यमों में बढ़ती रुग्णता की जानकारी प्राप्त करने के लिये पूर्वानुमान विधि का प्रयोग करना चाहिये जिससे सम्भावित रुग्णता का तत्काल निदान किया जा सके। रुग्ण इकाइयों को अधिगृहीत करने के पहले प्रथम चरण में एक कार्ययोजना प्रारूप तैयार किया जाना चाहिये। इसमें उत्पादकता सुनिश्चित करने एवं अपव्यय व्यवहारों को समाप्त करने से सम्बन्धित बातों के लिये श्रमिकों से एक समझौता को भी शामिल किया जाना चाहिये। इकाई के रोजगार स्तर तथा पुनर्वास करने हेतु एक समय बद्ध प्रारूप तैयार किया जाना चाहिये। लोक उद्यमों के समक्ष एक बड़ी समस्या काम के अभाव की है। लोक उद्यमों द्वारा एक दीर्घकालीन योजना बनाकर उपलब्ध क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिये। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन उद्यमों को समुचित कार्यभार सौंपना चाहिये। लोक उद्यमों में व्याप्त रुग्णता की जाँच एक समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये जिससे

रुग्णता के बारे में यथाशीघ्र जानकारी प्राप्त हो सके और उसके रोकथाम के लिये आवश्यक कदम उठाया जा सके।

1. लोक उद्यमों के आर्थिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये, जिससे प्रबन्धकीय निष्पादन का मूल्यांकन सम्भव हो। परम्परागत बजटिंग के स्थान पर शून्य आधारित बजटिंग व्यवस्था का प्रयोग किया जाना चाहिये। वित्तीय नियोजन व बजटिंग व्यवस्था का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिये। लोक उद्यमों को सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन नहीं दिया जा रहा है, इसलिये इन्हें पूँजी व्यवस्था के लिये पूँजी बाजार का सहारा लेना चाहिये। इनके वित्तीय एवं लेखांकन परम्पराओं में सदैव एकरूपता स्थापित करनी चाहिये। वित्तीय एवं लेखांकन विसंगतियों से वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलता है। लागत नियंत्रण तथा लागत घेराव कार्यक्रमों को प्रबन्धकीय निष्पादन मूल्यांकन के लिये एक आधार के रूप में निश्चित किया जाना चाहिये इन सब के माध्यम से उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य में स्थिरता लाई जा सकती है वित्त पर ही किसी उद्यम की सफलता निर्भर करती है, इसके अभाव में तो एक कदम भी आगे बढ़ना असम्भव है, इसकी पर्याप्त उपलब्धता लोक उद्यम की सफलता की कुंजी है। यदि यह पर्याप्त रूप से उपलब्ध है तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न हो सकती। इसकी व्यवस्था पर प्रबन्धक को पूर्णतया ध्यान देना चाहिये नहीं तो सभी विकास कार्य ठप्प पड़ सकता है वित्त की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अतः इसके निदान के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उठाना परमावश्यक है।

2. लोक उद्यमों के लिये निर्धारित उद्देश्यों को प्रधान एवं सहायक उद्देश्य के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये लाभ कमाना भी इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। सामाजिक उद्देश्यों को सहायक उद्देश्यों के रूप में परिभाषित करके उनका वित्तीयकरण सृजित आधिक्य से किया जाना चाहिये अथवा उनकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में की जानी चाहिये। लोक उद्यमों के सफल परिचालन हेतु मुख्य अधिशासी तथा प्रबन्धकों के लिये स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिये। स्पष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्यों के उपलब्ध होने पर ही प्रबन्धकीय हिसाबदेयता को सुनिश्चित किया जा सकता है। आर्थिक व्यावहारिक रूप में सम्भावी प्रत्याय की दर का स्पष्ट निर्धारण उद्यमों में किया जाना चाहिये। सरकार को श्वेतपत्र जारी करके लोक उद्यमों के मुख्य उद्देश्यों व लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिये जिससे लोक उद्यमों के उद्देश्य निर्धारण में किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न न हो। लक्ष्य निर्धारित होने पर उसको प्राप्त करने की दिशा में लोक उद्यमों द्वारा भरसक प्रयास किया जायेगा, जो उन्हें उन्नति के मार्ग पर अवश्यमेव ले जायेगा।

3. संगठन में ही शक्ति निहित है; लोक उद्यम के कर्मचारीगण व प्रबन्धकगण को संगठित होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रयासरत होना चाहिये। संगठन प्रारूप का आधार प्रबन्धकीय अधिकार अन्तरण का सिद्धान्त होना चाहिये। लोक उद्यमों की स्थापना के लिये ऐसे संगठन प्रारूप को चुना जाना चाहिये जिससे अधिकार अन्तरण तथा प्रबन्धकीय स्वायत्तता को बनाये रखा जा सके। सूत्रधारी कम्पनी प्रारूप का अधिकाधिक प्रयोग कर सम्बन्धित सहायक कम्पनियों एवं संयंत्रों को

कदम उठाया जा सके। बिजली की समस्या के समाधान के लिये जहाँ पर बिजली की अधिक मांग उसके नजदीक विद्युत स्टेशन में किसी भी प्रकार के रुकावट न उत्पन्न हो। लोक उद्यमों के सफलता का मूल मंत्र उत्पादन ही त है। जनता के मांग के अनुसार उत्पादन होना परमावश्यक है। उत्पादन सम्बन्ध समस्त समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करना समीचीन है।

5. मानव शक्ति लोक उद्यमों का इजन है, इसके अभाव में कोई भी कार्य असम्भव है। लोक उद्यम के लिये यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अस्त्र है। प्रबन्धन से लेकर उत्पादन तक का कार्य मनुष्य ही कर सकता है। कार्मिकों की समुचित व्यवस्था तथा उपलब्धता सदैव बनी रहनी चाहिये, जिससे उत्पादन कार्य तथा प्रबन्धन में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की उद्यमों के विस्तारण में अथवा लोक उद्यमों में नियुक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिये। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे कर्मचारियों की कार्मिक नीतियों, उत्पादकता में वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकेगा। श्रमिक अनुशासनहीनता के मामले में श्रम संघ के नेतृत्व को सरकार द्वारा अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि सरकार द्वारा उनको यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि उद्यम, जनता तथा उपभोक्ताओं का हित कर्मचारियों से ऊपर है। मानव शक्ति नियोजन के लिए एक विस्तृत ढाँचा तैयार किया जाना चाहिये। इसके अन्तर्गत कार्य की प्रकृति, स्तर तथा सीमा के अनुसार कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाकर उपयुक्त समय के अन्दर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिये। कार्मिक प्रबन्ध के

सम्बन्ध में प्रबन्ध तन्त्र को पर्याप्त स्वायत्तता मिलनी चाहिये। इन मामलों में सरकार को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

6. कार्मिक प्रबन्ध के क्षेत्र में भी व्यावसायीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इससे कर्मचारियों को अभिप्रेरित एवं उनके मनोबल को बढ़ाने में सफलता सुनिश्चित की जा सकेगी औद्योगिक संघर्ष का राजनीतिकरण एवं उनका सरकारी स्तर पर सन्दर्भित किये जाने की प्रवृत्ति को कम किया जाना चाहिये।

7 अधिकतर उद्योग वित्त के अभाव में ही रूग्ण हो गयी है। अधिकांश रूग्ण इकाइयां वित्तीय संस्थाओं एवं बैंक द्वारा प्राप्त करने वाली इकाइया हैं। इनको आवश्यक पूरी पूँजी एक साथ उपलब्ध नहीं की जाती तथा पूँजी की मात्रा भी कम रहती है। अतः पूर्ण वित्त के अभाव में सक्षम उत्पादन न कर पाने के कारण रूग्ण हो जाती है। वित्त प्राप्त करने के लिए लम्बे प्रावधान हैं इन प्रावधानों में अधिक समय लगता है और इकाइयां रूग्ण हो जाती हैं। अतः वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण पर्याप्त मात्रा में तथा कम समय में ही उपलब्ध कराये जाय तथा वित्त प्राप्त करने वाले प्रावधानों को सरल एवं ग्राह्य योग्य बनाया जाय। ताकि अन्य इकाइयां जो इस समय वित्त की सहायता से कार्यरत हैं तथा भविष्य में स्थापित होने वाली हैं वित्त के अभाव एवं अपर्याप्तता से रूग्ण न होने पायें। रूग्णता की स्थिति में पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत भी एक महीने के निर्धारित समय से कई महीने या

वर्ष लग जाते हैं। बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा एक कार्यदल का गठन किया जाय जो समय-समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करें तथा आवश्यक सुझाव दें जिससे इकाइयों रूग्ण न होने पायें। बी० पी० सी० एल० व टी० एस० एल० को रूग्णता से मुक्ति दिलाने के लिए इन इकाइयों में सरकार को पर्याप्त मात्रा में वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

8. ऊर्जा या शक्ति की अनियमितता एवं कमी उद्योगों की रूग्णता की श्रेणी में खड़ी करती चली जा रही है। यदि शक्ति/विद्युत का उचित उपचार नहीं किया गया तो रूग्णता की स्थिति को और अधिक जटिल बना देगी। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में और इकाइयाँ रूग्ण हो जायेगी। उद्योगों को रूग्णता से बचाने के लिए विद्युत केन्द्र खोले जायें ऊर्जा की कमी से रूग्ण होने वाली इकाइयों को तुरन्त ऊर्जा या जनरेटर की व्यवस्था की जाये। लोक उद्योगों को जनरेटर खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी दी जाती है लेकिन इससे उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है। जिसके फलस्वरूप रूग्णता भी बढ़ सकती है। लोक उद्योगों को जनरेटर सेट किस्त प्रणाली पर दिया जाए तथा किस्त की रकम न्यूनतम हो जिससे उद्योगों को अदा करने में कोई कठिनाई न हो दूसरी तरफ विद्युत विभाग को अपने कार्यों में सुधार की आवश्यकता है। सड़क और गलियों में बिजली दिन भर जलती रहती है। उसको दिन में बुझाने की व्यवस्था हो, इससे भी कुछ ऊर्जा बचेगी जो उद्योगों में काम आ सकती है। इसके साथ विद्युत चोरी को रोका जाय इससे भी ऊर्जा की बचत होगी। जिससे उद्योगों की रूग्णता को कम किया जा सकता है और

भविष्य में विद्युत से होने वाली रूग्णता को रोका जा सकता है सरकार द्वारा औद्योगिक आस्थानों में अलग विद्युत उत्पादन केन्द्र खोला जाय अथवा सौर ऊर्जा स्थापित किया जाय इसके अतिरिक्त उद्योग भी व्यर्थ शक्ति बरबाद न करे विद्युत की बचत से विद्युत का उत्पादन होगा जो उद्योगों के काम में आयेगी। अतः इस प्रकार उद्योगों को रूग्णता से बचाया जा सकता है और भविष्य में विद्युत की कमी से होने वाली रूग्णता से बचा जा सकता है।

9 मांग के अभाव में इकाइया रूग्ण हो जा रही है। अत रूग्णता न होने देने के लिए लोक उद्योगों द्वारा उत्पादित मालों की माँग बढ़ायी जानी चाहिये। इसके लिए निदेशालय द्वारा एक विक्रय सस्थान खोला जाना चाहिए जहाँ ऐसी इकाइयों द्वारा उत्पादित मालों का विक्रय हो। इसके अतिरिक्त उद्योगों का अपनी वृद्धि बढ़ाने के लिए उत्पादों के साथ मुक्त उपहार योजना को आरम्भ करना चाहिए इससे उसके मालों की माँग में वृद्धि होगी। उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिये उचित किस्म तथा कम मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेलों, प्रदर्शनियों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उद्यमी अपने उत्पादों को सामने ला सकें और बिक्री में वृद्धि हो सकें। इस प्रकार जो इकाइयाँ रूग्ण हो रही हैं या रूग्ण होने वाली हैं उनको बचाया जा सकता है।

उत्पादन कम रहने के कारण होने वाली रूग्णता को अधिक क्षमता द्वारा कम किया जा सकता है तथा भविष्य में रोका जा सकता है। कभी-कभी उत्पादन क्षमता में कमी संयंत्रों के पुराने हो जाने के कारण होती है। उत्पादन

क्षमता बढ़ाने के लिये उद्यमियों को अपने सयंत्रों का उचित रख-रखाव करना चाहिए तथा समय-समय पर जाँच पड़ताल करानी चाहिए। प्रायः देखा गया है कि उद्यमी सयंत्रों का उचित रख-रखाव नहीं करते उन्हें चाहिए कि उन पर ध्यान दे तथा समय-समय पर जाँच पड़ताल करें, उपकरणों की क्रियाशीलता तथा उत्पादन की अबाध सम्पन्नता, सुनियोजित कारखाना अनुरक्षण पर भी निर्भर करता है इससे श्रेष्ठ कार्यक्षमता एवं कम लागत आती है। यदि उत्पादन में कमी सयंत्रों के कारण हो रही है तो अविलम्ब उसकी पूर्ति करना चाहिए। जिला निदेशालय द्वारा उत्पादन बढ़ाने के तरीकों को ऐसे उद्योगों में एक दल समय-समय पर भेजकर उद्योगों की समस्याओं आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहिए तथा उन समस्याओं का निदान करने तथा उनके उत्पादन बढ़ाने के तरीकों की समीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार वर्तमान में उद्योगों की रूग्णता को दूर किया जा सकता है।

10 गुण नियंत्रण के अभाव के कारण रूग्ण उद्योगों को बचाने के लिये जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित गुण चिन्हांकन योजना के द्वारा तुरन्त लाभान्वित किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी लोक उद्योगों को चिन्हांकन योजना के तहत लाया जाय या उनके लिये अनिवार्य बनाया जाये।

आवश्यकता इस बात की है कि जनपद में एक ही केन्द्र पर सभी प्रकार की वस्तुओं का चिन्हांकन किया जाय इसके अतिरिक्त निश्चित समय पर उनका पुनः निर्धारण किया जाए और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया



जाय। उद्यमियों को भी चाहिए कि अपनी वस्तुओं की फिरम उच्छी रखे ताभी उनकी वस्तुएँ बार-बार बिकेगी तथा अधिक मात्रा में बिक पायेगी। इस प्रकार उच्च गुण नियन्त्रण बनाये रखकर वर्तमान तथा भविष्य के उद्योगों के रूग्णता से बचाया जा सकता है। बी० पी० सी० एल० व टी० एस० एल० अपने उत्पादों के गुण पर नियन्त्रण रखने में निरन्तर असफल हो रहे हैं जिससे ये अपनी उत्पाद की पूर्ण बिक्री करने में भी असफल हो जाते हैं। पूर्ण बिक्री न होने की दशा में यह उद्यम लगातार हानि अर्जन करना प्रारम्भ कर देते हैं।

11 यदि उद्योगों के प्रबन्धक के पास प्रबन्धकीय निर्देशन, नियन्त्रण, वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कार्यक्षमता नहीं है तो उसका उपयोग नहीं कर पाते और इकाई रूग्ण होती चली जाती है। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक वर्तमान तथा भविष्य में संचालित तरह-तरह की सुविधाओं आधुनिक तकनीकों आदि की जानकारी न रखने के कारण उसका लाभ उठा नहीं पाते फलस्वरूप उद्योग रूग्णता के कगार पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार की रूग्णता की रोकथाम के लिए वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा केवल उन्हीं उद्यमियों को ऋण दिया जाय जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रबन्धकीय योग्यता प्राप्त किया हो। उद्यमी प्रबन्धकीय क्षमता की उचित प्रयोग कर अपने उद्योगों में रूग्णता को आने नहीं देती है। जिला उद्योग निदेशालय द्वारा भी उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि उद्यमियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो और निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाय। विद्यमान तथा भविष्य में इस कारण से होने रूग्णता के निदान के लिए

प्रशिक्षण व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाय तथा समय-समय पर गोष्ठियो, कार्यशालाओ आदि का आयोजन किया जाय और उसमे उद्यमी को इस सम्बन्ध मे जानकारी दी जाए इस प्रकार वर्तमान मे तथा भविष्य मे इस कारण से होने वाली रूग्णता को काफी सीमा तक हल किया जा सकता है।

12. समाज में अक्सर ऐसी घटनाएँ घटती रहती है जिससे उद्योगो को भारी क्षति पहुँचती है। इस असम्भावितता को टाला नही जा सकता है। इस प्रकार से होने वाली रूग्णता से बचाव के लिए उद्योग निदेशालय या अन्य ऐसी किसी सस्था का निर्माण करे जो लोक उद्योगो का बीमा करार्ये इस योजना मे प्रीमियम की राशि न्यूनतम रखी जाए। इस प्रकार सामाजिक कारणो से भविष्य मे होने वाली रूग्णता को दूर किया जा सकता है।

13. उद्योगो की रूग्णता का मनोवैज्ञानिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक कारण ही सभी प्रकार की रूग्णता का आधार है इस प्रकार की रूग्णता से बचाने के लिए उद्यमियो को अपने आप को नम्र या विनम्र बनाये रखना चाहिए। प्रबन्धकों को दूसरो तथा श्रमिको के मनोबल कार्यप्रेरणा एव सहयोग की भावना को प्रेरित करती है। प्रबन्धकों को श्रमिको के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहिए यदि श्रमिको के साथ अच्छे सम्बन्ध है तो श्रमिको का मनोबल बढ़ेगा और वे उन्हे सहयोग प्रदान कर उद्यम की कार्य कुशलता से वृद्धि करेंगे प्रायः देखा जाता है कि प्रबन्धक अपने को बहुत उच्च समझने लगते हैं और श्रमिकों को निम्न दृष्टि से देखते हैं। इससे श्रमिकों का मनोबल गिर

जाता है। श्रमिकों को जीवन निर्वाह हेतु उचित पारिश्रमिक सामाजिक सुविधाएँ, उचित वातावरण, अवकाश आदि की सुविधाएँ देकर इस प्रकार की रूग्णता से बच सकते हैं।

14 लोक उद्यमों के दिन-प्रतिदिन मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए नीति निरूपण तथा लक्ष्य निर्धारण में ही सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। स्वायत्तता तथा हिसाबदेयता में उपयुक्त सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार के लिये यह उपयुक्त होगा कि वह आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग तथा अर्जुनसेन गुप्त समिति के सुझावों को सही दिशा में क्रियान्वित करे।

प्रेस को भी लोक उद्यमों से सम्बन्धित सूचनाओं को प्रयुक्त करने में विवेकपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिये कि तथ्यों का पक्षपात रहित होकर प्रस्तुत करना ही उनका कर्तव्य है।

संसद सदस्यों को भी अपने प्रश्नों को केवल नीति विषयक एवं बड़ी समस्याओं तक ही सीमित रखना चाहिए अनावश्यक प्रश्न व महत्वहीन प्रश्नों के पूछने से वे संसद तथा लोक उद्यम दोनों के अमूल्य समय को बरबाद करते हैं।

## संग्रहिका

क्र०सं०	लेखक	पुस्तक एवं प्रकाशक का नाम
1	हैन्सन ए० एच०	पब्लिक इण्टरप्राइज एण्ड एकोनोमिक डेवलपमेण्ट, लन्दन राउटलेज एण्ड कीगन पाल लिमिटेड, 1972
2	खेरा एस० एस०	गोवर्नमेन्ट इन बिजनेस, नेशनल पब्लिशिंग हाउस न्यू देलही, 1977
3	दत्ता आर० सी०	भारत में लोक उद्यम, भारतीय प्रबन्ध संस्थान कलकत्ता, 1988
4	प्रकाश ओम	द थ्योरी एण्ड वर्किंग ऑफ स्टेट कारपोरेशन्स विथ स्पेशल रिफरेन्स टू इण्डिया, 1962
5	गुप्ता एन० एस०	इण्डस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इण्डिया ड्यूरिंग मेडिवल पीरियेड, 1970
6	प्रकाश जगदीश व शुक्ल माता बदल	भारत में लोक उद्यम, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद, 1998
7	प्रकाश जगदीश, मुखर्जी ए० के० व अन्शुमान खरे	इण्डस्ट्रियल सिकनेस एण्ड रीवाइवल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 1996
8	एन० जी० दास	द पब्लिक सेक्टर इन इण्डिया एशिया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे, 1961
9.	सिंह अरूणेश	भारतीय अर्थव्यवस्था अभिव्यक्ति प्रकाशन, 1999
10.	भगवती जे० एन०	अल्प विकसित देशों का अर्थशास्त्र, युनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लन्दन, 1966

## सर्वेक्षणात्मक पुस्तकें

1. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 99-2000, 2000-2001 व 2001-2002
2. भारत सरकार सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 98-99, 99-2000, 2000-2001
3. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 2000-2001
4. भारत यन्त्र निगम के वित्तीय संकेतांक
5. विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन, भारत यंत्र निगम
6. योजना जुलाई 2000
7. टाटा आउट लाइन ऑफ इण्डिया, 2000-2001
8. लोक उद्यम सर्वेक्षण 1997-2002